बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 211

जीएसटी में अगला कदम

कोविड-19 महामारी की वजह से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में देरी हुई। अप्रत्यक्ष कर सुधार 2017 में लागू किया गया था और उस समय यह वादा किया गया था कि राज्य सरकारों को पहले पांच साल के दौरान होने वाली राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। राज्यों को मुआवजा देने के वास्ते फंड जुटाने के लिए जीएसटी की उच्चतम दरों वाले स्तर पर एक मुआवजा उपकर लगाया गया। सामान्य परिस्थितियों में मुआवजा उपकर 2022 में समाप्त हो जाना था। बहरहाल महामारी के दौरान कर संग्रह पर बुरा असर हुआ और यह निर्णय लिया गया कि राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए उधारी ली जाएगी और उपकर संग्रह की अवधि बढ़ाई जाएगी ताकि इसके लिए जुटाए गए कर्ज तथा उसके ब्याज को चुकता किया जा सके। ऐसे में महामारी के दौरान लिए गए 2.7 लाख करोड़ रुपये की राशि को चुकता करने के लिए उपकर लिया जा रहा है। अनुमान के मुताबिक जनवरी 2026 तक इसे चुकाने का काम पूरा हो जाएगा। ऐसे में यह महत्त्वपूर्ण है कि भविष्य की दिशा तय की जाए और समय पर जरूरी कानूनी बदलाव पूरे कर लिए जाएं।

मंत्रियों का एक समूह बनाया गया ताकि वह भविष्य की राह सुझा सके। जैसा कि इस समाचार पत्र ने गत सप्ताह लिखा, राज्य सरकारों ने मुआवजा उपकर को जीएसटी दर में समाहित करने का सुझाव रखा है। राजस्व वाले नजरिये से देखा जाए तो उपकर को उच्चतम जीएसटी दर में समाहित करने से राजस्व संग्रह और करदाताओं पर बोझ दोनों बरकरार रहेंगे। फिलहाल उपकर के रूप में संग्रहीत राजस्व का इस्तेमाल कर्ज को चुकाने के लिए किया जा रहा है। विलय के बाद इसे सामान्य जीएसटी संग्रह के रूप में केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जा सकता है। उपकर से हासिल होने वाला संग्रह 2023-24 में 1,44,554 करोड़ रुपये था।

हालांकि हालात इतने भी आसान नहीं रहने वाले हैं और मंत्री परिषद जिसे 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है उसे कई संभावित परिणामों पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए उपकर सीमित समय के लिए लगाया गया था और फिर असाधारण परिस्थितियों में उसमें इजाफा किया गया। ऐसे में क्या उसे स्थायी रूप से कुछ चीजों पर लगने वाली उच्च कर दर में मिला देना उचित होगा? इतना ही नहीं विभिन्न वस्तुओं पर उपकर का स्तर भी अलग है। उपकर को आधार दर में शामिल करने से जीएसटी प्रणाली में स्लैब बढ़ सकते हैं। अब यह स्वीकार्य है कि दरों की बहुलता से कारोबार और कर अधिकारियों दोनों के लिए जटिलता उत्पन्न होती है और स्लैब की तादाद कम करने की आवश्यकता है। एक अन्य मंत्री परिषद दरों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रही है। गत सप्ताह बैठक में इस मंत्री परिषद ने यह अनुशंसा की थी कि पैकेटबंद पानी, साइकिल, कलाई घड़ी और जूतों जैसी वस्तुओं पर जीएसटी कर दर में बदलाव किया जाए। मंत्री परिषद को मार्जिन में छेड़छाड़ से आगे बढ़कर ढांचागत बदलाव के तरीकों पर विचार करना चाहिए। यह महत्त्वपूर्ण होगा कि मंत्री परिषद समन्वय करें और अपनी अनुशंसाओं को जीएसटी परिषद के निर्णयों के साथ सुसंगत बनाएं।

परिषद का लक्ष्य यह होना चाहिए कि स्लैब को अधिक से अधिक तीन तक सीमित किया जाए। कुछ जरूरी वस्तुओं के लिए कम कर दर और विलासिता वाली या नुकसानदेह वस्तुओं के लिए अधिक दर होनी चाहिए। अन्य सभी वस्तुओं को बीच की एक दर में शामिल किया जा सकता है जिसमें अपवाद की गुंजाइश सीमित हो। उपकर को भी उच्चतम दर में शामिल किया जाए लेकिन केवल सीमित वस्तुओं पर। कुल मिलाकर जीएसटी ढांचे को राजस्व निरपेक्ष स्तर पर ले जाने का प्रयास होना चाहिए। वर्ष 2023-24 में उपकर सहित कुल संग्रह सकल घरेलू उत्पाद के लगभग उतने ही हिस्से के बराबर था जितना जीएसटी के पहले जुटाया जाता था। बिना उपकर के संग्रह में कमी आएगी। ऐसे में जरूरत यह है कि जीएसटी प्रणाली में सुधार किया जाए और उसे सहज बनाकर राजस्व संग्रह बढ़ाने की दिशा में बढ़ा जाए।

बिनय सिन्हा

विदेशों में बसे सिख उपद्रवियों से परेशान न हो भारत

सिख अलगाववादी उपद्रव कर रहे हैं तो उनके मेजबान देशों को चिंता करने की जरूरत है। अगर उनके गिरोह आपसी लड़ाई में पास-पड़ोस को असुरक्षित बनाते रहें तो क्या भारत के लिए चिंतित होने की बात है?

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

बड़े और पुराने खतरे दोबारा सिर उठा रहे हैं और पीढ़ियों से दफन प्रेत फिर उठ रहे हैं तो सेना को हटाना या कम करना कैसे सही ठहराया जा सकता है? हम पंजाब और सिखों की बात कर रहे हैं।

आप पूछ सकते हैं कि जंग के हालात आखिर कहां हैं? पंजाब खामोश है और शायद उत्तर भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक शांत है और कानून सम्मत ढंग से काम कर रहा है। कम से कम वहां हिंदी प्रदेशों से तो बेहतर ही हालात हैं। सिखों ने लोक सभा और राज्य विधान सभा के चुनावों में जमकर मतदान किया और ताकतवर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को खारिज कर दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना जो कांग्रेस या भाजपा से भी अधिक बाहरी है। फिर दिक्कत कहां है? चुनौती कहां है? हम किन गंभीर खतरों की बात कर रहे हैं? क्या हलचल मची है और जंग कहां है?

सत्ता में होने या पूरी तरह नियंत्रण रखने पर बड़ी चुनौती यह होती है कि लोगों को लगने लगता है कि उन्हें कुछ करना चाहिए। हर सत्ता तंत्र के भीतर एक डॉन कुहाते (मिगुएल दी सवर्ति का उपन्यास नायक जिसे हिंदी में तीसमार खां कहा जाता है) होता है, जो अपने साथी सांचो पांजा के साथ मिलकर भौमकाय और दुष्ट पवनचक्की से निपटने निकल पड़ता है। मगर उपन्यास में यह सब 1605 में होता है और अब 1605 नहीं है। मामला तब ज्यादा पेचीदा हो जाता है, जब पवनचक्की ब्रिटिश कोलंबिया में हो। तब दुष्ट दानवों से लड़ रही सेना को वापस बुलाना पड़ता है क्योंकि जिन लोगों, जमीन और राजनीति पर ध्यान देने की आवश्यकता है वे सब यहीं हैं: अमृतसर में, जो दिल्ली से कुछ ही घंटों की दूरी पर है। वहां कोई जंग या झड़प नहीं हो रही है। वहां की आबादी नाखुश और हताश है, वह भारत छोड़ना चाहती है जो अब लगभग असंभव हो गया है।

अलगाववादी जो बयान देते हैं, उनकी परेड में जो अपमानजनक झांकियां निकाली जाती हैं या जो नारे, पोस्टर और असॉल्ट राइफल के साथ सेल्फी होती हैं, वे भी भारत की समस्या नहीं हैं। वैसे मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि हरदीप सिंह निज्जर बनाना रिपब्लिक वाली भगवा टी-शर्ट पहनकर क्या जताना चाह रहा है? इन सब में ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार लोग शामिल हैं। अगर वे परेशानी का सबब हैं तो जहां रहते हैं, उन देशों के लिए हैं क्योंकि वे हथियारबंद हैं और उनकी अंडरवर्ल्ड की अपनी दुनिया है। महत्त्वपूर्ण बात है कि यह सब अमेरिका में नहीं केवल कनाडा में हो रहा है।

गुरपतवंत सिंह पन्नून भारत की आंखों में सबसे ज्यादा खटकता है मगर वह सोच-समझकर बोलता है। बात करते समय वह वकालत की अपनी पढ़ाई का बढ़िया इस्तेमाल करता है। उसके होर्डिंग पर लिखा होता है, 'भारत को खत्म कर दो!' या 'भारत को कुचल डालो!' किंतु नीचे बारीक अक्षरों में लिखा हो, 'गोली से नहीं वोट से।' कनाडा में हालात अधिक बुरे हैं बिल्कुल ब्रिटेन की तरह। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दूसरे देशों में गड़बड़ कुछ कम है।

यह सब देखकर गुस्सा आ सकता है मगर क्या वे सब वाकई इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि हम अहम राजनियक संबंधों को ताक पर रखकर उनसे उलझें, वह भी तब जब हमारा पड़ोसी ऐसा है? खासकर उत्तरी पड़ोसी ऐसा है? एक समझदार महाशक्ति के पास अपनी दोस्ती और खतरों को आंकने तथा कोई भी कदम उठाने का सही समय भांपने की क्षमता होनी चाहिए। किसी भी समय जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा हो, सबसे पहले उसी पर प्रतिक्रिया देना निरी मानवीय प्रकृति है। फिर भी राष्ट्रों, समाजों तथा निजी एवं व्यावसायिक जीवन के अनुभव हमें बताते हैं कि गहरी सांस ली जाए और गुस्से को शांत होने दिया जाए तो अगली सुबह हम खुद से ही पूछते हैं: क्या इतनी सी बात के लिए मैं जंग करने जा रहा था? या रिश्ता तोड़ने जा रहा था? नौकरी छोड़ने जा रहा था? किसी को नौकरी से निकालने जा रहा था? ताकतवर लोग और राष्ट्र गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देते और गुस्से को कोई काम नहीं करते। शोरशराबा करने वाले इन अलगाववादियों में से कोई नहीं मानता कि कोई चमत्कार होगा और संप्रभु सिख देश बन जाएगा। इनमें से अधिकतर तो पंजाब में पंचायत चुनाव जीतने या 100 हथियारबंद लोगों को अपने साथ जुटा लेने की ताकत भी नहीं रखते। उन्हें ऐसे लोग भी माना जा सकता है, जो कभी हमारी तरह भारतीय थे मगर अब उनमें से ज्यादातर कनाडाई हो गए हैं और पाकिस्तानियों से उनका बचा-खुचा पैसा खर्च करा रहे हैं। वे उसी पैसे पर जी रहे हैं। भारत और उसका मजबूत खुफिया तंत्र भी पाकिस्तान को इसी तरह जवाब दे सकता है और देता रहा है।

भारत, अमेरिका और यहां तक कि कनाडा भी देखेंगे कि समय के साथ उनके विवाद खत्म हो जाएंगे चाहे उनके तरीके अलग-अलग क्यों न हों। संप्रभु देशों खासकर जिनके बीच बहुत कुछ साझा हो, के रिश्ते अधिक समय तक टूटे नहीं रहते। अमेरिका और भारत पहले ही पन्नून मामले को अलग रखकर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन यह तथ्य नहीं बदलेगा कि सिख प्रवासियों की बड़ी और प्रभावशाली आबादी दोनों देशों में रहती है। कनाडा में कई सीटों पर चुनाव के लिहाज से उनका बहुत महत्त्व है। यह तथ्य भी नहीं बदलेगा कि दोनों जगह इस कट्टर तबके को आईएसआई से रकम मिलती रहेगी।

इसी पखवाड़े में इंदिरा गांधी की 40वीं बरसी होगी और उनकी शहादत के साथ ही सिखों के नरसंहार को भी 40 साल पूरे हो जाएंगे। यह ऑपरेशन ब्लू स्टार की भी 40वीं बरसी है। भिंडरावाले के रहते हुए पंजाब में जो अशांति थी, उससे कहीं ज्यादा खूनखराबा उसने भिंडरावाले के बाद के एक दशक में देखा और तब जाकर वहां शांति कायम हुई। उसके बाद से तीन दशक तक पंजाब में पूरी तरह शांति रही है। मगर अब गुस्सा और हताशा पनप रहे हैं। इसकी मूल वजह पंजाब की कमजोर होती आर्थिक स्थिति है। वहां यह धारणा भी गहराती जा रहती है कि राष्ट्रीय राजनीति और सत्ता में पंजाब का पुराना कद घट गया है। मेरा यह कहना अजीब लग सकता है क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक सिख ने भारतीय वायु सेना की कमान संभाली है। लेकिन केंद्र की सत्ता अब पूरी तरह भाजपा के हाथ में है, जिसे सिख सबसे कम पसंद करते हैं। पंजाब में भाजपा के पास सिख नेता नहीं है और शिरोमणि अकाली दल ने 2020 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का साथ छोड़ दिया था।

अकाली दल के साथ रिश्ते खत्म करने की राजनीतिक वजह जो भी रही हो, यह कदम देश के हित में नहीं रहा। अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहते थे कि पंजाब में चुनौती है सिख और हिंदू विभाजन। इसका सही जवाब था सिखों और हिंदुओं के दलों यानी अकाली और भाजपा में गठबंधन। इस गठजोड़ के टूटते ही सब बिखर गया। अकाली अब वहां लोकप्रिय नहीं हैं और कट्टरपंथी उनके धार्मिक क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। इसे पंजाब में 'पंथिक' कहा जाता है और पंथिक राजनीति में निर्वात खतरे की बात है। और धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात तो न ही करें। पंजाब में अगर कोई कहता है कि भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है तो सिख राष्ट्र की मांग पर सवाल कैसे उठाया जाएगा? वैसे यह केवल कहने की बात है। अमृतपाल सिंह लोकतांत्रिक राजनीति में आ गए हैं और उनको बंदी बनाए जाने पर ज्यादा शोरगुल नहीं हुआ।

कठिन प्रश्न यह है कि सिख पंथ, उसके बड़े गुरुद्वारों, संसाधनों और संस्थाओं पर किसका नियंत्रण है? यह काम निर्वाचित संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है, जिसके लिए केवल धर्मपालक सिख ही मतदान कर सकते हैं। आखिरी बार इसका चुनाव चुनाव 2011 में हुआ था और चुनाव के लिए पंजीकरण की अभी जारी प्रक्रिया में पात्र सिख मतदाताओं की संख्या आधी हो गई है क्योंकि धार्मिक सिख घटते जा रहे हैं।

इससे असुरक्षा और चिंता बढ़ी है। केंद्र की शंका ने हालात और बिगाड़े हैं। 40वीं बरसी पर कुछ नारे और पोस्टर दिख सकते हैं लेकिन कोई बगावत नहीं होने वाली है। क्या आप उन सभी को यूएपीए और रासुका के तहत बंद कर देंगे? अगर नहीं तो समुद्र के पार बैठे कुछ सौ लोगों के साथ जंग क्यों छेड़ी जाए? यही वजह है कि हमें अपने जवान बैरक में वापस बुलाने चाहिए।

टाटा: कारोबार में असहज विचारों को सम्मान

जमीनी हकीकत
सुनीता नारायण

दिवंगत रतन टाटा के साथ हमारा पहला संपर्क सुखद नहीं था। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कारण दम घुटने जैसी स्थिति बन गई थी और हमने स्वच्छ हवा के अधिकार का अभियान शुरू कर दिया था। डीजल को हवा में घुलने वाले सूक्ष्म कण पीएम 2.5 के उत्सर्जन का जिम्मेदार बताया जा रहा था। 1990 के दशक के मध्य में यह सब कुछ नया था क्योंकि विज्ञान पता लगा रहा था कि ईंधन और वाहन की गुणवत्ता सुधरने से प्रदूषण फैलाने वाले उन सूक्ष्म कणों का प्रसार अप्रत्याशित रूप से कैसे बढ़ेगा, जो हमारे फेफड़ों की गहराई में जमा हो सकते हैं। इसी वजह से मैंने और मेरे दिवंगत सहयोगी अनिल अग्रवाल ने डीजल के खतरों के बारे में लिखा था। तुरंत ही हमें टाटा मोटर्स की तरफ से मानहानि का नोटिस मिल गया, जिसमें बतौर मुआवजा कुछ रकम भी मांगी गई थी।

यह तब की बात है जब रतन टाटा ने कार बनाने का अपना कारोबार शुरू ही किया था। उनकी कंपनी ईंधन के नए विकल्प डीजल पर दांव लगा रही थी, जिससे उसे पेट्रोल से चलने वाली कार बना रही मारुति सुजूकी और दूसरी कंपनियों पर बढ़त हासिल हो सकती थी। बहरहाल न तो हम पीछे हटने वाले थे और न ही वह। यह मामला उच्चतम न्यायालय में गया और मुकदमा लंबा चला। मुकदमा खिंचा तो मुझे महसूस हुआ कि रतन टाटा वास्तव में यह मानकर मुकदमा लड़ रहे थे कि उनका मुकाबला कर रही पेट्रोल कार कंपनियों के कहने पर ही हम यह मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन जब साबित हो गया कि हमारा अभियान पीएम 2.5 के बारे में नई वैज्ञानिक खोजों और बतौर वाहन ईंधन डीजल के सेहत पर होने वाले असर के कारण था तब माहौल बदल गया।

ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स डीजल कार की अपनी महत्त्वाकांक्षी परियोजना से पीछे हट गई। ऐसा भी नहीं है कि हमने डीजल वाहनों के खिलाफ अपनी लड़ाई छोड़ दी। असल में हमने विपरीत विचारों को स्वीकार करने की पुरानी और भली लोकतांत्रिक परंपरा निभाई। दिल्ली में ऑटो एक्सपो के दौरान जब रतन टाटा ने नैनो कार की अपनी दुलारी परियोजना शुरू की तो उन्होंने मेरा नाम लेते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस किफायती कार पर मुझे कोई एतराज नहीं होगा। कितनी अद्भुत और विनम्रता भरी बात थी।

मेरा दूसरा अनुभव और भी व्यक्तिगत मगर उतना ही भावुक करने वाला है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब मैं एक भोज में शरीक हुई, जहां धनी और ताकतवर लोगों का जमावड़ा था। वहां रतन टाटा लोगों को समझा रहे थे कि कैसे उनकी वाहन कंपनी देश की आबादी के हरेक तबके के लिए कार बना रही है। उन्हीं दिनों उन्होंने ब्रिटेन का मशहूर जगुआर ब्रांड खरीदा था, जो संपन्न तबके के लिए कार बनाता था और उसी समय उन्होंने पहली बार कार खरीदने जा रहे लोगों के लिए नैनो भी पेश की थी।

मैंने उन्हें बीच में रोककर कहा कि वह कुछ भूल रहे हैं। मैंने उनकी आंखों में चिंता नजर आई क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे भीतर बैठी एक्टिविस्ट असहज करने वाली बात ही कहेगी। लेकिन मैंने कहा कि वह भूल रहे हैं कि टाटा मोटर्स बसें भी बनाती है और उनमें कारों के मुकाबले हजारों ज्यादा लोग आते-जाते हैं। मैंने यह भी कहा कि उनकी बसें आधुनिक (लो-फ्लोर बसें तो नहीं) हैं और स्वच्छ ईंधन (सीएनजी) से चलती हैं। सबने इस बात की तारीफ की और फिर दूसरे आम मुद्दों पर बात होने लगी। मुझे भी लगा कि बात खत्म हो गई।

लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ दिन बाद टाटा मोटर्स के एक शीर्ष अधिकारी मुझसे मिलने आए। मुझे लगा कि वह हमारे डीजल विरोधी अभियान के सिलसिले में आए होंगे। उन्होंने कहा कि वह टाटा के कार कारोबार नहीं बल्कि बस कारोबार से जुड़े हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने रतन टाटा से क्या कहा था। मैंने भी सवाल किया कि वह ऐसा क्यों पूछ रहे हैं तब उन्होंने मुझे पूरी बात समझाई। असल में भोजन के समय मैंने उनके बॉस से जो कहा था, उसके बाद उनके पास एक फोन आया। फोन पर पूछा गया कि वह कौन सा शानदार काम कर रहे हैं, जिसकी तारीफ सुनीता नारायण ने भी की। मुझे बताया गया कि उसकी वजह से उनके बॉस यानी रतन टाटा को परिवहन में हो रहे बदलाव और लोगों को लाने-ले जाने में आधुनिक बसों की भूमिका में ज्यादा दिलचस्पी हो गई।

आज इतना सब कुछ मैं यह दिखाने के लिए नहीं लिख रही हूं कि है कि ऐसी महान शख्सियत के साथ मेरी बातचीत थी। मैं बताना चाहती हूं कि उनकी महानता का कारण था दूसरों को सुनने की क्षमता और असहज होने पर भी दूसरों के विचारों को स्वीकार करने की क्षमता। मैं यह सब इसलिए भी बता रही हूं क्योंकि मैंने उद्योग की दूसरी बड़ी हस्तियों को भी देखा है। मुझे याद आता है कि हमारे काम पर सबसे आक्रामक और आपत्तिजनक प्रतिक्रिया दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आई थी। यह प्रतिक्रिया तब आई थी, जब हमने अपने अध्ययन में खुलासा किया था कि उनके उत्पादों में कीटनाशक मिले हैं। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में यह कहते हुए हमें सिरे से खारिज कर दिया कि वे गलत नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे अमेरिका की कंपनियां हैं। यह हद से ज्यादा अहंकार था। हमें दूसरी सबसे खराब प्रतिक्रिया कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों से मिली है। हमें अब भी खाद्य पदार्थ में विषैले तत्वों के खिलाफ अपने काम पर धमकी मिलती रहती है, डराया-धमकाया जाता है और मुकदमे भी होते हैं। कोई यह समझता ही नहीं कि हमारा काम निजी नहीं है बल्कि कारोबार के स्याह पक्ष से जुड़ा है और हम उसमें संतुलन चाहते हैं।

इसलिए जब हम रतन टाटा के निधन पर शोक मान रहे हैं तो हमें उस गुजरे वक्त के लिए भी शोक मनाना चाहिए, जब उनके जैसी कारोबारी हस्ती ने दुनिया पर राज किया, जब व्यक्तिगत जीवन में संयम और सादगी के मूल्यों को तवज्जो दी जाती थी और जब कारोबार का मतलब केवल मुनाफा या निजी फायदा नहीं बल्कि जनहित की रक्षा करना था।

उम्मीद है कि जब हम रतन टाटा को श्रद्धांजलि दें तो अपनी दौलत का बेशर्मी के साथ प्रदर्शन करने की आज के रसूखदार लोगों के स्वभाव की भी अस्वीकार करें। साथ ही हम यह विचार भी वापस लाने की शपथ लें कि असहमति वास्तव में मतभेद नहीं होता। हमें पता ही नहीं कि यह विचार भी हुआ करता था।

(लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवॉयरनमेंट से जुड़ी हैं)

आपका पक्ष

भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता पर प्रश्नचिह्न

लेख 'एक नई शुरुआत' में भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर सार्थक चर्चा की गई है। भारत की ओर से कई बार संबंधों को सकारात्मक आयाम देने की पहल हुई परंतु हर बार इसका प्रतिकार आतंकवादी हमलों, करगिल युद्ध और पुलवामा में हमारे सैनिकों पर घात लगा कर हमलों से हुआ और हमारी सेना ने दो बार सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया। पाकिस्तान में कोई भी सरकार हो, वहां उनकी वास्तविक सत्ता सेना के हाथ में रहती है। भारत से सीधे युद्ध करने के बजाय पाकिस्तान पिछले चार युद्धों में पराजय को दोहराने के डर से आतंकवादियों को सैन्य और लॉजिस्टिक सहायता देकर भारत के साथ छद्म युद्ध कर रहा है। भारत के साथ संबंध सुधारना पाकिस्तान की किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए संभव नहीं है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आजादी के लिए खूनी संघर्ष बहुत लंबे समय से हो रहा है। पाकिस्तान अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। इसलिए भारत के साथ पाकिस्तान की ओर से कोई सार्थक वार्ता संभव नहीं है। पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे से कश्मीर वापस लेने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान के साथ किस दायरे में हो सकती है, यह भी प्रश्नचिह्न है क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का सूत्रधार है।

विनोद जौहरी, दिल्ली

विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से एससीओ बैठक के दौरान मिले थे

भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या बड़ी समस्या

भारत की बढ़ती जनसंख्या देश के सामने कई गंभीर चुनौतियां खड़ी कर रही है। संसाधनों का अभाव बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य, पानी, ऊर्जा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इससे इन संसाधनों की कमी और उन तक पहुंच में असमानता बढ़ सकती है, बढ़ती आबादी के लिए आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करना एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना भी एक बड़ी समस्या है। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ने से सामाजिक असंतोष और अपराध बढ़ सकते हैं। वहीं प्रदूषण, वन कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती हैं और बढ़ती आबादी के कारण शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है, जिससे शहरीकरण की समस्याएं जैसे कि भीड़भाड़, यातायात जाम और स्लम क्षेत्रों का विकास हो रहा है। यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है सरकार को इसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी है।

राजूराम प्रजापत, नागौर

राजधानी में फिर बढ़ने लगा प्रदूषण

देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा है। ठंड की दस्तक के साथ ही पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी के कारण राजधानी में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है। हर साल प्रदूषण रोकने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं लेकिन हालात जस की तस ही रहती है। पड़ोसी राज्य पंजाब हरियाणा में जब तक पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगती तब तक राजधानी के लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ेगा।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस त्रिकंड और ओमान की नौसेना का युद्धपोत अल सीब रविवार को भारत-ओमान द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 'नसीम अल-बहर' में शामिल हुए।

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। सोमवार, 21 अक्टूबर 2024

तालमेल का संकट

हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद जब विपक्षी दलों के I.N.D.I.A. ब्लॉक को ज्यादा तालमेल और एकजुटता दिखाने की जरूरत थी, तब झारखंड में सीट बंटवारे के सवाल पर उसमें बिखराव दिख रहा है। आलम यह है कि गठबंधन का पुराना सहयोगी दल RJD साफ शब्दों में कह रहा है कि उसके सभी विकल्प खुले हैं।

एकतरफा घोषणा | सीटों के बंटवारे पर घोषणा से पहले न केवल कांग्रेस नेता राहुल गांधी बल्कि RJD प्रमुख तेजस्वी यादव भी रांची में थे। फिर भी, मंडियरा में सीट बंटवारे पर सहमति का एलान करते हुए RJD या लेफ्ट का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं था। एकतरफा घोषणा कर दी गई कि 81 में से 70 सीटों पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) लड़ेंगे। बाकी सीटें अन्य दलों यानी RJD और CPI-ML को दी जानी हैं। मगर किसे कितनी सीटें मिलेंगी, इसे लेकर अभी अटकलें ही चल रही हैं।

झारखंड : I.N.D.I.A. में तकरार

I.N.D.I.A. में नया ट्रेंड | कुछ ही समय पहले यूपी में दस सीटों पर हो रहे उपचुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। कांग्रेस को विश्वास में लिए बगैर दस में से छह सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी। वैसे तो राज्यों के चुनावों में पार्टियों का ऐसा रुख पहले भी दिखता रहा है, लेकिन खासकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद I.N.D.I.A. के क्षेत्रीय घटक दलों की ओर से उसे दबाव में लाने की कोशिश देखी गई। ऐसे में क्या झारखंड में JMM के साथ मिलकर दिखाया गया यह रुख उन दलों को कांग्रेस का जवाब है?

बढ़ी हुई आकांक्षा | वैसे, अगर पिछले चुनावों के आंकड़ों की कसौटी पर देखें तो सीट बंटवारे का JMM-कांग्रेस फॉर्म्युला ज्यादा अटपटा नहीं लगता। पिछले विधानसभा चुनाव में RJD ने सात सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और एक सीट पर उसे जीत मिली थी। पांच सीटों पर वह दूसरे नंबर की पार्टी थी। ऐसे में उसे छह सीटों की पेशकश एक स्तर पर तर्कसंगत ही कही जाएगी। RJD हालांकि इसे राज्य में अपने बढ़े हुए प्रभाव के आधार पर गलत करार दे रहा है।

सर्वसम्मति की राह | खास बात यह कि कोई सर्वसम्मत फॉर्म्युला न निकाले जाने पर उसने 15 से 18 सीटें ऐसी बताई हैं जिन पर उसे भरोसा है कि राष्ट्रीय जनता दल, बीजेपी को हरा भी सकता है। अगर इसे बढ़ा-चढ़ाकर दिया गया बयान मान भी लें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी इन सीटों पर I.N.D.I.A. ब्लॉक की संभावनाएं बिगाड़ सकती है। आखिर, हरियाणा में कुछ हजार वोटों के अंतर से BJP के हाथ तीसरी बार सत्ता की चाबी लगी। इसलिए अच्छा होगा कि I.N.D.I.A. ब्लॉक में आपसी तालमेल बेहतर हो।

चक्र-व्यू

सीने में जलन

राहुल पाण्डेय

हमारी ओर अव्वल तो पेड़ काटा नहीं जाता, सूख जाए तो अलग बात है। लेकिन अगर काटना ही पड़े तो काटने से पहले पूजा जाता है। कोई-कोई पंडित बुला लेता है, नहीं तो कोई घरैतिन या खुद पेड़ काटने वाला पेड़ से उसे काटने की इजाजत और माफी मांगता है। बुआ बताती थीं कि हर पेड़ में कोई न कोई ब्रह्म होता है। वह सिर ना चढ़े, इसलिए उसकी विधि-विधान से पूजा की जाती है। बुआ यह भी बताती थीं कि जब भी कोई सांप-बिच्छू दिख जाए तो उसे प्रणाम करके अपना रास्ता बदल लो। वह कुछ नहीं करेगा। इसके पीछे खुद उनकी दर्जनों कहानियां थीं, जिसमें कभी किसी कोबरा या करैत या किसी भामिन को प्रणाम करके वह अपने रास्ते हुई और सांप अपने रास्ते। हर जीव में यही आत्मा है जो हमारे अंदर है, यह दुनिया के कई आदिवासी समुदायों की मान्यता रही है और भारत में तो शायद सबसे ज्यादा। अपनी एक किताब में युवाल नोआ हरारी दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहने वाले नायक समुदाय के बारे बताते हैं। जंगल में भटकते हुए नायकों का जब किसी बाघ, हाथी या किसी और खतरनाक जानवर से सामना होता है तो वो कहते हैं कि तुम भी जंगल में रहते हो, मैं भी। तुम भी भोजन की तलाश में निकले हो और मैं भी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आश्चर्यजनक रूप से इस समुदाय में जंगली जानवरों के साथ कभी इतनी टेंशन ही नहीं हुई कि आत्मा की आत्मा से टकराहट हो।

लेकिन एक बार अकेले घूमने वाले एक हाथी ने नायक समुदाय के एक व्यक्ति को मार दिया। खबर वन विभाग वालों को मिली तो वे हाथी पकड़ने आए। नायकों ने वन विभाग की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इस हाथी ने हमारे आदमी को इसलिए मारा क्योंकि कुछ दिन पहले वन विभाग के लोग उसके साथी को पकड़ ले गए थे। वन विभाग वालों ने हाथी को पकड़ने से पहले बेहोश किया। हाथी ने अपने साथी को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा और हिंसक हो उठा। नायकों ने पूछा कि यही चीज कोई आपके साथी के साथ करे तो? नायक ही नहीं, पूर्वोत्तर की नगा, मिजो, गारो, खासी, जयंतिया, न्याशी, अंगामी, भूटिया, कुकी, रेंगमा आदिवासी तो पत्थरों में ही नहीं, प्राकृतिक घटनाओं में भी वही आत्मा मौजूद मानते हैं, जो हम सबमें है। सरनाबद तो जंगल का धर्म ही है, जिसे मुंडा, हो, संथाल, भूमिज, उरांव आदि फॉलो करते हैं। लगभग सभी धर्मों में हर चीज में ब्रह्म होने की अवधारणाएं हैं, बस एक लालच नाम के धर्म को छोड़कर। धरती पर ब्रह्म हत्या का कारोबार इसी धर्म को मानने वाले कर रहे हैं। बुआ ने बताया था कि ब्रह्म छोड़ता नहीं है। नायकों को वन विभाग की कारस्तानी भुगतनी पड़ी थी, और बाकी खुद जानें कि उनके सीने में जलन, सांसों में तूफान सा क्यों है।

एकदा

रटवाने वाली शिक्षा

राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई महेंद्र प्रसाद जब छपरा से कलकत्ता पढ़ने के लिए जाने लगे, तब हथुआ के स्कूल में उनका नाम लिखवा दिया गया। इस स्कूल में पढ़ाई का तरीका अलग था। बच्चों को पाठ कंठस्थ करने के लिए कहा जाता था और अगले दिन उन्हें सुनाने के लिए मजबूर किया जाता था। राजेंद्र प्रसाद की आदत विषय को पूरी तरह समझे बिना रटने की नहीं थी। इसलिए वह असहज महसूस करने लगे, क्योंकि कक्षा में न सुना पाने पर उनकी अवमानना होती। ऐसा नहीं था कि वह कोशिश नहीं करते थे। एक दिन तो किसी ने उनसे कहा कि विषय को यदि 120 बार पढ़ा जाए तो वह याद हो जाता है। राजेंद्र प्रसाद ने आधी रात को उठकर वैसा ही किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और अगले दिन इतिहास के अध्यापक के गुस्से का शिकार होना पड़ा। आखिरकार, वह बीमार पड़ गए। उनके भाई जब कोलकाता से आए, तो उनकी दशा देखकर दुखी हुए। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद का नाम हथुआ से कटवा कर फिर छपरा में लिखवा दिया। वहां उनके व्यक्तित्व का विकास होने लगा। रटवाने वाले इस स्कूल में अपने छह महीने के जीवन से वह बहुत दुखी थे, जिसे उन्होंने अपनी आत्मकथा में दर्ज किया है। वह छपरा के स्कूल और अध्यापकों का बखान करने से नहीं थकते। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि आज भी ऐसे अध्यापक हैं जो कक्षा में समझाने के बजाय बच्चों को रटने के लिए कहते हैं। कुछ शिक्षक तो बच्चों को एक उत्तर 15 बार लिखने के लिए कहते हैं। उन्होंने रटवाने वाली शिक्षा के बदले समझाने वाली शिक्षा की पैरवी की है।

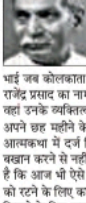

संकलन : हरिप्रसाद राय

विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख गठबंधनों, महायुति और आघाड़ी के दिग्गजों की साख दांव पर

महाराष्ट्र में होगी 'असली-नकली' की लड़ाई

गंगाधर ढोबले

महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक हलचल और तेज हो चुकी है। छोटे-मोटे कोई 16 दल मैदान में हैं। इनमें से 6 प्रमुख दल दो गठबंधनों में बंटे हैं, जबकि बाकी 10 छोटे दलों का अपना अलग गठबंधन है। इसे तीसरी आघाड़ी कहा जाता है। इसमें से 7 तो दो बड़े गठबंधनों के साथ हो गए हैं, जबकि बचे 3 ने अपना अलग कुनबा बनाया है, जिसे परिवर्तन महाशक्ति आघाड़ी नाम दिया गया है। चौथा कुनबा भी है, जिसका नाम है वंचित आघाड़ी। भीमराव आंबेडकर के पोते प्रकाश इसके नेता हैं। उन्होंने AIMIM के ओवैसी के साथ हाथ मिलाया है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, महायुति की ओर झुकती नजर आ रही है।

अस्तित्व की लड़ाई | इनमें से प्रमुख दो ही गठबंधन हैं, महायुति और महाविकास आघाड़ी। महायुति का नेतृत्व BJP के पास है, जबकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। विभाजित शिवसेना और NCP के गुट इनके घटक दल हैं। इन दलों और उनके नेताओं के लिए यह चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है। असली शिवसेना किसकी है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की या उद्धव ठाकरे की, या असली NCP अजित पवार की या शरद पवार की, यह भी साबित होना है। BJP के देवेंद्र फडणवीस और कांग्रेस के नाना पटोले के समक्ष भी अपने को साबित करने की चुनौती है। तीसरी या चौथी आघाड़ी को तो हाजिरी लगाने के लिए चुनाव लड़ना है। कुल वोटिंग में उन्हें एक से 1.5% वोट ही मिलते रहे हैं।

BJP का लक्ष्य | BJP के कोटे में लगभग 150 सीटें आ सकती हैं। पार्टी ने शत प्रतिशत जीत का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब कि इस चुनाव में अधिकाधिक सीटें जीतना और 2029 में अपने बलबूते सरकार बनाने का लक्ष्य। इससे शिवसेना का शिंदे गुट और NCP का अजित पवार गुट चौकन्ना हो गया है।

संघ का साथ | हरियाणा में BJP-संघ के विशाल नेटवर्क ने बाजी पलट दी थी। वोटर्स तक सीधी पहुंच के लिए ऐसा ही नेटवर्क महाराष्ट्र में भी तैयार है। संघ ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी अतुल लिमये को जिम्मेदारी सौंपी है।

शिंदे का फायदा | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सत्ता में होने का लाभ मिलेगा। वह लगभग 70 सीटों पर लड़ सकती है। मंत्रिमंडल की पिछली दो-तीन बैठकों में शिंदे ने जिस गति से फैसले लिए, उससे उनकी छवि चमक चुकी है। अंतिम बैठक में 10 मिनट में ही अजित पवार के उठकर चले जाने से साफ हो गया है कि उनकी कम चलती है। इस बैठक में 150 मिनट में रेवड़ियां बांटने वाले 50 से अधिक फैसलों से लोग चौक गए। लाड़की बहीण (लाडली बहना) योजना, छोटे किसानों को मुफ्त बिजली, साल में तीन मुफ्त रसोई सिलिंडर, युवकों को अप्रेंटिस सहायता, लड़कियों को छात्रवृत्ति, मुंबई के पांच टोल नाकों पर टोल छूट वगैरह ऐसी रेवड़ियां हैं, जिन पर राज्य का सालाना कोई एक लाख करोड़ रुपये खर्च होगा।

चुनावी चुनौतियां
- दोनों गठबंधन में खींचतान मची
- अजित हारे तो करियर पर संकट
- उद्धव बनना चाहते हैं सीएम फेस

अजित की मुश्किल | अजित पवार की बगावत से मतदाता खुश नहीं दिखते। संभ ने लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा अजित पवार पर फोड़ा है। महायुति में अब उनका दम घुट रहा है, लेकिन शरद पवार ने उनकी वापसी की राह बंद कर दी है। अजित पवार के लिए अपना वजूद बनाए रखने का यही एक अवसर है।

हरियाणा का सबक | लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सर्वाधिक 13 सीटें जीती थीं। लेकिन सारा जोश और आत्मविश्वास हरियाणा में हार के साथ धुल गया। पार्टी को भटक दलों के साथ अधिक तालमेल से पेश आना होगा। गुटबाजी से बचना होगा। उसे शरद पवार जैसे परिपक्व दिग्गज के साथ मिलकर दांव-पेच बनाने होंगे। सही उम्मीदवारों का चयन मुख्य मुद्दा होगा।

उद्धव की कमजोरी | शिवसेना में फूट के बाद ठाकरे सेना में आई मायूसी अब दूर हो चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में उसने शिंदे सेना से दो सीटें अधिक जीती हैं। उद्धव खुद महाविकास आघाड़ी की तरफ से सीएम पद का चेहरा बनना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और शरद पवार ने उनकी मांग ठुकरा दी है। मुंबई, ठाणे, कोंकण में उद्धव सेना का दबदबा है। वहां शिंदे सेना के साथ उनकी सीधी टक्कर हो सकती है।

पवार से आस | आघाड़ी में शरद पवार सबसे अनुभवी रणनीतिकार है। वह अपने बलबूते 60 से अधिक सीटें पा सकते हैं। लेकिन, केवल उनके बल पर महाविकास आघाड़ी सत्ता के करीब कितना पहुंच सकती है, यह सवाल है। NCP में फूट पड़ी, तब 41 विधायक अजित पवार अपने साथ ले गए। केवल 12 विधायक ही शरद पवार के साथ बचे थे। उन्होंने फिर से पार्टी संगठित की है। लोकसभा में अजित के मुकाबले उन्हें बहुत अधिक सफलता मिली। इससे अजित गुट के कई लोग अब फिर से शरद पवार के रास्ते पर हैं। उनके पुणे स्थित 'मोदीबाग' बंगले में नेताओं का आना-जाना बढ़ गया है। पाला बदलने के इच्छुक लोगों में अजित गुट, BJP और कांग्रेस के कई नेताओं के भी नाम हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

शरीर के अंदर ही छिपी है ख़ुशियों की केमिस्ट्री

AI Image

लैब में पहले दिन की शुरुआत टीचर ने यही से की, 'बिल्कुल चाय बनाने की तरह है केमिस्ट्री। जिस तरह अच्छी चाय के लिए उसमें सब चीजें बिल्कुल सही मात्रा में होनी चाहिए और यह पता होना चाहिए कि कितना उबालना है, उसी तरह का मामला केमिस्ट्री के साथ है।' इसके बाद अगले तीन साल लैब में 'अच्छी चाय' बनाने की कोशिश में ही बीत गए। खैर, केमिस्ट्री केवल लैब तक सीमित नहीं। चाय की तरह उसका भी दायरा बहुत बड़ा है। परखनली से लेकर हमारे शरीर तक, हर जगह है केमिस्ट्री। बल्कि शरीर के भीतर चल रहा रसायनों का गणित कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हमारा मूड बस हमारे हाथ में नहीं रहा, जब लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुकी है, और जब बाहरी कारण हमारी अंदरूनी सेहत पर ज्यादा असर डाल रहे हैं, तब जरूरी है कि शरीर की केमिस्ट्री को भी समझा जाए। यही सबसे अच्छा तरीका है खुशियों के नंबर बढ़ाने का।

हमारी भावनाओं को कंट्रोल करने वाले चार हॉर्मोन बेहद अहम हैं- Dopamine, Oxytocin, Serotonin और Endorphins। Dopamine को 'रिवॉर्ड बूस्टर' कहा जाता है। हमें कामयाबी की भावना का अनुभव कराता है यह। इसे बढ़ाने के लिए अपने लक्ष्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटिए। हर छोटा लक्ष्य पूरा होगा, तो संतुष्टि और खुशी मिलेगी, Dopamine बढ़ेगा। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करें और टायरोसिन से भरपूर खाना मसलन, पनीर, सोयाबीन वगैरह को डाइट का हिस्सा बनाएं। साथ ही, नींद बहुत जरूरी है इस हॉर्मोन के बैलेंस के लिए, जबकि सोशल मीडिया और जंक फूड उतने ही खराब।

जीवन आनंद

एक बहुत ही पुराना वाक्य है और लगभग हर किसी ने पढ़ाई के दौरान कभी न कभी इस पर निबंध जरूर लिखा होगा कि, 'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।' सामाजिक बनना हमें अच्छा महसूस कराता है और इसके पीछे है Oxytocin (ऑक्सिटोसिन)। इसे बॉन्डिंग हॉर्मोन भी कहा जाता है। इसे बढ़ाने के लिए अपने करीबी रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दें। अच्छा वक्त बिताएं, बातचीत करें। संवाद जितना आत्मीय होगा, उतना ही बेहतर। जादू की झप्पी बहुत काम करती है इस हॉर्मोन को बढ़ाने में।

खुशियों का अगला महत्वपूर्ण रसायन है Serotonin (सेरोटोनिन)। यह तनाव, अवसाद से बचाकर हमारे मूड को स्थिर रखता है। सोचिए, इस समय की सबसे बड़ी समस्या है डिप्रेशन, और इसकी काट Serotonin के लिए चाहिए हर दिन बस थोड़ी-सी धूप। सूरज की रोशनी में कुछ देर रहना काफी है इस हॉर्मोन का बैलेंस ठीक रखने के लिए। साथ में, रेगुलर एक्सरसाइज हो और उसमें भी एरोबिक तो फिर क्या ही बात है।

इस केमिस्ट्री का अगला चैप्टर है Endorphin (एंडोर्फिन), प्राकृतिक दर्द निवारक। इसे बढ़ाने के लिए हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT) और एंड्योरेंस स्पोर्ट्स मददगार साबित हो सकते हैं। हंसी-मजाक और पसंदीदा गतिविधियों में भाग लेने से भी Endorphin का स्तर बढ़ता है। डार्क चॉकलेट और थोड़ा मसालेदार भोजन भी अच्छा होता है।

इन चारों हॉर्मोन को कहा जाता है DOSE। ये दरअसल डोज हैं खुशियों के। अति किसी चीज की अच्छी नहीं, तो ऐसा भी नहीं है कि एक हॉर्मोन को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे की कुर्बानी दे दी जाए। जो भी करें, सकारात्मक सोच के साथ। लैब में केमिकल्स पर हाथ साधना भले ही मुश्किल है, लेकिन अगर थोड़ा-सा ध्यान दें तो जीवन की केमिस्ट्री बहुत मुश्किल नहीं।

शेयर करें अपने अनुभव

जीवन की हिलचलों के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं nbtreader@timesofindia.com पर, और सब्जेक्ट में लिखें-'जीवन आनंद'

कैसी रही है इस महान अभिनेता की ज़िंदगी

मृत्युंजय राय

यूं तो यह बात दिग्गज अमेरिकी अभिनेता ऐल पचिनो अपने इंटरव्यूज में पहले भी कह चुके हैं कि 'द गॉडफादर' में शुरुआती दौर में फिल्म के डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला उनके काम से इतने नाराज थे कि उन्हें निकालना चाहते थे। लेकिन लोग यह भी जानना चाहते हैं कि हालात ऐसे थे तो फिर वे बदले कैसे। ऐल पचिनो ने अपने संस्मरण SONNY BOY में इस वाकये से परदा हटाया है और बताया है कि असल में हुआ क्या था। वह लिखते हैं कि एक रोज एक रेस्तरां में कोपोला ने उन्हें बुलाया और कहा कि वह अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। कोपोला की नाराजगी को भूं समझ जा सकता है कि उन्होंने पचिनो को बैठने तक को नहीं कहा।

विचार विंडो

लेकिन रेस्तरां वाले वाकये के बाद फिल्म का एक सीन सूट हुआ। इस सीन में माइकल कॉर्लियोन का किरदार निभा रहे पचिनो अपने पिता (अमेरिका के महान अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले मार्लन ब्रैंडो ने यह भूमिका अदा की थी) की हत्या की कोशिश करने वाले एक शख्स की जान ले लेते हैं। इसे न सिर्फ 'द गॉडफादर' बल्कि सिनेमा के इतिहास के चुनिंदा शानदार सीन में से एक माना जाता है। इस किताब में पचिनो ने ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया है। वह लिखते हैं कि अभिनय की दुनिया ऐसी है कि कभी आप इसमें गिरते हैं तो कभी आपके सितारे बुलंदी पर होते हैं। पचिनो जैसे महान अभिनेता जब ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं तो इनसे उनकी शख्सियत का एक ऐसा पहलू सामने आता है, जिससे अक्सर फैन्स वाकिफ नहीं हैं।

'Sonny Boy' पचिनो का पुकारू नाम था, इसी वजह से किताब का भी उन्होंने यही नाम रखा है। वह जब 2 साल के थे, तभी उनके माता-पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद वह अपनी मां और नाना-नानी के साथ रहे। ऐल ने किताब में अपने बचपन के दोस्तों क्लिफ, ब्रुस और क्लिफी का जिक्र किया है। आगे चलकर उनके इन तीनों दोस्तों की मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई। पचिनो लिखते हैं कि उनके घर वाले अगर ध्यान न देते तो शायद वह भी नशे के शिकार हो जाते। हालांकि, अभिनेता के रूप में करियर शुरू होने के बाद शुरुआती दिनों में वह काफी शराब पीते थे। पचिनो ने 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बाद छिटपुट काम करके उन्होंने जीवन चलाया और थिएटर करते रहे। उन्हें बड़ी कामयाबी 70 के दशक में सिनेमा में मिली। गॉडफादर 1, गॉडफादर 2, सर्पिको, स्कारफेस और डॉग डे आफ्टरनून जैसी फिल्मों की कामयाबी ने उन्हें हॉलिवुड का बड़ा स्टार बना दिया और उनकी अभिनय क्षमता को भी सराहा गया।

किताब में वह फिल्मों में निभाए गए चरित्रों के अपने विश्लेषण के बारे में भी बताते हैं। फिर 1980 के दशक में उनकी कुछ फिल्में नाकाम हुईं। पचिनो लिखते हैं कि एक दौर ऐसा भी आया, जब उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। वह बताते हैं कि अभिनय छोड़ने से भी उन्हें गुरेज नहीं था, लेकिन तब उनकी पार्टनर डायन कीटन थीं। दोनों एक साथ रहते थे। कीटन ने उनसे कहा, 'अब तुम पीछे नहीं लौट सकते...तुम लंबे समय तक अमीरी की जिंदगी गुजार चुके हो।' खैर, पचिनो की जिंदगी में गुरबत का वक्त ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन संस्मरणात्मक लेखन में अक्सर जिस ईमानदारी की उम्मीद रहती है, उसे पचिनो पूरा नहीं कर पाए हैं। खासतौर पर उन्होंने इसमें अपनी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम लिखा है। खासतौर पर अपने अफेयर्स और रोमांटिक पार्टनर्स के बारे में। जहां उन्होंने इन लोगों का जिक्र किया है, वहां भी तफसील से उन रिश्ते के बारे में जानकारी नहीं दी है। इसके बावजूद पचिनो के फैन्स के लिए इस किताब में बहुत कुछ है।

शादी की पेनल्टी क्यों?

प्रणय प्रियदर्शी

साउथ एशियन डिवेलपमेंट से जुड़ी वर्ल्ड बैंक की एक ताजा रिपोर्ट ने इस धारणा की तथ्यों के आधार पर पुष्टि कर दी है कि भारत जैसे देशों में लड़कियां शादी करने और मां बनने की कीमत अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता की बलि देकर चुकाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में शादी के बाद फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में 12 फीसदी तक की कमी आ जाती है। ऐसी ही स्थिति उनके मां बनने पर भी होती है। रिपोर्ट में यह ट्रेंड इतने स्पष्ट तौर पर उभरता पाया गया कि इसे बाकायदा मैरिज पेनल्टी और मदरहुड पेनल्टी नाम दे दिया दिया गया है। यह स्थिति सीधे तौर पर समाज में पितृसत्तात्मकता के प्रभावों से जुड़ी है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरे दक्षिण एशिया में हालात एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पर, नेपाल में शादी करने या मां बनने के बाद लेबर फोर्सेज में लड़कियों की भागीदारी में गिरावट इतनी कम है कि जानकार इसे किसी ट्रेंड के रूप में स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। भारत समेत ज्यादातर देशों में स्थितियां एकदम उलट हैं। चाहे मैरिज पेनल्टी हो या मदरहुड पेनल्टी, सही तो दोनों में से किसी को नहीं कहा जा सकता, लेकिन समाज में आम तौर पर मदरहुड पेनल्टी को ज्यादा आपत्तिजनक नहीं माना जाता। इसके बचाव में यह दलील दी जाती है कि बच्चा चूंकि मां के शरीर से निकलता है, इसलिए कम से कम जन्म के कुछ समय बाद तक उसकी मां पर निर्भरता सबसे ज्यादा होती है। मगर मैरिज पेनल्टी के पक्ष में तो ऐसी कोई थ्योरी दलील भी नहीं। आखिर शादी के बाद किसी लड़की को पति की देखभाल में अपना पूरा समय क्यों देना चाहिए, खासकर तब, जबकि शादी से पहले पति ही पत्नी समेत अपने पूरे भावी परिवार की देखभाल करने का दावा कर रहा होता है? और बच्चे की देखभाल भी शुरुआत के कुछ हफ्तों से आगे मां की ही संपूर्ण जिम्मेदारी क्यों होनी चाहिए? क्यों नहीं इसे परिवार और समाज के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों की साझा जिम्मेदारी के रूप में विकसित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए?

AI Image

आधी दुनिया

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

इंसान की सबसे बड़ी सफलता है संतुलित जीवन

श्री श्री आनंदमूर्ति

हर व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है। लेकिन जब हम कुछ करते हैं, तो सफलता हमारे हाथों में नहीं होती। यह किसी काम के फल के रूप में आती है। जब हमारा काम सकारात्मक दिशा में होता है तो प्रतिक्रिया भी अच्छी होती है। अच्छी प्रतिक्रिया के रूप में आया वह परिणाम ही सफलता है।

एक आध्यात्मिक व्यक्ति या साधक जो समाज की सेवा करता है, उसके लिए सेवा ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बीमार व्यक्ति की देखभाल करते हैं और वह ठीक हो जाता है, तो वही आपका पुरस्कार है, वही आपकी सफलता है।

संस्कृत में सफलता के लिए तीन अलग-अलग शब्द हैं- प्रतिष्ठा, सर्वैजाशा, सिद्धि)। मनुष्य जीवन के सभी तीन क्षेत्रों में सफलता चाहता है। साधारण व्यक्ति भौतिक स्तर पर सफलता चाहता । एक विकसित, बुद्धिमान व्यक्ति मानसिक स्तर पर सफलता की तलाश करता है। एक भक्त हमेशा आध्यात्मिक स्तर पर सिद्धि चाहता है। यदि आपके पास एक ऊंचा लक्ष्य है, पर आप उस दिशा में बढ़ने की मानसिक सहनशक्ति नहीं रखते, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। उच्च विचारधारा और सहनशक्ति दोनों आवश्यक हैं।

भगवान शिव ने कहा है, 'फालिष्यति विश्वासः सिद्धिरप्रश्यलक्षणम्।' इसका अर्थ है, मुझे अपने मिशन में सफल होना है। यही सफलता का पहला रहस्य है। 'द्वितीयं श्रद्धया युक्तम्।' श्रद्धा का अर्थ है सत्य की वास्तविकता के प्रति मानसिक गति। एक आध्यात्मिक साधक में अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। यह सफलता का दूसरा रहस्य है। तीसरा तत्व है गुरु कृपा। एक साधक में अपने गुरु के प्रति सम्मान होना चाहिए, क्योंकि गुरु वह होता है जो अंधकार को मिटाता है। चौथा तत्व है समता भाव, यानी मन में किसी भी प्रकार की हीनता या अहंकार न हो। जब साधक संतुलित रहता है, तो वह अपने विकास को सही दिशा में बढ़ा सकता है।

पांचवां महत्वपूर्ण कारक है इंद्रिय निग्रह। किसी भी कार्य में आपको अपने व्यवहार पर उचित नियंत्रण रखना चाहिए। शरीर के लिए आपको भोजन, हवा, पानी और प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन शारीरिक भोजन का आध्यात्मिक शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। भोजन आपके भौतिक और मानसिक शरीर को प्रभावित करता है, इसलिए आपको संतुलित और उचित भोजन लेना चाहिए। जब भोजन संतुलित और प्रचुर होता है, तो उसे संस्कृत में प्रमिता आहार कहा जाता है। अत्यधिक भोजन करने वाला व्यक्ति सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। लंबे समय तक उपवास भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। शरीर की क्षमता के अनुसार उपवास एक प्रकार से प्रमिता आहार में शामिल होता है, क्योंकि यह पाचन अंगों को विश्राम देता है।

स्पष्ट है कि सफलता केवल बाहरी पुरस्कारों में नहीं है, बल्कि आंतरिक संतोष और विकास में भी है। एक संतुलित जीवन, जिसमें मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, वह सफलता है और हम सभी को इसी की तलाश है।

प्रस्तुति : दिव्यचेतनानंद अवधूत

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ सबके लिए जरूरी

14 अक्टूबर को 'जीवन आनंद' कॉलम में 'लोगों को करीब लाने वाला ग्लू है हंसी-मजाक' शीर्षक से प्रकाशित लेख पढ़ा। हंसी-मजाक केवल मनोरंजन का साधन नहीं, यह रिश्तों में मिठास बढ़ाता है। हंसी-मजाक तनाव को कम करता है जो शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। हालांकि कई बार हंसी-मजाक के पीछे चिढ़ाने वाली बात छिपी होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हंसी-मजाक वही है जिसका आनंद सुनने और सुनाने वाला बराबर उठा सके। जीवन की जटिलताओं के बीच हास्य को अपनाना एक बुद्धिमानी भरा कदम है। हमें अपने जीवन में हंसी-मजाक को प्राथमिकता देनी चाहिए।

सोनम गुप्ता, ईमेल से

■ संबंध मजबूत होते हैं

यह पत्र 14 अक्टूबर के लेख 'लोगों को करीब लाने वाला ग्लू है हंसी-मजाक' से संबंधित है। कभी-कभी हंसी-मजाक और व्यंग्य दोनों ही सामाजिक संवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनमें मूलभूत अंतर है। हंसी-मजाक आमतौर पर आनंद और मनोरंजन के लिए होता है, जबकि व्यंग्य अक्सर आलोचना या टिप्पणियों के लिए उपयोग किया जाता है। हंसी-मजाक एक सकारात्मक भावना को जन्म देता है। इससे लोग आपस में जुड़ते हैं। यह संबंधों को मजबूती देता है।

प्रवेश गोयल, ईमेल से

जीवन आनंद

■ फिटनेस की खुशी

फिटनेस न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक आनंद भी प्रदान करता है। नियमित व्यायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होते है, जो 'खुशी के हॉर्मोन' के रूप में जाने जाते हैं। इससे तनाव कम होता है और mood बेहतर होता है। फिटनेस से शारीरिक ताकत और सहनशक्ति बढ़ती है, जिससे रोजमर्रा के काम करने में आसानी होती है। जब हम फिट होते हैं, तो ऊर्जा स्तर उच्च रहता है, जिससे हम अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करते हैं। यह मन को भी तरोताजा रखता है।

नीलमणि कुमार, साहिबाबाद

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय : अमेरिका का बिगड़ैल बच्चा है इस्राइल - खबर - तो अमेरिका का होनहार बच्चा कौन सा देश है।

रोजी सिन्हा

[illegible]

चिंतन

रेलवे के बाद विमानन में दहशत की कोशिश

इस समय भारतीय विमानन क्षेत्र को फिर टेरर का सामना कर रहा है। विमानों को बम से उड़ाने की झूठी धमकी दी जा रही है। 14 अक्टूबर से अब तक 90 विमानों को फेक धमकी दी जा चुकी हैं। हर फेक धमकी से एयरलाइंस को तीन करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। भारतीय विमानन क्षेत्र तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, हजारों यात्री विमान परिचालन में हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। चूंकि यह धमकी रोज दी जा रही है, इसमें विमानों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए यह किसी सिरफिरे का काम नहीं हो सकता है। यह एक पैटर्न है, जिस पर सुनियोजित तरीके से काम हो रहा है। ऐसे ही कुछेक दिन पहले रोज किसी न किसी ट्रेन रूट को बाधित किया जा रहा था। कई बार ऐसा हुआ कि ट्रेन हादसा होते-होते बचा। भारतीय रेल विशाल नेटवर्क है और रोजाना दो करोड़ से अधिक लोग ट्रेन में सफर करते हैं, इसलिए रेलयात्री के मन में असुरक्षा का डर पैदा कर रेलवे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। पहले रेल यात्रियों में डर, अब विमान यात्रियों में डर। यह डर आतंकवाद है, जिसका मकसद भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना है। रेल और विमानन क्षेत्र को असुरक्षित कर देने से इन पर गहरा आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों को इस फिगर टेरर को गंभीरता से लेना चाहिए। यह आतंक का नया मॉड्यूल हो सकता है। विमानों को धमकी पर गृह मंत्रालय ने जरूर रिपोर्ट मांगी है, सरकार सख्ती की तैयारी कर रही है, लेकिन वास्तविकता में विमानों को बम से उड़ाने की झूठी धमकी केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। फौरी एक्शन से कुछ खास नहीं प्राप्त होगा। सरकार को इसकी तह में जाना चाहिए। क्या यह देश के अंदर किसी प्रतिबंधित ग्रुप की सुनियोजित हरकत तो नहीं है? क्या इसमें दुश्मन पड़ोसी देशों की खुफिया एजेंसियों के हाथ तो नहीं हैं? देश के अंदर भी कई विध्वंसक, अलगाववादी, आतंकी, नक्सलवादी, उग्रवादी ताकतें हैं, जो दुश्मन मुल्कों की कठपुतलियां हैं और चंद टुकड़ों के लिए अपने मुल्क को अस्थिर करने में जुटे रहते हैं। सरकार को हर एंगल से जांच करनी चाहिए। भारतीय रेल और विमानन क्षेत्र दुश्मनों के निशाने पर हैं। विमान व रेल यात्रा का सुरक्षित होना जरूरी है। ये भारत की लाइफलाइन हैं। आज ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच राज्यों के सात एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। सरकार मेट्रो शहरों के साथ टियर दो और तीन श्रेणी के शहरों में भी विमान सेवा का विस्तार कर रही है। परिवहन के विभिन्न क्षेत्र को बढ़ाया देकर कनेक्टिविटी को तेज और मजबूत बनाया जा रहा है, इसके लिए सुरक्षा का माहौल बहुत जरूरी है। विमान में बम होने की झूठी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, इसके पैटर्न को समझना चाहिए और इसके पीछे के टेरर मॉड्यूल का पता लगाना चाहिए। सरकार के पास सभी तरह के सुरक्षा व जांच तंत्र हैं। इजराइल के साथ बेहतर संबंध के चलते भी भारत इजराइल विरोधी आतंकी गुटों के निशाने पर रहता है। उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक ने जरूर भरोसा दिलाया है कि भारतीय आसमान पूरी तरह से सुरक्षित है, यात्रियों को बिना डरे यात्रा करनी चाहिए, लेकिन जिस मात्रा में धमकियां मिल रही हैं, आपात लैंडिंग हो रही है, उसमें यात्रियों व विमान कर्मियों में सुरक्षा का भाव पैदा होना कठिन है, क्योंकि फेक धमकी देने वाले पकड़े नहीं गए हैं, जिससे इसके पीछे का मकसद पता चले। रेल और विमान यात्रा को सुरक्षित बनाना सरकार की महती जिम्मेदारी है।

विश्लेषण
अवधेश कुमार

संगठित रहकर ही चुनौतियों का हल

ऐसा पहली बार देखा गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल से डा. भागवत के भाषण का लिंक रिपोस्ट किया और आग्रह किया कि इसे अवश्य सुना जाए। इस नाते भी इसका महत्व बढ़ जाता है। डॉ. भागवत विजयादशमी के हर भाषण के आरंभ में भारत राष्ट्र के रूप में किस तरह सर्वांगीण उन्नति कर रहा है और विश्व में इसकी महिमा, प्रतिष्ठा और साख कैसे बढ़ी है, इसकी आवश्यक चर्चा करते हैं। स्वाभाविक ही इससे स्वयंसेवकों एवं कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों के अंदर भारत को लेकर सकारात्मक आत्मविश्वास की भावना सशक्त होती है। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया।

आजकल घटनाएं इतनी तेजी से घटती और बदलती हैं कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्वजनिक स्तर पर आवश्यक गहन चर्चा और विश्लेषण नहीं हो पाता। ऐसा ही कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के महत्वपूर्ण विजयादशमी उद्बोधन के संदर्भ में हुआ। संघ का संगठन परिवार इस समय विश्व स्तर पर सबसे बड़े जन समूह और संगठनों वाला विचार परिवार है। सरसंघचालक का हर वक्तव्य उनके लिए मार्गदर्शन के समान होता है। विजयदशमी संघ का स्थापना दिवस है। इस कारण भी नागपुर से दिए भाषण का सर्वाधिक महत्व हो गया है। ऐसा पहली बार देखा गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल से डा. भागवत के भाषण का लिंक रिपोस्ट किया और आग्रह किया कि इसे अवश्य सुना जाए। इस नाते भी इसका महत्व बढ़ जाता है। डॉ. भागवत विजयादशमी के हर भाषण के आरंभ में भारत राष्ट्र के रूप में किस तरह सर्वांगीण उन्नति कर रहा है और विश्व में इसकी महिमा, प्रतिष्ठा और साख कैसे बढ़ी है इसकी आवश्यक चर्चा करते हैं। स्वाभाविक ही इससे स्वयंसेवकों एवं कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों के अंदर भारत को लेकर सकारात्मक आत्मविश्वास की भावना सशक्त होती है। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया।

आगे उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विषय पर मैं बोलने नहीं जा रहा हूं क्योंकि इस समय भारत और विश्व के लिए चुनौतियां एवं खतरे ऐसे खड़े हुए हैं जिनको समझना और उनका सामना करते हुए समाप्त करना और अपरिहार्य हो गया है। इसमें उन्होंने हिंदू समाज को ही स्वाभाविक रूप से केंद्र में रखा। इसका कारण वह लगातार बताते रहे हैं कि हिंदुओं का संस्कार, चरित्र, जीवन मूल्य और जीवन दर्शन ही ऐसा है जिसमें संपूर्ण विश्व के समुत्कर्ष, कल्याण, शांति - सद्भाव के लिए जीने और काम करने का आधार होता है। इसलिए हिंदू संगठित रहें, खतरों के प्रति सतर्क और इसे समाप्त करने के लिए सक्रिय हों जिससे भारत एक राष्ट्र के रूप में अपने सही लक्ष्य को पहचानते हुए सशक्त रह पाएगा तभी यह संभव होगा। अगले दिन समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी - "डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं को समझना होगा कि दुर्बल व असंगठित होना अत्याचार को निमंत्रण देना है।' अगर देखें तो निस्संदेह वह उनके भाषण का प्रमुख सूत्र था किंतु ऐसा उन्होंने क्यों कहा, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने भाषण के अंत में उन्होंने नवरात्र की चर्चा करते हुए बताया, उस पंक्ति को दोहराए। 'इसी साधना से विश्व के सभी राष्ट्र अपना- अपना उत्कर्ष याद कर नए सुख, शांति व सद्भावनायुक्त विश्व को बनाने में अपना योगदान करेंगे। उस साधना में आप सभी आमंत्रित हैं।' उनकी उन्होंने एक गीत की पंक्ति दोहराई –हिंदू भूमि का कण-कण हो अब शक्ति का अवतार उठे, जल -थल से अंबर से फिर हिंदू की जय - जयकार उठे, जग जननी की जयकार उठे। तो यह साधना कौन सी है? नवरात्रि में देवी वास्तव में देवताओं के शक्तियों की पुंज थीं लेकिन शक्तिशाधना शील के साथ। इसीलिए उन्होंने कहा कि संघ की प्रार्थना में कोई परास्त न कर सके ऐसी शक्ति और विश्व विनम्र हो, ऐसा शील भगवान से मांगा है। विश्व के, मानवता के कल्याण का कोई काम अनुकूल परिस्थिति में भी इन दो गुणों के बिना संपन्न नहीं होता। विश्व की मंगल साधना में मौन पुजारी के नाते संघ लगा है तो उसके पीछे यही सोच है। इसलिए संगठित होने का अर्थ दूसरे को डराना या हमलावर होना

नहीं बल्कि कल्याण के लिए शील संपन्न शक्ति साधना है। उनकी इस बात से हर भारतीय को सहमत होना चाहिए कि भारत विश्व में प्रमुखता पा रहा है तो ऐसी शक्तियां और देश हैं जिन्हें अपने निहित स्वार्थ पर खतरा नजर आता है और वह अनेक तरीकों से भारत को कमजोर और अस्थिर करने का प्रयास करते हैं।

इसके दुनिया में उदाहरण हैं कि ऐसे देश पर आक्रमण करना हो, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को अवैध अथवा हिंसक तरीकों से उलट देना हो, अंदर विद्रोह करना हो, ऐसे प्रयास चलते रहे हैं और भारत के विरुद्ध चल रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंसक तख्तापलट की चर्चा करते हुए कहा कि हिंदू समाज पर जिस तरह अकारण नृशंस अत्याचार हुए उसके विरुद्ध हिंदू समाज संगठित होकर स्वयं बचाव में घर के बाहर आया इसलिए बचाव हुआ किंतु वह समाप्त नहीं हुआ है। इससे भारत में कई प्रकार के खतरे बढ़े हैं, इसलिए विश्वभर के हिंदुओं और भारत सरकार के सहयोग की अल्पसंख्यक हिंदुओं को आवश्यकता है। वहीं पर उन्होंने कहा कि असंगठित रहना व दुर्बल रहना, यह दूसरों के द्वारा अत्याचारों को निमंत्रण देना है। चूंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान में भी मिलाने की बात हो रही है इसलिए यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। दूसरे खतरे के रूप में उन्होंने डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिस्ट की चर्चा करते हुए कहा कि यह सभी सांस्कृतिक परंपराओं के घोषित शत्रु हैं और सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं तथा जहां-जहां जो भी भद्र मंगल है उसका पूरी तरह नाश इनकी कार्य प्रणाली का अंग है। सच है कि देश में कृत्रिम तरीके से मांग, आवश्यकता अथवा समस्या के आधार पर अलगाव के लिए प्रेरित करते हैं, असंतोष को हवा देते हैं और शेष समाज से अलग व्यवस्था के विरुद्ध उग्र बनाते हैं। समाज में टकराव की संभावनाओं को ढूंढ कर टकराव खड़े करते हैं और इस तरह चारों ओर अराजकता और भय का वातावरण पैदा किया जाता है। बताने की आवश्यकता नहीं कि भारत में यह स्थिति हमारे चारों ओर है। दुर्भाग्य से सत्ता के लिए स्पर्धा में अनेक दलों ने यही पद्धति अपनायी और इसकी क्षति देश को हो रही है। इसमें संस्कार युक्त परिवार और समाज परंपरा में दोष उत्पन्न हो गए हैं और हर स्त्री को माता के रूप में देखने का आचरण कमजोर हुआ है। इसके कारण बलात्कार और अन्य शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं।

सीमा क्षेत्र से लेकर चारों ओर संकट खड़ा करने तथा बिना कारण कट्टरपन को उकसाने की घटनाएं हमारे सामने हैं जब हिंदू धर्म यात्राओं पर अकारण पथराव और हमले हो रहे हैं तथा बिना कारण हिंसा व भय पैदा करने की घटनाएं जिसे डॉक्टर भागवत ने गुंडागर्दी कहा और वही सच है। चूंकि यह योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है इसलिए इसे तुरंत नियंत्रित करना, उपद्रवियों को दंडित करना प्रशासन का काम है लेकिन उन्हें हम तक पहुंचने से रोक कर अपने प्राण व संपत्ति की रक्षा का दायित्व तो समाज का ही है। लेकिन जब तक हिंदू समाज जातियों में बंटा रहेगा तब तक यह संभव नहीं होगा, इसलिए मोहन भागवत की यह बात बिल्कुल उचित है कि समाज के सभी वर्गों में कुटुंबों की मित्रता होनी चाहिए।इस तरह डॉ. भागवत ने भारत में व्याप्त सभी खतरों, उनके कर्म और यहां तक कि उनके निदान की भी बात की और अगर आपके अंदर कोई वैचारिक भ्रांति और दुराग्रह नहीं है तो इसे स्वीकार करना पड़ेगा। अगर दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में सद्भावना व संतुलन लाकर शांति और बंधुता की ओर बढ़ना है तो भारत को विशेषकर हिंदुओं को अपने को शक्तिशाली बनाए रखना होगा । बलहीन को कोई नहीं पूछता। इसीलिए उन्होंने संगठित होने की बात की तथा असंगठित होने को आपत्तिजनक बताया।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व विश्लेषक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

स्वास्थ्य
बाल मुकुन्द ओझा

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ा रहा मोटापा

आयातित और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के अत्यधिक सेवन ने देश के नौनिहालों से लेकर किशोर, युवा और बुजुर्ग तक को अपने आगोश में ले लिया है। इसके फलस्वरूप देश और दुनियाभर में मोटापे की समस्या गंभीर रूप से उत्पन्न हो गई है। विशेषकर व्यस्क आबादी इसकी चपेट में आ गई है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को हानिकारक इसलिए माना जाता है क्योंकि इनमें स्वाद को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे कृत्रिम योजक या रसायन होते हैं। आप प्रत्येक पैकेज के पीछे लगे लेबल को पढ़कर किसी विशेष खाद्य उत्पाद को बनाने में प्रयुक्त सामग्री की पहचान कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है 1990 के बाद से दुनियाभर के व्यस्कों में मोटापा दो गुना से अधिक बढ़ गया है। इस अवधि में किशोर आबादी में मोटापा चार गुना बढ़ा है। आयातित और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के अधिक उपयोग से 2022 तक करीब 43 प्रतिशत व्यस्कों का अधिक वजन बढ़ा है वहीं 16 प्रतिशत मोटापे के शिकार हुए हैं। विश्व मोटापा एटलस 2024 के अनुमानों के मुताबिक 2035 तक लगभग 330 करोड़ व्यस्क मोटापे से ग्रस्त होंगे। साथ ही 5 से 19 साल की आयु सीमा के 77 करोड़ से अधिक किशोर और युवाओं को मोटापा घेर लेगा। भारत की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2022 तक सवा सात प्रतिशत से अधिक व्यस्क मोटापे की चपेट में थे। नेशनल फैमिली हेल्थ और मेडिकल पत्रिका लेसेन्ट आदि के अनेक प्रमाणिक सर्वेक्षणों में भी कहा गया है कि हमारे देश में पेट के मोटापे की समस्या सर्वाधिक है। यह समस्या महिलाओं में 40 और पुरुषों में 12 प्रतिशत पाई गई है। स्वास्थ्य के प्रति इस गंभीर खतरे को हमने समय रहते सख्ती से नहीं रोका तो यह देश में नशे से भी अधिक भयावह स्थिति उत्पन्न कर देगा और इसके जिम्मेदार केवल हम ही होंगे। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में देश में दबे पांव प्रवेश करने वाले जंकफूड जिसे फास्ट फूड भी कहते है, ने हमारे सम्पूर्ण पाचनतंत्र पर कब्जा कर स्वास्थ्य के जीवन तंत्र को बिगाड़ कर रख दिया है। फास्ट फूड आज घर-घर में अल्पाहार के रूप में प्रयोग में लिए जा रहे हैं। जंकफूड में कार्बोहाइड्रेट, वसा और शर्करा होती है। इसमें अधिकतर तलकर बनाए जाने वाले व्यंजनों में पिज्जा, बर्गर, फ्रैंकी, चिप्स, चॉकलेट, पेटीज मुख्य रूप से शामिल हैं। एक आहार विशेषज्ञ अनुसार बर्गर में 150-200, पिज्जा में 300, शीतल पेय में 200 और पेस्ट्री, केक में करीब 120 किलो कैलोरी होती है जो आजकल लोगों पर मोटापे के रूप में हावी हो रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आलू के चिप्स हों या कोक का वह गिलास जिसका आप दिन या रात के किसी भी समय आनंद लेते हैं, आप नहीं जानते होंगे कि आप जो नाश्ता करना पसंद करते हैं वह वास्तव में प्रसंस्कृत भोजन है।

कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें किसी न किसी तरह से बदलाव किया जाता है, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की श्रेणी में आता है। आमतौर पर, ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें उनकी शेल्फ लाइफ या उनके स्वाद को बढ़ाने के लिए बदल दिया गया है, लेकिन प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से विभिन्न स्वास्थ्य जोखिम भी होते हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आधुनिक जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। इनको न्यूनतम प्रसंस्कृत, भारी प्रसंस्कृत या अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जब किसी खाद्य उत्पाद के स्वाद, स्थिरता और बनावट को बढ़ाने के लिए कई सामग्रियों को जोड़ा जाता है, तो आप इसे भारी या अति-प्रसंस्कृत कह सकते हैं। एक सर्वे के अनुसार, 33.66 फीसदी भारतीयों ने स्वीकारा है कि वे हफ्ते में कम से कम दो बार जंकफूड या रेडीमेड फूड खाते ही हैं। भारत में रेडीमेड फूड का उद्योग भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी वार्षिक प्रगति दर 40 फीसदी बताई जाती है। तीव्र गति से बढ़ते शहरीकरण, व्यस्त जीवन-शैली और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे बदलाव ने भारत में लोगों के जीवन-यापन के तरीके को बदल कर रख दिया है। इन बदलावों के फलस्वरूप लोगों ने घर पर खाना पकाने और खाने की आदत में भी बदलाव किया है। महानगरों में रहने वाले परिवारों की तैयार भोजन, फास्ट फूड और जंकफूड पर निर्भरता ज्यादा बढ़ गई है। अब तो इनकी पहुंच घर-घर में हो गई है। यह बच्चों के प्रिय नाश्ते में शुमार हो गया है। देखा तो यह गया है कि पूरा परिवार अल्पाहार में फास्ट फूड का उपयोग करने लगा है। आहार विशेषज्ञों के अनुसार फास्ट फूड कभी-कभार तो ठीक है लेकिन इनका ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। स्वाद के पीछे के जहरीले रसायन को पहचान कर हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी होगी, इसी में हम सबकी भलाई है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सारी जीवन-ऊर्जा बाहर की तरफ यात्रा कर रही है

संकलित
दर्शन

हम दीपावली अमावस की रात को मनाते हैं! दीयों की पंक्तियां बाहर जला लेते हैं, पर दीये तो भीतर नहीं जा सकते। भीतर की अमावस तो अमावस ही रहेगी। धोखे छोड़ो! इसे स्वीकार करो कि तुम बुझे हुए दीपक हो। अपने ही कारण तुम बुझे हुए हो। अपने ही कारण भीतर प्रकाश नहीं जगा। कहां चूक हो गई है? वस्तुतः हमारी सारी जीवन-ऊर्जा बाहर की तरफ यात्रा कर रही है। इस बहिर्यात्रा में ही हम भीतर अंधेरे में पड़े हैं। यह ऊर्जा भीतर की तरफ लौटे तो यही ऊर्जा प्रकाश बनेगी। तुम्हारा सारा प्रकाश बाहर पड़ रहा है। सबको देख लेते हो, अपने प्रति अंधे रह जाते हो। जिसने स्वयं को न देखा, उसने कुछ भी न देखा। तुम्हारे भीतर का दीया कैसे जले, सच्ची दीपावली कैसे पैदा हो? उसके सूत्र हैं बड़े मधु-भरे! पीओगे तो जी उठोगे। ध्यान धरोगे इन पर, संभल जाओगे। डूबकी मारोगे इनमें, तो तुम जैसे हो वैसे मिट जाओगे और तुम्हें जैसा होना चाहिए, वैसे ही प्रकट हो जाओगे। सूत्र यह है कि जिस प्रकाश को तुम खोज रहे हो, वह तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम्हारी खोज के कारण ही तुम उसे नहीं पा रहे हो। तुम दौड़े जाते हो। थकते हो, गिरते हो। जिसे तुम खोजने चले हो, उस मालिक ने तुम्हारे घर में बसेरा किया हुआ है। तुम जिसे खोजने चले हो, वह अतिथि नहीं है, आतिथेय है। खोजने वाले में ही छिपा है। वह जो गंतव्य है, कहीं दूर नहीं, कहीं भिन्न नहीं, गंता की आंतरिक अवस्था है। अगर उसे देखना हो, उसके प्रति चेतन्य से भरना हो तो आंखें उलटाना सीखना पड़ेगा। यही ध्यान है।

एक लकड़ी का कटोरा

संकलित
प्रेरणा

एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहु-बेटे के यहां शहर रहने गया। वो एक छोटे से घर में रहते थे, पूरा परिवार और उसका चार वर्षीया पोता एक साथ ही खाना खाते थे। लेकिन वृध्द होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। बहु-बेटे कुछ दिनों तक तो ये सब सहन करते रहे। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के एक कोने में लगा दिया और अपने बूढ़े बाप से बोला कि पिता जी आप यहां पर बैठ कर खाना खाया करो। बूढ़ा पिता वहीं अकेले में बैठ कर अपना भोजन करने लगा, यहां तक की उनके खाने-पीने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठ कर खाना खाते। वहां बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता, और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले, उस छोटे बालक को उसके माता-पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखाः तुम क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा, बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूं, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खा सके, और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता-पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आये, और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया।

अंतर्मन

आज की पाती

दमघोंटू हवा के लिए जिम्मेदार कौन?

हमारा देश जो सारी दुनिया में प्रकृति प्रधान और शस्य श्यामला वसुंधरा के सौंदर्य से प्रसिद्ध है, उसकी छवि को हमने अपने स्वार्थ के लिए प्रदूषण बढ़ाकर खराब करने का काम किया है। माना कि सरकारों की गलत नीतियां प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, लेकिन क्या हम खुद प्रदूषण से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए इसकी रोकथाम के लिए कुछ प्रयास नहीं कर सकते? अगर हमने स्वार्थी होकर पर्यावरण को संभालने के लिए अभी भी गंभीरता नहीं दिखाई और हवा में प्रदूषण फैलाने वाले गलत कामों पर पाबंदी नहीं लगाई तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा सांस लेना मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। कुदरत ने तो हमें साफ-सुथरी हवा सांस लेने के लिए दी थी, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए इसमें जहर घोलकर इसे दमघोंटू बना लिया है। इस पर रोक लगनी चाहिए। - रविंद्र जोशी, बिलासपुर

ट्रेंड

ठीकरा अधिकारियों के सिर

आजम वाँ ये पुरानी आदत है कि पहले लोकप्रोप्रेस बनाकर पुरावा बटावर करते है और जब पोल खुल जाती है तो उसका ठीकरा अधिकारियों के सिर पर फोड़ देती है। गनदा पूछ रही है कि सरकार वाँ लगाम क्या अधिकारियों के हाथ में है? -अखिलेश यादव, सपा सांसद

करुणा की परिभाषा

एक वॉलेज रात ने पूछा, "करुणा वाँ पुरानी व नई परिभाषाओं में क्या अंतर है?" मेरा उत्तर था, "करुणा वाँ पुरानी परिभाषा 'पराए का पीड़ा सहना' और नई परिभाषा 'पराए का मिलकर सहायता करना' है। -कैलाश सत्यार्थी, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता

बागडोर अपने हाथों में लें

आप जो भी भावना महसूस करते है, हर विचार जो आपके दिमाग में आता है, आप अपने आस-पास वाँ दुनिया को वैसे देखते है, और वैसे प्रतिक्रिया करते है - वह सब आपके निर्माण में है। अपने जीवन वाँ बागडोर जरूरतों से अपने हाथों में लें। -हर्ष गोयनका, कारोबारी

विनम्रता सबसे खूबसूरत

विनम्रता रचनात्मकता वाँ बुलंदूर शक्ति है। अपने व्यक्तिगत अहंकार वाँ निष्पादन सीखें और अपने रचनात्मक अहंकार को अहते हुए देखें, वह आपके पास मौजूद सबसे खूबसूरत चीज है। -संजय कपूर, फिल्मकार

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

वैक्सीन संबंधी भ्रांतियां रंगमंच के जरिए की दूर

लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के कलाकार अमित शर्मा ने वैक्सीन लेने में लोगों की हिचकिचाहट और इसे लेकर फैली भ्रांतियों को रंगमंच के जरिये जीवंत करके लंदन के किल्म विएटर के कलात्मक निदेशक के रूप में अपनी पारी का आगाज किया। नाटक 'फिन्स एंड नीडल्स' का प्रदर्शन हाल ही में पूरी दुनिया में किया गया है और इसका प्रदर्शन अगले सप्ताहांत तक होगा। रॉब डुमंड द्वारा लिखित इस नाटक के जरिये वॉयिड के टीके और दुनिया भर में बच्चों से जुड़े अन्य टीकों को लेकर हुई राजनीति और फैलाई गई भ्रांतियों को दिखाने का प्रयास किया गया है। इसमें भारतीय मूल के ब्रिटेश अभिनेता गर्वी सिंह वेरा मुख्य किरदार रॉब की भूमिका में हैं। शर्मा का कहना है, 'इस नाटक से निश्चित रूप से (टीकों के पक्ष और विपक्ष में) बहस को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ से इससे एक दर्शक के लिए अपने से विपरीत विचारों वाले व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखने और उसे समझने में मदद मिलेगी।' उन्होंने कहा, 'दर्शकों के लिए मेरा जुनून है कि वे खुद को और अपनी आवाज को प्रतिबिंबित होते देखें। यह उन लोगों को भी समझाने में मदद कर सकता है, जो समान पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, लेकिन हमारे अभिनय से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।'

ऑफ बीट

घर के कामकाज करने वाले रोबोट बनाने में लगेगा समय

हाल ही में टेस्ला की प्रदर्शनी में चलते-फिरते, बोलते-नाचते 'ऑप्टिमस' रोबोट ने काफी उत्साह पैदा किया था। भले ही यह अब भी भविष्य की एक आकर्षक झलक हो, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि रोबोट उम्मीद से बेहतर साबित हुए हैं। उदाहरण के लिए, 'सोफिया' को ही लें, जिसे 2016 में टेक्सास स्थित हैनसन रोबोटिक्स ने बनाया था। इसी तरह हमने बोस्टन डायनेमिक्स के 'एटलस' जिमनास्टिक्स, ब्रिटेन निर्मित अमेका रोबोट 'वेकिंग अप' और हाल ही में टेस्ला के 'ऑप्टिमस' के सावधानीपूर्वक तैयार किये गए वीडियो देखे हैं। जाहिर है कि ये अभी अलग-अलग तरीकों से प्रभावशाली हैं, लेकिन वे पूर्ण 'पैकेज' के करीब नहीं पहुंचे हैं। ऑप्टिमस या एटलस को किसी गैर पूर्व निर्धारत स्थान पर छोड़ दें और आप बहुत कुछ अलग देखेंगे। हमारे घरों में काम करने में सक्षम एक मानव रोबोट को कई अलग-अलग कार्य करने, हमारे उपकरणों का उपयोग करने, हमारे वातावरण में गतिविधियां करने और मानव की तरह हमसे संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह केवल एक या दो साल में संच हो सकता है, तो आपको निराशा हाथ लगने वाली है।

दैनिक जागरण
जगत विचार का ही ठोस रूप है

चुनावी दौर की खटपट

गठबंधन के घटकों के बीच खटपट होते रहना कोई नई-अनोखी बात नहीं। यह खटपट तब और अधिक बढ़ जाती है जब चुनाव आते हैं और यह प्रश्न खड़ा होता है कि कौन दल कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगा। इस पर हैरानी नहीं कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की ओर से सीटों का जो बंटवारा किया गया, वह राष्ट्रीय जनता दल को पसंद नहीं आया। उसने अपनी नाराजगी भी जता दी है। आश्चर्य नहीं कि वह इसका बदला बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों में ले और कांग्रेस को बंछिष्ट सीटें न दे। जो भी हो, राजद को यह समझना होगा कि उसका प्रभाव बिहार में ही है और झारखंड में उसकी कोई विशेष राजनीतिक अहमियत नहीं है। यह बात जनता दल (यू) को भी समझनी होगी, जो झारखंड में दो सीटें मिलने से नाखुश दिख रही है। चूंकि गठबंधन राजनीति के कोई नियम-कानून नहीं बने हैं, इसलिए महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी के घटकों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। फिलहाल सत्तारूढ़ महायुति में खटपट नहीं दिख रही, लेकिन इसके आसार कम ही हैं कि सब कुछ सुगम तरीके से हो जाएगा।

सीटों के बंटवारे के बाद जब विभिन्न दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे तब भी असंतोष और विद्रोह की खबरें आएंगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भाजपा की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा होते ही असंतोष के स्वर सुनाई देने लगे हैं। कई बार असंतोष के ऐसे स्वर विद्रोह में बदल जाते हैं और चुनाव लड़ने के आकांक्षी उम्मीदवार या तो विद्रोही बन जाते हैं या पार्टी छोड़ देते हैं अथवा भितरघात में लग जाते हैं। इस स्थिति से करीब-करीब सभी राजनीतिक दल दो चार होते हैं, लेकिन वे प्रत्याशी चयन की कोई तर्कसंगत और पारदर्शी व्यवस्था अपनाने से इन्कार कर रहे हैं। आखिर कुछ विकसित देशों की तरह से भारत में भी आंतरिक चुनाव के जरिये प्रत्याशी चयन की कोई व्यवस्था क्यों नहीं बन सकती, जिससे सक्षम और योग्य नेताओं को ही चुनाव लड़ने का अवसर मिले। हमारे राजनीतिक दल लोकतंत्र की चाहे जितनी दुहाई दें, सच तो यह है कि प्रत्याशियों के चयन में आम जनता की बात तो दूर रही, संबंधित दल के कार्यकर्ताओं की भी कोई भागीदारी मुश्किल से ही होती है। लोकतंत्र का तकाजा यह कहता है कि प्रत्याशियों के चयन में संबंधित राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं और साथ ही जनता की आकांक्षाओं को भी महत्व दिया जाए। यह कोई कठिन कार्य नहीं, लेकिन इसके लिए पश्चिमी देशों सरीखी जैसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, उससे बचा जा रहा है। इन स्थितियों में उचित यह होगा कि चुनाव आयोग ऐसी कोई पहल करे जिससे राजनीतिक दल प्रत्याशियों के चयन में मनमानी न कर सकें। अभी तो वे जनता पर प्रत्याशियों को थोपने का काम करते हैं। यह समझा जाना चाहिए कि प्रत्याशियों के चयन में आम जनता की भागीदारी एक ओर जहां योग्य जन प्रतिनिधियों को सामने लाने का काम करेगी, वहीं लोकतंत्र को भी सुदृढ़ करेगी।

सराहनीय पहल

मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कला महोत्सव मनाने की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की पहल सराहनीय है। इस पहल के तहत झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों के जाने-माने 81 चित्रकारों ने कैनवस पर कलाकृतियां उकेरकर मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मतदान करने का संदेश दिया। इस दो दिवसीय आयोजन में मतदाताओं को जहां एक ओर झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों की कला-संस्कृति और परंपराओं को नजदीक से देखने का अवसर मिला, वहीं आसन्न विधानसभा चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने को प्रेरणा भी मिली। खासकर शहरी क्षेत्रों में इस तरह के प्रयास जरूरी हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में मतदान के प्रति उदासीनता कहीं अधिक देखने को मिलती रही है। इसी वर्ष संपन्न लोकसभा चुनाव में भी रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर आदि शहरों का मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। कला महोत्सव के लिए अगर रांची का चयन किया गया तो इसके पीछे का कारण यहां का मतदान प्रतिशत सबसे कम रहना है। वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां 50 प्रतिशत से भी कम मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी झारखंड दौरे के क्रम में इस पर चिंता जताते हुए शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर आवश्यक निर्देश राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी समेत सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों सह उपायुक्तों को दिए थे। साथ ही 'मजबूत लोकतंत्र-सबकी भागीदारी' के उद्देश्य को केंद्र में रखकर स्वयंसेवी संस्थाओं से भी सहयोग लेने की अपील की थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि आसन्न विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां बदलेंगी और शहरी मतदाता भी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेंगे।

प्रभावी सिद्ध हों न्याय की देवी

हृदयनारायण दीक्षित

न्यायपालिका का सम्मान है, लेकिन कई शिकायतें भी हैं। न्याय व्यवस्था को और विश्वसनीय बनना होगा

सुप्रीम कोर्ट के पुस्तकालय में स्थापित की गई न्याय की देवी की नई प्रतिमा • पीटी

न्याय आदिम अभिलाषा है। दुनिया की सभी प्राचीन सभ्यताओं में न्याय व्यवस्था के उल्लेख मिलते हैं। उनमें न्याय की प्रतीक देवी की अंखियों पर पट्टी है। एक हाथ में तलवार है। देवी का प्रतीक यूनानी सभ्यता से लंबी यात्रा करते हुए यूरोपीय देशों और अमेरिका में भी पहुंचा। औपनिवेशिक काल (17वीं सदी) में ब्रिटेन के एक न्यायिक अधिकारी न्याय की देवी की मूर्ति भारत लाए थे। भारत में कलकत्ता और बंबई हाई कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति स्थापित की गई। इसका सार्वजनिक प्रयोग होने लगा। बांग्लादेश में भी न्याय देवी की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में थी। कट्टरपंथी मुस्लिम जमातों ने इसे बुतपरस्ती बताया और तख्तापलट के आंदोलन में यह ध्वस्त कर दी गई।

स्वाधीन भारत ने न्याय की देवी के प्रतीक को अपना लिया। हाल में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्याय की देवी की एक नई प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा में आंख की पट्टी हटा ली गई है। पट्टी कानून के अंधा होने का संकेत देती थी। कानून को अंधा नहीं होना चाहिए। भारतीय सिनेमा ने अंधा कानून विषयक कई फिल्में बनाईं। देवी के एक हाथ में तलवार सजा प्रतिबिंबित करती थी। अब न्याय की देवी की प्रतिमा में तलवार की जगह संविधान है। देवी का यह प्रतीक संवैधानिक मूल्यों और विधि के समक्ष समता का संदेश देता है। देवी की यह प्रतिमा आकर्षक है। उन्हें साड़ी पहनाई गई है। सिर पर मुकुट, गले के हार से मूर्ति को सुंदर बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पुस्तकालय में यह स्थापित की गई है। साफ है देश औपनिवेशिक सत्ता के समय के कानूनों-प्रतीकों से छुटकारा पा रहा है। भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता ब्रिटिश काल में अधिनियमित हुए थे। भारतीय संसद ने भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, 2023 पारित किए। पुराने कानून कालबाह्य हो चुके हैं।

न्याय की देवी की प्रतिमा प्रेरक है। संशोधित प्रतिमा के हाथ में संविधान है तो इसीलिए कि भारत में संविधान का शासन है। न्याय की देवी का ताजा प्रतीक स्वागतयोग्य है। न्याय की देवी का इतिहास प्राचीन है। इसकी सबसे प्राचीन मूर्ति प्राचीन मिस्र में मिली थी। बाद में यूनानी और रोमन सभ्यताओं ने न्याय की देवी की मूर्तियां बनाईं। रोमन साम्राज्य में भी न्याय की देवी थी। यूनानी सभ्यता में गंभीर सृष्टि चिंतन हुआ था। होमर को कुछ विद्वानों ने यूनान का गुरु बताया है। उनके लिखे इलियड और ओडाइसी महाकाव्यों की विश्व प्रतिष्ठा है। जैसे भारत में वेदों और महाभारत के लिए वेद व्यास के प्रति श्रद्धा है, वैसे ही इलियड और ओडाइसी के लिए होमर की ख्याति है। यूनानी अपनी न्याय व्यवस्था पर गर्व करते रहे हैं, पर सुकरात को यूनानी अदालत ने ही मृत्यु दंड दिया था। न्यायपालिका ने उनका पूरा पक्ष नहीं सुना। सुकरात के विरुद्ध युवकों को पथभ्रष्ट करने का आरोप था। सुकरात 70 वर्ष के वृद्ध थे। उन्होंने कहा था, 'शासक जल्दी न करते तो भी वह थोड़े दिन बाद स्वाभाविक मृत्यु से मरते।'

भारत में दुनिया की प्राचीन न्यायपालिका है। यहां प्राचीन काल में भी व्यवस्थित न्यायतंत्र था। राजा हरिश्चंद्र, रघु और शिवि आदि न्यायप्रियता के लिए देश में आज भी चर्चित हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसएस धवन ने प्राचीन भारत की न्यायिक प्रणाली का खूबसूरत अध्ययन किया है। उन्होंने ब्रिटिश लेखकों पर प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में गलत और मनमाने विचार व्यक्त करने के आरोप लगाए। उन्होंने हेनरी मेने पर भारत की न्याय व्यवस्था को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। यही स्थिति अनेक यूरोपवादी विद्वानों की है। धवन ने भारत की प्राचीन न्याय व्यवस्था को निष्पक्ष बताया। इसके ज्ञान के लिए प्राचीन साहित्य का अध्ययन जरूरी बताया। प्राचीन न्याय व्यवस्था में न्यायाधीश कानून के अधीन थे। प्राचीन न्यायपालिका में भी न्यायधीशों का पदनुक्रम था। राजा मनमाना आचरण नहीं कर सकते थे। महाभारत के अनुसार जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने की शपथ लेता है और बाद में वैसा नहीं करता, तो उसे दंडित करना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि प्रजा की प्रसन्नता में राजा की प्रसन्नता है। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था। प्रत्येक स्तर पर अधिकारी कर्मचारी थे। न्याय व्यवस्था थी। मनु, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, बृहस्पति आदि ने प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था की सुंदर बताया है। न्यायाधीश के लिए निर्धारित आचार संहिता थी। निष्पक्ष काम करने वाला न्यायप्रिय राजा प्रशंसा का पात्र था। तब राजा आसन पर बैठते ही विवस्वान के पुत्र यम की शपथ लेकर काम करते थे। उत्तर वैदिक काल में नचिकेता और राजा यम के बीच संवाद पढ़नीय है। यम ने नचिकेता को बताया, 'धरती पर जो लोग अन्याय और उत्पीड़न करते हैं, हे नचिकेता! मैं उन्हें बार-बार दंडित करता हूं।' यम न्याय व्यवस्था के उच्चतर देवता हैं। वह दोषियों को दंड देते हैं। ऋग्वेद के अनुसार न्यायकर्ता के लिए उच्च प्रतिभा आवश्यक थी। कात्यायन ने लिखा है, 'न्यायाधीश को संयमी, निष्पक्ष और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए।' बृहस्पति ने कहा है, 'व्यक्तिगत लाभ के लिए पक्षपात नहीं करना चाहिए।' वैदिक साहित्य में राजव्यवस्था और न्यायतंत्र के विशेष उल्लेख हैं। पराशर ने कह है, 'कृतयुग के कानून कृतयुग के समय उपयोगी हैं। द्वापर के कानून अलग हैं। कलयुग के कानून पिछले युगों से अलग हैं।' प्रत्येक युग के कानून युग की विशेषता के अनुसार होते थे। प्राचीन काल से लेकर मध्य युग के अंत तक न्याय प्रणाली का लगातार विस्तार हुआ है।

संप्रति भारतीय न्यायपालिका की प्रतिष्ठा है, लेकिन तमाम मामलों में न्यायपालिका से आशा के साथ निराशा हाथ लगती है। न्याय में देरी अन्याय है। यह सिद्धांत पुराना है। देश के न्यायालयों में विचारणीय मुकदमों की संख्या पांच करोड़ है। ऐसे में यह आपेक्षा है कि न्याय की देवी समय पर सुगम तरीके से सभी को न्याय देने में प्रभावी सिद्ध हों, क्योंकि न्याय में विलंब की समस्या राष्ट्रीय चिंता का विषय है। न्यायपालिका का सम्मान है, लेकिन कई शिकायतें भी हैं। न्याय व्यवस्था को और विश्वसनीय बनना होगा।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

जन-जन का मिशन बनी स्वच्छता

रमेश कुमार दुबे

भारत में हरित, श्वेत, पीली, नीली आदि की तरह ही शौचालय क्रांति ने भी देश को एक नई दिशा दी है

खुले में शौच से मुक्त देश घोषित हुआ भारत। फाइल

स्वच्छता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जन आंदोलनों में से एक स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता से संबंधित 10,000 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाएं शुरू कीं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस आंदोलन को मिले अपार जनसमर्थन पर प्रकाश डाला और कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक ने इसे अपना मिशन बना लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर वोट लेकर सरकार बनने वालों ने कभी गंदगी को समस्या माना ही नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो अब तक की सरकारों ने स्वच्छता के प्रति उपेक्षा का भाव अपनाया और शौचालयों की कमी को कभी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं माना गया। देश में हरित, श्वेत, पीली, नीली आदि क्रांतियां तो हुईं, लेकिन शौचालय क्रांति की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यही कारण रहा कि आधुनिकता और विकास के तमाम दावों तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया भर में अपना लोहा मनवाने वाला भारत ऐसे दोषों में अग्रणी रहा, जहां लोग खुले में शौच जाते हैं। इस मामले में भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे रहा। यूपीए सरकार ने वर्ष 2012 तक सभी को शौचालय सुविधा मुहैय्या कराने के लिए देश के सभी जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान शुरू किया, लेकिन भ्रष्टाचार, नौकरशही की सुस्ती और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण लक्ष्य दूर ही रहा।

इन्हीं परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 में लाल किले की प्राचीर से अपने पहले संबोधन में जब स्वच्छ भारत का समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह लक्ष्य समय से पहले पूरा हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे इससे बेपरवाह प्रधानमंत्री मोदी ने ''पहले शौचालय फिर देवालय'' के अपने एजेंडे को लागू करने के लिए उसी सल महात्मा गांधी की जन्मतिथि अर्थात दो अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने की घोषणा की। स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय बनाने की योजना को 15 अगस्त से ही शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन को एक बड़े जन आंदोलन में बदलने के लिए सफाई मित्रों, धार्मिक गुरुओं, एथलीटों, प्रसिद्ध हस्तियों, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया के सहयोग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने इसके लिए राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी सहयोग देने के लिए आह्वान किया कि उन्हें सामाजिक दायित्व के तहत शौचालय निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए। शौचालय क्रांति में नवविवाहिताओं की जिद ने भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री द्वारा शौचालय क्रांति के आह्वान के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में नवविवाहिताओं ने ससुराल के उन घरों में रहने से साफ इन्कार कर दिया, जिनमें शौचालय नहीं थे। इससे न केवल संबंधित परिवारों में, बल्कि समाज में भी शौचालय निर्माण के प्रति नई जागरूकता आई। इसका परिणाम यह हुआ कि मात्र 10 वर्षों में 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती अर्थात दो अक्टूबर, 2019 से पहले ही भारत खुले में शौच से मुक्त देश घोषित हो गया।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में देश के 82.5 प्रतिशत परिवारों में शौचालय की सुविधा है, जबकि 2004-05 में मात्र 29 प्रतिशत परिवारों में ही शौचालय थे। इससे खुले में शौच में भारी कमी के साथ ही बीमारियों का खतरा भी कम हुआ है। नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में गिरावट आई है। स्वच्छता अभियान हर साल 60-70 हजार बच्चों की डायरिया के कारण मौत के मुंह में जाने से बचा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साल 2014 से 2019 के बीच तीन लाख लोगों की जान बचाई गई, जो डायरिया के कारण गंवा दी जाती। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार अब देश की 93 प्रतिशत महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के कारण महिलाओं में सेक्रमण से होने वाली बीमारियों में भी काफी कमी आई है। इसके अलावा लाखों स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बनने से उनके स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है। यूनिसेफ के अध्ययन के अनुसार स्वच्छता के कारण परिवारों को आज हर साल औसतन 50,000 रुपये की बचत हो रही है, जो पहले बीमारियों के इलाज पर खर्च हो जाते थे।

स्वच्छता से जुड़ी प्रतिष्ठा में वृद्धि से देश में बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी आया है। इसी का परिणाम है कि सफाई कार्य में शामिल लोगों को अब सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। स्वच्छ भारत अभियान ने देश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी किया है। देश में करोड़ों शौचालयों के निर्माण से राजमिस्त्री, प्लंबर, मजदूर जैसे लाखों लोगों को रोजगार मिला है। इतना ही नहीं, स्वच्छ भारत अभियान ने महिला राजमिस्त्रियों की एक नई पीढ़ी तैयार की है। यूनिसेफ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन से 1.25 करोड़ लोगों को किसी न किसी रूप में रोजगार मिला है। स्वच्छ भारत अभियान ने चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है। इसके तहत घरों से निकलने वाले कचरे से अब खाद, बायोगैस, बिजली और सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक जैसे पदार्थों का उत्पादन किया जा रहा है। गैबरधन योजना के तहत गांवों में बायोगैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जहां पशु अपशिष्ट को बायोगैस में बदला जा रहा है। कुल मिलाकर स्वच्छ भारत अभियान देश को एक नई पहचान देने के साथ-साथ विकास को भी नई दिशा देने में सफल दिख रहा है।

(लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संतोष साधना

मनुष्य की क्षुधा का अंत नहीं है। लखपति करोड़पति बनना चाहता है, क्योंकि वह लाख रुपये पाकर भी संतुष्ट नहीं होता। करोड़पति से पूछो, क्या इतने रुपये पाकर वह सुखी है? वह कहेगा कि 'रुपया कहां है, किसी प्रकार दिन काट रहा है।' अधिक संपत्ति रहने के बावजूद ऐसे व्यक्ति को अभाव बोध होते रहना उसका अपरिहार विरोधी भाव है। इसका उसके देह और मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शरीर और मन को अत्याधिक लोभ-लालसा में बांधकर मनुष्य जरूरत से अधिक धन संचय में लगा रहता है। इसलिए मन विश्राम नहीं पाता है। प्रश्न है, शरीर पर इसका कैसे बुरा असर पड़ता है? चूंकि मन को संतुष्ट करने की लालसा में मनुष्य परिश्रम करता रहता है। इस क्रम में वह अपने शरीर पर सामर्थ्य से ज्यादा बोझ डालता है।

वहीं व्यक्ति द्वारा शरीर पर सामर्थ्य से अतिरिक्त बोझ न देकर जो धन या संपत्ति वह उपार्जित करता है, उससे तृप्त रहने का नाम संतोष साधना है। 'तोष' शब्द का अर्थ है मन के आराम की अवस्था और संतोष का अर्थ हुआ सभी प्रकार से आराम की अवस्था में आना। हालांकि संतोष साधना का उद्देश्य यह नहीं है कि कोई आपको किसी प्रकार ठग ले या आपके ऊपर अत्याचार करे और आप उसे सह लें। अस्तित्व की रक्षा के अपने अधिकार या अपने न्यायोचित भावना का त्याग करना किसी भी तरह से उचित नहीं होता। जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सदैव संग्राम करते रहना चाहिए, लेकिन इस क्रम में कभी भी आते लोभ के वश में होकर अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को नष्ट कर संतोष भाव के विपरीत नहीं जाना चाहिए।

चूंकि मनुष्य अवसर अपने सुख के लिए लोभ वृत्ति के वश में अपने सामर्थ्य से अधिक धन उपार्जन करने का प्रयास करता है। इसके चलते शरीर और मन के स्तर पर असंतुलन पैदा होता है, जो उसके आध्यात्मिक प्रगति में बाधक बनता है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

ई-शासन की नई उड़ान

ठेंद्रराज सुथार

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां प्रापर्टी रजिस्ट्रेशन पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस हो गया है

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रापर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर एक नई मिसाल कायम की है। 'संपदा 2.0' के नाम से शुरू की गई यह पहल न केवल तकनीकी उन्नति का परिचायक है, बल्कि सुशासन की दिशा में अन्नूठा कदम भी है। डिजिटल युग में सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण और नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं सुलभ बनाना किसी भी सरकार के सुशासन के प्रयासों का प्रमुख हिस्सा है और मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत नागरिकों को किसी दफ्तर का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वे घर बैठे ही अपनी जमीन, मकान या दुकान का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नागरिक आनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, चीट्ठियें कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रिमोट रजिस्ट्रेशन की सुविधा पा सकते हैं या यदि चाहें तो स्लाट बुक कर कार्यालय जा सकते हैं। विदेश में रहनेवाले लोगों के लिए यह अधिक सुविधाजनक है।

यह पहल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में भी सहायक सिद्ध होगी। पहले नागरिकों को कार्यालयों में कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे प्रक्रिया में देरी होती थी और भ्रष्टाचार की आशंका भी बढ़ जाती थी। अब जब प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है और आधार, भू-अभिलेख एवं अन्य डिजिटल स्रोतों से जुड़े हुए हैं, तो किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े की गुंजाइश कम हो गई है। पहचान के लिए गवाह की आवश्यकता नहीं होने से नागरिकों का वक्त और धन दोनों बचेंगे। सरकार का दावा है कि संपदा पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से नागरिक स्टांप ड्यूटी की गणना, भुगतान और माडल डीड तैयार करने जैसी प्रक्रियाएं स्वयं कर सकेंगे। स्टांप शुल्क की जानकारी भी आनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे सुविधा के अनुसार लोग जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

वास्तव में संपदा 2.0 जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि तकनीकी उन्नति और सुशासन के माध्यम से नागरिकों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। यह पहल डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं को सुगम और पारदर्शी बनाने का यह प्रयास प्रशंसनीय है। सुशासन का अर्थ केवल कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों का संचालन नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी होता है कि नागरिकों को सरकारी सेवाएं सरलता, पारदर्शिता और दक्षता के साथ मिलें। मध्य प्रदेश सरकार ने संपदा 2.0 के जरिये सुशासन का एक नया मानदंड स्थापित किया है। उम्मीद है कि इस प्रकार की पहल देश के अन्य राज्यों को भी प्रेरित करेगी, ताकि समूचे देश में डिजिटल गवर्नेंस का दायरा बढ़ सके।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

बातचीत का माहौल तो बने

पाकिस्तान के साथ बातचीत की हर बार पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, लेकिन सार्थक बातचीत नहीं हो पाती। आखिर हो भी कैसे। दोनों पक्ष अपने अपने पथ पर अड़िग हैं। भारत चाहता है कि पाकिस्तान नेकदिली से हाथ बढ़ाए, भारत में आतंकवाद को एक्सपोर्ट करना बंद करे। आतंकवाद और सद्भावना साथ-साथ नहीं चल सकते। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। वह कश्मीर का मुद्दा और अब इसके साथ ही अनुच्छेद-370 का मुद्दा छोड़ नहीं सकता। पाकिस्तान को जनता तो जानती है कि भारत से संबंध सुधारने में ही उसकी भलाई है, लेकिन सत्ता के गलियारों में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की केमिस्ट्री कुछ बनने लगी थी, लेकिन वह केमिस्ट्री उनके छोटे भाई के साथ नहीं बन पाई। भारत तो संबंध सुधारन चाहता है, तभी तो विदेश मंत्री को शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए भेजा गया। यह भी एक इतिहास रहा है, जब भी भारत और पाकिस्तान की कोई सकारात्मक बातचीत होने लगती है तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसी आतंकी कार्रवाई हो जाती है, जिससे बातचीत पटरी से उतर जाती है। पाकिस्तान के नेता और जनता में ऐसे लोग हैं, जो चाहते हैं कि भारत और पाक के संबंध कभी न सुधरें।

चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग, दिल्ली

कोटे में कोटा व्यवस्था

समाचार पत्र के 20 अक्टूबर के अंक में मुख्य पृष्ठ पर हरियाणा में कोटे में कोटा व्यवस्था पर नई प्रदेश सरकार का निर्णय प्रकाशित हुआ है। यह संपूर्ण देश में जातिगत आरक्षण की नई दिशा को और संकेत करता है। यह अंत्योदय की संकल्पना को सार्थक करता है। जातिगत आरक्षण व्यवस्था राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है और राजनीतिक दल भी यह समझ चुके हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी के करोड़ों युवाओं को बहुत थोड़ी सी सरकारी नौकरियों के छलावे से बहुत समय तक नहीं बहलाया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जातिगत आरक्षण द्वारा सरकारी नौकरियों में नियुक्ति का लाभ बहुत सीमित वर्ग को ही मिला है। क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ा देने से भी केवल सांकेतिक सुधार है, जिसका धरातल पर प्रभाव न्यूनतम है। विभिन्न चुनावों में आरक्षण का विषय हिंदुओं में विभाजन का सबसे प्रमुख आधार बन जाता है, जबकि आरक्षित समाज का इससे कोई भला नहीं होता।

विनोद जौहरी, दिल्ली

नए नेता तैयार करने में पिछड़ती कांग्रेस

'अपने ही क्षत्रपों से पस्त कांग्रेस' शीर्षक से लिखे आलेख में राज कुमार सिंह ने क्रमबद्ध तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और हरियाणा विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस की दुर्दशा के लिए उसके क्षत्रपों को शीर्ष नेतृत्व द्वारा सधे जाने में विफल रहना बताया है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि कांग्रेस ने कभी जमीनी कार्यकर्ताओं में से विकल्प के तौर पर अपने नेताओं का दूसरा वर्ग तैयार ही नहीं किया, जबकि कांग्रेस के उलट भाजपा ने ऐसे नेताओं की अगली पंक्ति तैयार करने में कार्यकर्ताओं को ही महत्व नहीं दिया, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरे दलों के नेताओं को भी खास महत्व दिया। इसके जीवंत उदाहरण असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता हैं। आखिर कांग्रेस अपनी इस कमजोरी को भांपने में क्यों नाकाम रही? ऐसे में यह कहना उपयुक्त होगा कि कांग्रेस अपनी हार के लिए खुद जिम्मेदार है। जब तक इस जिम्मेदारी को समझ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पार्टी संगठन के स्तर पर व्यापक परिवर्तन को तैयार नहीं होगा, तब तक वह हरियाणा और छत्तीसगढ़ की तरह जीती बाजी भी सदैव हारता रहेगा। यह तो कांग्रेस के पुराने नेताओं की सीधी जमीन का चमत्कार है कि आज अकूराल संचालन के बाद भी पार्टी का थोड़ा-बहुत जनाधार कमोबेश हर राज्य में कायम है। यह जनाधार पूरी तरह खत्म हो जाए इससे पहले कांग्रेस हाईकमान को चेत जाना चाहिए।

mukeshkr.mi7542@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

551 एनजीओ (गैर-सरकारी संगठनों) द्वारा देशभर में ऐसे वृद्धाश्रमों का संचालन किया जाता है, जिन्हें सरकार समेत विभिन्न स्रोतों से मदद प्राप्त होती है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार।

भारतीय संस्कृति

परिवार संस्था पर आघात का षड्यंत्र

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डा. मोहन भागवत ने कहा है कि स्वयं को वोक अर्थात जागृत कहने वाले लोग आधुनिकता के नाम पर पारंपरिक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। भागवत ने कहा कि यह विचारधारा विनाशकारी और सर्वभक्षी है, जो भारतीय समाज के मूल्यों एवं उसकी सांस्कृतिक धरोहर के विरुद्ध काम कर रही है। ये ताकतें भारतीय समाज में अलगाव और भेदभाव पैदा करके उसे कमजोर करना चाहती हैं, ताकि विनाशकारी शक्तियों का प्रभुत्व कायम किया जा सके

शिवेश प्रताप
लोकनीति विश्लेषक

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में विजयदशमी के अपने संबोधन में 'सांस्कृतिक मार्क्सवाद' और 'वोक संस्कृति' पर तीखा प्रहार किया है। 'वोक संस्कृति' की आलोचना करते हुए भागवत ने कहा कि ये लोग शिक्षा और मीडिया पर नियंत्रण करके समाज को भ्रम, भय और छुपा के चक्रव्यूह में फंसाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 'वोक' विचारधारा का उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति, राजनीति और सामाजिक वातावरण को अराजक एवं भ्रष्ट बनाना है, ताकि समाज भीतर से कमजोर हो जाए। इस विचारधारा से प्रभावित लोग नहीं चाहते कि भारत अपने दम पर खड़ा हो और इसलिए वे समाज को एकजुटता को तोड़ने के लिए सक्रिय हैं। लिहाजा उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि वे भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित सकारात्मक बदलावों के साथ आगे बढ़ें, जिससे न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया को सही दिशा मिल सके।

कहा जा सकता है कि मोहन भागवत ने साफ्ट पावर कोलोनाइजेशन पर आघात करते हुए भारतीय समाज को इसके विरुद्ध जागरूक करने का प्रयत्न किया। ऐसे में हमें मोहन भागवत के इन विचारों को गहराई से समझना चाहिए। वस्तुतः विश्व में हुए लोकतांत्रिक जागरण एवं संचार क्रांति के द्वारा जब औपनिवेशिक शक्तियों के लिए सामाजिक व शारीरिक गुलामी संभव नहीं रही तो वैचारिक गुलामी का एक नया दौर प्रारंभ किया गया जिसे साफ्ट पावर कोलोनाइजेशन कहा जाता है। इस नए दौर की औपनिवेशक शक्तियां मतांतरणकारी, पूंजीवादी और वामपंथी स्वरूपों में इस वैचारिक गुलामी को प्रभावी बनाते दिखाई देती हैं। वैश्विक स्तर पर इस्लाम एवं ईसाइयत के बीच चलने वाला धौषित युद्ध हो या पूंजीवादी देशों एवं वामपंथी विचारधारा के बीच का अघोषित युद्ध, भारत इन अधर्मी ताकतों के लिए जनसंख्या, भूगोल, जलवायु आदि सभी रूपों से अपने प्रदर्शन के लिए सबसे सुखद संभावनओं वाला देश दिखाई पड़ता है। पिछली सदी के अंतिम दशक के आर्थिक तौर में विश्व में हुए खम्बवादी-वामपंथी शक्तियों के पराभव के बाद चीन धीरे-धीरे एक पूंजीवादी देश बन गया तथा भारतीय वामपंथी विचारधारा भारत में एक परजीवी बनकर इस्लामिक एवं ईसाई मतांतरण व पूंजीवादी ताकतों की बी टीम के रूप में कार्य कर रही है। इसका लक्ष्य है भारत की सनातन परंपरा का नुकसान कर इसे इस्लामिक एवं ईसाई ताकतों का उपनिवेश बना दिया जाए। इन्हीं विचारों के क्रम में विगत तीन दशकों से वैश्वीकरण के नाम पर पूंजीवादी देशों (अमेरिका, यूरोप एवं चीन) के द्वारा भारत को आर्थिक उपनिवेश बनाने एवं मतांतरण की शक्तियों द्वारा इसे अरब एवं वेटिकन का धार्मिक उपनिवेश बनाने हेतु भारत की कुटुंब प्रणाली पर आघात किया जा रहा है, क्योंकि यही परिवार व्यवस्था इन कुचक्रों हेतु बड़ी बाधा बन रहा है।

परिवार/ विवाह संस्कार पर आघात : कुटुंब व्यवस्था का आधार स्तंभ है विवाह संस्कार। पति एवं पत्नी मिलकर वंश परंपरा में तीन पीढ़ियों का पालन-पोषण करते हैं, जिसमें उनके माता-पिता एवं बच्चे शामिल होते हैं। पूंजीवादी शक्तियों के भारत में पनपने में यह सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि एक ही छत के नीचे स्त्रियां मिलकर सभी गृहकार्य कर लेती हैं और पुरुष मिलकर आर्थिक एवं सामाजिक दायित्व निभाते हैं। बुजुर्ग, बच्चों के साथ संवाद करके उनकी जिज्ञासाओं को पूष्ट करते हुए उन्हें सामाजिक संस्कार देते हैं। कल्पना कीजिए कि यह विवाह संस्कार टूटने से क्या प्रभाव पड़ेगा? बुजुर्गों को मोटी फीस देकर वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा, उनके लिए नर्स, कुक, क्लीनर आदि सेवक सेविकाएं सब पैसे पर आएंगे। इसके अलावा, सभी स्त्री एवं पुरुष जो एकल जीवनशैली में रहेंगे, वे भी जीवन से जुड़ी अपनी सभी आवश्यकताओं हेतु बाजार पर निर्भर होंगे। घर से रसोई कक्ष समाप्त होगा तो रेस्टोरेंट व्यवसाय को गति मिलेगी। कपड़े धुलने हेतु लांड्री, सफाई हेतु क्लीनर आदि सभी आवश्यकताओं हेतु व्यक्ति बाजार पर निर्भर होगा। 'यूज एंड थ्रो' की संस्कृति विकसित होने से पूंजीवाद पर निर्भर व्यक्ति एक इकाई के रूप में भाव शून्य हो पैसे कमाकर अपनी जरूरतों को पूर्ण करने का यंत्र बन जाएगा।

विवाह परंपरा के समाप्त होने से व्यक्ति का कुटुंब समाप्त होगा तो एकल व्यक्ति का ब्रेनवाश करना मतांतरण गिरोहों के लिए आसान होगा। किसी को वृद्धाश्रम की सेवा के नाम पर मतांतरित किया जाएगा तो किसी को सर्वसांरिक मुक्ति के नाम पर। बच्चे जो अपने दादा-दादी से अलग परिवारिकओं के संरक्षण में पलेंगे या माता-पिता के साथ एकाकी जीवन में होंगे तो उनके भीतर मानवीय संवेदनाएं और सामाजिक संस्कार शून्य होंगे। इससे उनका ब्रेनवाश आसानी से संभव होगा। आइएसआइएस के द्वारा यूरोप के बच्चों को आतंक हेतु इंटरनेट पर प्रभावित करते देख गया जिससे वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ी हैं।

भारतीय त्योहारों पर कुचक्र : भारत की परिवार व्यवस्था पर आघात करने के लिए ऐसे सभी भारतीय त्योहारों पर आघात किया जा रहा है जिसे भारतीय परिवार मिल-जुल कर मनाते हैं। इसके लिए औपनिवेशिक मानसिकता वाले मतांतरण गैंग स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं कारपोरेट संस्थाओं आदि में ईसाइयों के त्योहार पर छुट्टियां प्रदान करते हैं, परंतु हिंदू त्योहारों पर धीरे-धीरे लंबी छुट्टियां को समाप्त कर एकदिवसीय छुट्टी दी जाती है। कान्वेंट आधारित स्कूली शिक्षा एवं वामपंथी नेक्सस के द्वारा निर्मित होने वाले विश्वविद्यालयों द्वारा बच्चों की परीक्षाओं को हिंदू त्योहारों के इर्द-गिर्द डाला जाता है जिससे चाहते हुए भी कोई परिवार इकट्ठा होकर त्योहारों का आनंद न ले सके। कारपोरेट कंपनियों में 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक धोषित रूप से छुट्टियां कर दी जाती हैं, क्योंकि इस दौरान ईसाई क्रिसमस के लिए छुट्टियां मनाते हैं, लेकिन तर्कसंगत बात यह है कि हिंदुओं के लिए ऐसी छुट्टियों का क्या मतलब? पूंजीवादी वामपंथी नेक्सस ने भारत में एक विमर्श खड़ा कर दिया कि दीपावली से प्रदूषण होता है, होली से पानी की बर्बादी होती है। वहीं, पश्चिमी त्योहारों जैसे वैलेंटाइन डे, थैंक्सगिविंग, क्रिसमस आदि पर महंगे उपहार के द्वारा पूंजीवाद को प्रमोट किया जाता है।

उपभोक्तावाद के निशाने पर भारत की जनता

उपभोक्तावाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार ऐसे विचार गढ़े जाते हैं कि जो व्यक्ति बड़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, वे बेहतर स्थिति में होते हैं। थोरस्टीन वेबलन 19वीं सदी के अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे, जिन्हें अपनी पुस्तक 'द थ्योरी आफ द लीजर क्लास' (1899) में 'विशिष्ट उपभोग' शब्द गढ़ा। विशिष्ट उपभोग किसी की सामाजिक स्थिति को दिखाने का एक साधन है, खासकर जब सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित सामान और सेवाएं उसी वर्ग के अन्य सदस्यों के लिए बहुत महंगी हों।

आम तौर पर उपभोक्तावाद का मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों की अत्यधिक भौतिकवाद की जीवनशैली अपनाने की प्रवृत्ति से है, जो रिफ्लेक्सिव, अत्यधिक उपभोग के इर्द-गिर्द घूमती है। सांस्कृतिक मोहन भागवत द्वारा उठाए गए बिंदु यह दर्शाते हैं कि ऐसी विचारधाराएं जो संस्कृतिक मार्क्सवाद या वोक विचारधारा के तहत आती हैं, भारतीय समाज में भेदभाव, भ्रम और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करती हैं। इनका उद्देश्य पारंपरिक संस्कृतिक व्यवस्थाओं और मूल्यों को ध्वस्त करना है, ताकि समाज में अराजकता पैदा हो सके। वोक संस्कृति के प्रति सावधानी बरतते हुए हमें अपने समाज की एकता, संस्कृतिक धरोहर व नैतिकता को बनए रखना होगा। यह आवश्यक है कि भारतीय समाज अपने सांस्कृतिक मूल्यों पर गर्व करे और अपने रास्ते पर अडिग रहते हुए मूल्यों को अपनी शक्ति बनाकर विश्व मंच पर साफ्ट पावर के रूप में प्रस्तुत करें, जैसे वर्तमान में विश्व योग, अध्यात्म व आयुर्वेद के रूप में हमारी संस्कृतिक विरासत को स्वीकार कर रहा है। इस तरह भारत अपने दम पर खड़ा होकर दुनिया के सामने एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभरेगा जिसका नेतृत्व लंबे समय तक विश्व को आलोकित कर सकेगा।

पारिवारिक ढांचे में एक ओर जहां एक भाई दूसरे के सुख-दुख में भाग लेकर, अपने माता-पिता की सेवा करने में सुख और शांति महसूस करता था, उसे अब उपभोक्तावाद ने कमाई के अनुरूप अपने भौतिक सुखों की वृद्धि के मानक पर विभाजित कर दिया है।

उपभोक्तावाद विज्ञापन उद्योग के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं को जन संस्कृति के अगुआ के रूप में स्थापित करती है जो सक्रिय और रचनात्मक लोगों के बजाय ब्रांडों द्वारा नियंत्रित लोगों को लोकप्रिय बनाती है। ऐसे नियोजित पूर्वाग्रह उपभोक्तावाद को जन्म देते हैं। अगर इन पूर्वाग्रहों को खत्म कर दिया जाए, तो बहुत से लोग कम उपभोक्तावादी जीवनशैली अपनाएंगे। उपभोक्तावाद का एक उदाहरण हर साल मोबाइल फोन के नए माडल पेश करना है। जबकि कुछ साल पुराना मोबाइल डिवाइस पूरी तरह से काम करने लायक और पर्याप्त हो सकता है, उपभोक्तावाद लोगों को उन मोबाइल को छोड़ने और नियमित आधार पर नए मोबाइल खरीदने के लिए प्रेरित करता रहता है। जबकि यही पैसे परिवार के भाई, भतीजे, बेटी, बुजुर्ग माता-पिता की जरूरतों में खर्च हो सकता था, लेकिन उपभोक्तावाद ने इस सामाजिक साहचर्य को समाप्त कर दिया। इसी उपभोगवादी समाज में अब अपने रिश्तेदारों चाचा, मामा, फूफा, मौसा के यहां रहकर पढ़ने-लिखने, जीवन बनाने जैसे उदाहरण भी दिखना लगभग शून्य हो चुका है। इस अर्थ में, उपभोक्तावाद को पारंपरिक मूल्यों और जीवन के तरीकों के विनाश, बड़े व्यवसायों द्वारा उपभोक्ता शोषण, पर्यावरण क्षरण और नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभावों में योगदान देने के लिए व्यापक रूप से समझा जा सकता है।

(शिवेश प्रताप)

खरी-खरी

ईवीएम : कभी सौतन कभी सहेली!

मुकेश तटेर

एक प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक में दो पत्नकी सहेलियों की कहानी थी, जिसमें वे एक ही व्यक्ति से प्रेम कर बैठती हैं। जब उन्हें पता चलता है तो वे अपने प्रेमी की बेवफाई से दुखी होकर अलग हो जाती हैं। आज ईवीएम का हाल भी कुछ ऐसा ही है, उस पर भी वक्त बेवक्त बेवफाई के आरोप लगते रहते हैं। अंतर बस इतना है कि इधर ईवीएम नायिका है और परस्पर विरोधी राजनीतिक दल नायक। एक फूल दो माली। उधर दो फूल एक माली था। खैर, एक नायक तो फिर भी समझदारी दिखाता है, क्योंकि वह लगातार जीत रहा है। जीतने वाला समझदार माना जाता है, परंतु दूसरा जब चुनाव जीतता है तो ईवीएम सहेली हो जाती है, जैसे ही चुनाव हारा, उसे सौतन बताते देर नहीं करता। सौतन के साथ कैसा दुर्व्यवहार होता है आप जानते ही हैं।

एक समय था जब देश में मतपत्रों से चुनाव होते थे। बजह निरक्षर मतदाताओं की अधिकता और तकनीक का अभाव था। मतदाता मतपत्रों पर मुहर लगाकर मतपेटी में डालते और मतदान हो जाता। 'पंच-म' (मतदाता, मतपत्र, मुहर, मतपेटी और मतदान) की महत्ता थी। इस पद्धति में जो भी फर्जीबाड़ा करना होता, करने वाले मतदान के दौरान करते यथा मतदाताओं से बलपूर्वक मतदान, मतपत्रों पर फर्जी मतांकन, मतपत्र फाड़ना और मतपेटियां ले भागने तक की शिकायतें आती थी।

निर्वाचन में तकनीक आई। अब मतपेटी की जगह ईवीएम (कंट्रोल यूनिट), मतपत्र की जगह बैलेट यूनिट ने ले ली। न मुहर लगाने की झंझट, न मतपत्र मतपेटी में घुसेड़ने की खटपट। बूथ पर जाओ, बटन दबाओ और हो गया मतदान। जितना आसान मतदान, उतनी ही आसन मतगणना। आप सोच रहे होंगे, तब तो बढ़िया ही हो गया। चुनाव है साहब इतना भी आसन न समझो। ये इश्क नहीं आर्स टाइप, ईवीएम दबाने वाली उंगली ही ईवीएम पर उठने लगी।

बहरहाल, बात जहां से शुरू की वहीं लाकर खत्म करते हैं कि ईवीएम बेचारी क्या करे? वह कोई जैविक तो है नहीं जो अपनी बेवफाई पर सफाई दे दे और न पक्कमुद्रा जो अपना सौना फाड़कर दिखा दे।

पोस्ट

भारत की सबसे बड़ी समस्या खराब शासन है। जैसे-जैसे आप निचले स्तर पर जाते हैं, यह इतना बद से बदतर हो जाता है कि इसका अस्तित्व ही नजर नहीं आता है। पिछले हफ्ते मैंने महाराष्ट्र के एक गांव में इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा।
तवलीन सिंह@tavleen_singh

ट्रेन की पटरियों पर आए-दिन कुछ न कुछ रख कर उन्हें पटरियों से उतारने की साजिशें करना और यात्रियों में दहशत फैलाना। अब एक के बाद एक कई हवाई जहाजों में बम की अफवाहें फैला कर यात्रियों, एयरलाइंस और देश को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना। देश इस समय कई चुनौतियों से जूझ रहा है।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

इन दिनों चुनावों में एक टैंड देखा जा रहा है। पहले राजनीतिक दल वोट पाने के लिए रेवड़ी बांटने की घोषणा करते हैं। चुनाव जीतने के बाद अगर केंद्र में समान दल या गठबंधन की सरकार है तो वे चुप रहते हैं और काम चला लेते हैं। विपरीत स्थिति में केंद्र पर धन आवंटित न करने का आरोप लगाते हैं। यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक परेशान करने वाली मिसाल है।
हर्ष गोयनका@hvgoenka

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या अधोसंरचना आरक्षण में क्रीमीलेयर की सीमा को मौजूदा आठ लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये किया जाना चाहिए?

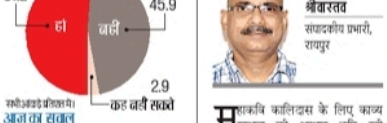

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

अन्य क्या सवाल

क्या आप मानते हैं कि भारतीय टेस्ट टीम के लिए न्यूजीलैंड से मिली हार बड़ी चुनौतियों से पहले एक जरूरी झटका है?

घरिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

धम्मकी मिले विमान को पटरी पर उतारोः, कैसेहो अब यात्रा जरा करोओ बोध।
जरा करोओ बोध उन्हें आता है सुनकर, यह जाते हैं लोग कितुमन में जल भुन कर।
रोज-रोज आपराह सुनाई देती धमकी, खुरपघत यह कौन करे यह देकर धमकी!
- ओमप्रकाश तिवारी

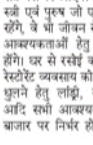

हरिशंकर मिश्र
वरिष्ठ संपादक, संपादक, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश डायरी

सपा के किले और दरारें तलाशती भाजपा

योगी आदित्यनाथ। फाइल

अखिलेश यादव। फाइल

इसे यदि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल न भी माना जाए तो शक्ति परीक्षण तो माना ही जा सकता है, क्योंकि साख का सवाल समाजवादी पार्टी के लिए है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। प्रदेश में नौ विधानसभा सीटों पर उप चुनाव के लिए तारीखें धोषित हो चुकी हैं और सपा को इसके जरिये यह साबित करना है कि लोकसभा चुनाव में उसकी सफलता अनायास नहीं थी और जनता का मूड बदल रहा है, तो भाजपा को यह स्थापित करना है कि जनमत अभी उसके साथ है और योगी के सुशासन व कानून व्यवस्था को मान्यता देता है। यही वजह है कि भाजपा की निगाहें पिछले चुनाव में जीती गईं सपा की सीटों पर अधिक है। इसलिए भी कि इनमें कई सपा का गढ़ मानी जाती हैं और उन पर जीत पार्टी का मनोबल ठौगना कर देगा। करहल और कन्नौज जैसी सीटें तो सीधे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की छवि से जुड़ी हैं, इसलिए भाजपा की निगाहें इनमें दरार तलाश रही हैं। वैसे तो चुनाव बरसा भी लड़ रही है, लेकिन जिन नौ सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से एक भी उसने पिछले चुनाव में नहीं जीती थी, इसलिए कितनी सीटों पर उसका सिक्का चलता दिखाई देगा, कहना मुश्किल है।

बीते यानी 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उप चुनाव वाले क्षेत्रों में भाजपा गठबंधन और सपा का मुकाबला कटि का रहा है। वर्तमान में दस सीटें रिक्त हैं जिनमें चुनाव नौ पर ही होना है, एक सीट मिल्कीपुर का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इन दसों सीटों पर पांच भाजपा गठबंधन और पांच समाजवादी पार्टी ने जीतीं थीं। भाजपा गठबंधन के सहयोगियों में अपना दल (एस) और रालोद के हिस्से एक-एक सीट आई थी। समीकरण बदले हैं और अब रालोद भाजपा के साथ है तो सपा की कांग्रेस का साथ मिल रहा है। कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा भले ही मजबूत न हो, लेकिन सपा को उससे मनोवैज्ञानिक मजबूती तो मिलती ही है। तैयारियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने छह सीटों पर अपने उम्मीदवार धोषित कर बढ़त ली है और चुनाव वाले क्षेत्रों में सक्रिय भी है, लेकिन भाजपा भी पीछे नहीं। उसकी ओर से उम्मीदवारों पर मोहर भले ही न लगी हो, लेकिन विधानसभा क्षेत्रों के लिए मंत्रियों को प्रभारी बनाकर वह आधार बनाने में जुटी है।

इस उप चुनाव के राजनीतिक मायने इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 2027 के आम चुनाव तक इनका संदेश जाएगा ही। इसलिए भाजपा और सपा दोनों ही कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहतीं। भाजपा की गंभीरता का अनुमान इस बात से ही समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं दो विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी ले रखी है और दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी दो-दो क्षेत्रों के लिए जवाबदेह बनाया है। मुख्यमंत्री स्वयं न केवल चुनाव क्षेत्रों वाले जिलों में जा चुके हैं, बल्कि पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा का क्रम भी जारी है। दूसरी ओर आम तौर पर उप चुनावों में प्रचार के लिए न जाने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार स्वयं भी मैदान में दिखाई देंगे। संगठनात्मक और रणनीतिक मजबूती के लिए वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव को कटेहरी विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाने के साथ ही सभी वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी के रूप में चुनाव क्षेत्रों में जोत दिया गया है।

उप चुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर और मतगणना 23 नवंबर को होगी, लेकिन इससे पहले भाजपा को कई चुनौतियों से जूझना होगा। विशेष तौर पर करहल, कन्नौज, सीसामऊ और अंबेडकरनगर उसके लिए बड़ा मोर्चा साबित होने जा रहे हैं। करहल को सपा की सुरक्षित सीट माना जाता है। भाजपा ने यहां दबाव के रूप में सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संध्या यादव और उनके पति अनुजेश यादव को अपने से जोड़ा है और वे टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं, लेकिन मुलायम से इस क्षेत्र के लोगों के भावनात्मक जुड़ाव को तोड़ पाना आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी ने टिकट देने में भी सतर्कता और राजनीतिक समझदारी बरती है, इसलिए संसदों के परिजनों को भी चुनाव मैदान में उतारने से परहेज नहीं किया है। कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के इरफान सोलंकी पिछली बार विजयी हुए थे। वहां से इस बार उनकी पत्नी नसीम सोलंकी उम्मीदवार हैं। तीन बार के विधायक रह चुके मुजम्मा सिद्दीकी को फूलपुर, अंबेडकरनगर से सांसद बनने के बाद लालजी वर्मा की सीट कटेहरी पर उनकी पत्नी शोभावती वर्मा और मीरजापुर की मझवां सीट से डा. ज्योति बिंद सपा प्रत्याशी होंगी। डा. ज्योति बसपा से तीन बार विधायक और भदोही से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे डा. रमेश बिंद की बेटी हैं। भाजपा के पते भी एक-दो दिन में खुलने वाले हैं जो उप चुनाव में लोगों को विधानसभा के आम चुनाव का रोमांच देंगे।

छत्तीसगढ़ डायरी

हवाई संपर्क से विकास को नई गति

सतीश चंद्र श्रीवास्तव
संपादकीय प्रभारी, रायपुर

महाकवि कालिदास के लिए काव्य साधन की आधार भूमि रही सरगुजा (अंबिकापुर) से संपर्क का मार्ग अब कुछ सरल हो गया है। बादलों के बीच से गुजरते हुए वायुयान 'मेघदूतों' की धरती तक पहुंचाएंगे। रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी से जिन परियोजनाओं की शुरुआत की, उनमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और मध्य प्रदेश के रीवा के टर्मिनलों ने प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध इतिहास की संजोए इन क्षेत्रों को दुनिया से सुगम संपर्क में ला दिया है। विकास की उड़ान भरने को तैयार अंबिकापुर तक पहुंचना मुश्किलों भरा रहा है। सड़क-रेल मार्ग अभी भी विकास की प्रक्रिया में हो है। ऐसे में अंबिकापुर का मां महामाया हवाई अड्डे का नया टर्मिनल यहां तक पहुंचाने का साधन बनने जा रहा है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर हिंद महासागर तक के प्राकृतिक सौंदर्य पर साहित्य के सृजनकर्ता कालिदास ने अपने सबसे सुंदर खंड काव्य मेघदूतों की रचना के प्रस्थान बिंदु के लिए सरगुजा का ही चयन किया था। इससे क्षेत्र की विशिष्टता को सहज समझा जा सकता है। रामगढ़ पहाड़ियों की गुफा से कालिदास के यक्ष ने आषाढ़ के पहले बादल देखे और उसका हिमालय की अल्का नगरी तक मार्ग प्रशस्त कर दिया। वही अल्का नगरी जो कैलास पर्वत पर अलकनंदा नदी की किनारे बसी थी और कभी धन के देवता कुबेर और यक्षों की राजधानी रही। कहना गलत नहीं होगा कि सरगुजा क्षेत्र की ऐतिहासिक समृद्धि और वर्तमान स्थिति में भी हिमालय और हिंद महासागर जैसी दूरी स्थापित हो चुकी है। यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री ने ही मजबूत न हो, लेकिन सपा को उससे मनोवैज्ञानिक मजबूती तो मिलती ही है। तैयारियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने छह सीटों पर अपने उम्मीदवार धोषित कर बढ़त ली है और चुनाव वाले क्षेत्रों में सक्रिय भी है, लेकिन भाजपा भी पीछे नहीं। उसकी ओर से उम्मीदवारों पर मोहर भले ही न लगी हो, लेकिन विधानसभा क्षेत्रों के लिए मंत्रियों को प्रभारी बनाकर वह आधार बनाने में जुटी है।

मां महामाया हवाई अड्डे के उद्घाटन अवसर पर रविवार को अंबिकापुर में राज्यपाल रमेन डेका (बाएं) और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मंत्रणा करते हुए। जनसंपर्क विभाग

के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में विष्णुदेव साय ने पिछले दस महीनों में आदिवासी बाहुल्य बस्तर और सरगुजा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। परिणामतः इन क्षेत्रों में सड़क, रेल और वायु संपर्क के लिए विशेष प्रयास सामने आ रहे हैं। यह स्थापित सत्य है कि आवागमन के साधन केवल दो संस्कृतियों को ही नहीं जोड़ते, बल्कि इनके माध्यम से विकास और व्यापार को विस्तार मिलता है। हवाई अड्डे तो दुनियाभर में आसानी से पहुंचने की खिड़की भी खोल देते हैं।

यहां छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में जंगल, पहाड़ और झरने प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाते हैं, तो आदिवासी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को संजोए हैं। वामपंथी उग्रवादियों के कारण बस्तर राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय चर्चा में रहता है और विकास की प्राथमिकता भी मिली है, परंतु वर्षों से उपेक्षित रहे सरगुजा क्षेत्र में अब विकास की नई शुरुआत हुई है। विकास में पिछड़े दोनों क्षेत्रों की संस्कृति को मतांतरण की बड़ी चुनौती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के निवासी विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद क्षेत्र में अधोसंरचना के साथ ही उद्योग, सिंचाई, पर्यटन आदि की नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं। कनेपन प्रसंस्करण उद्योगों का विकास हो रहा है तो बेहतरीन आधोहरा प्राकृतिक चिकित्सा के लिए संभावनओं के द्वार भी खोल रहे है। अंबिकापुर अड्डा इसे और गति देने में सहायक बन सकता है। अब मां महामाया और मां दंतेश्वरी हवाई अड्डों के माध्यम से आदिवासी बाहुल्य सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों का संपर्क भी स्थापित हो सकेगा।

वायुमार्ग से संपर्क के कारण उत्तर में बलरामपुर से दक्षिण में बस्तर के सुकमा के अंतिम छोरों तक की लगभग एक हजार किलोमीटर की दूरी अब दुरूह नहीं रह जाएगी। रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सड़कों के लिए नितिन गड़करी की हरी झंडी मिल चुकी है। समझा जा सकता है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में विष्णु देव साय सरगुजा के आदिवासियों की पीड़ा से परिचित रहे हैं। वे वनवासी कल्याण आश्रम से भी जुड़े रहे हैं और क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार के लिए लंबे समय से कार्य भी करते आए हैं। अब मुख्यमंत्री के रूप में पूरी शक्ति के साथ कार्य को आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के तहत 63 हजार गांवों के पांच करोड़ लोगों को लाभ होगा है। उसमें सरगुजा संभाग के अधिकांश गांव शामिल हैं। सरगुजा में पर्यटकों के लिए अच्छी अधोसंरचना भी उपलब्ध है। महामाया हवाई अड्डा श्रद्धालुओं को राम वन गमन पथ के दंडकारण्य के सबसे आरंभिक बिंदुओं को देखने का अवसर भी प्रदान करेगा और वे देख पाएंगे कि किस तरह जनजातीय समुदाय ने भगवान श्रीराम की सुंदर स्मृतियों को अब तक सहेज रखा है। आवश्यकता है कि विकास की परियोजनाओं को और गति देकर समय सीमा में पूरा करा किया जाए।

****

कल्पमेधा

सही मायने में बुद्धिपूर्ण विचार हजारों दिमागों में आते रहते हैं, लेकिन उनको अपना बनाने के लिए उन पर गहराई से तब तक विचार करना चाहिए जब तक वे हमारी अनुभूति में जड़ न जमा लें ।
– गोथे

दोहरा रवैया

कनाडा के बाद अब अमेरिका ने भारत द्वारा घोषित एक आतंकी और खालिस्तान समर्थक को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। वहां की खुफिया एजंसी एफबीआइ ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक भारतीय नागरिक को अति वांछित घोषित किया है। इससे संबंधित एक सचित्र पोस्टर भी जारी कर दिया है। एफबीआइ ने उसे भारतीय खुफिया एजंसी 'रा' का एजंट बताया है। उसके खिलाफ न्यूयार्क की एक अदालत में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। हालांकि भारत सरकार ने एफबीआइ के इस आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि वह व्यक्ति अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। कुछ समय पहले अमेरिका के सुरक्षा विभाग ने आरोप लगाया था कि दो भारतीय नागरिकों ने पन्नू की हत्या की साजिश रची थी, उसे मारने के लिए निशानेबाजों को पैसे भी दिए थे। इस संबंध में भारत और अमेरिका के सुरक्षा अधिकारियों की परस्पर बातचीत भी हुई, मगर अमेरिका अपने रुख पर अड़ा हुआ है कि इस तरह किसी दूसरे देश के नागरिक उसके देश में घुस कर उसी के नागरिक की हत्या की साजिश रचेंगे, तो यह अक्षम्य अपराध है। जिन दो भारतीय नागरिकों को साजिशकर्ता बताया गया है, उन पर धनशोधन और गलत तरीके से धन की लेनदेन का भी मुकदमा दर्ज किया गया है।

कनाडा का आरोप है कि उसके एक नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय खुफिया एजंसियों के लोग शामिल थे। यहां तक कि उसने कनाडा में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भी इस साजिश में शामिल बता दिया। इसे लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए कनाडा से अपने सभी दूतों को वापस बुला लिया और कनाडा के दूतों को वापस भेज दिया। अब पन्नू मामले को तूल देकर एक तरह से अमेरिका कनाडा के साथ खड़ा हो गया है। इन दोनों देशों की अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता एक बात है, मगर उनके ताजा रुख से आतंकवाद को लेकर उनका दोहरा रवैया ही पता चलता है। विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने दुनिया भर के देशों से अपील की थी कि वे आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों। भारत शुरू से अमेरिका की इस मुहिम में साथ खड़ा रहा है। मगर विचित्र है कि भारत ने जिन आतंकियों को वांछित घोषित कर रखा है, उनके खिलाफ न तो कनाडा ने कभी सकारात्मक रुख दिखाया और न अमेरिका ने। जिस पन्नू को लेकर अमेरिका नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का परचम फहरा रहा है, वह भारत का घोषित आतंकी है।

यह कोई नई बात नहीं है कि कई देश अपने यहां आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ दूसरे देशों में भी घुस कर अभियान चलाते रहे हैं। अमेरिका खुद अपने घोषित आतंकियों की पहचान कर दूसरे देशों की जमीन पर उन्हें मार चुका है। वह बड़े गर्व से इसका बखान भी करता रहा है, चाहे वह लादेन रहा हो, अल-जवाहिरी या कासिम सुलामानी। इजराइल भी यही काम करता रहा है। भारत तो उनसे अपने आतंकियों के खिलाफ उनसे कार्रवाई की मांग करता रहा है, उस पर ध्यान देना उन्हें जरूरी नहीं लगता। पन्नू मामले को इतना तूल देकर आखिर अमेरिका ने यही साबित किया है कि दूसरे देशों के खिलाफ आतंकी गतिविधियां चलाने वालों के प्रति उसका रवैया नरम है। उसके इस रुख से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और कमजोर होगी।

आतंक का सिलसिला

कश्मीर में पिछले कुछ समय से, बाहरी राज्यों से गए मजदूरों पर, लक्षित आतंकी हमलों का जो दौर शुरू हुआ है और उसमें जैसी निरंतरता देखी जा रही है, वह अब सरकार और वहां तैनात सुरक्षा बलों के लिए एक जटिल चुनौती बन रही है। गौरतलब है कि शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में एक प्रवासी मजदूर का शव मिला था। रोजी-रोटी की तलाश में बिहार से वहां गए मजदूर को दो गोलियां मारी गई थीं। अनुमान है कि दहशतगर्दों ने लक्षित हमले की अपनी रणनीति के तहत उस मजदूर की हत्या कर दी। यों, यह कोई पहली घटना नहीं है, मगर सच यह है कि हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों के शिविरों से लेकर प्रवासी मजदूरों तक के घरों पर हमला करने के पीछे उनकी हताशा दिखती है। हालांकि आतंकवादी गिरोहों से किसी तरह के विवेक की उम्मीद करना बेमानी है, मगर हैरानी की बात यह है कि बेहद कमजोर तबके के ऐसे लोगों को भी मार डालने में वे नहीं हिचकते, जो महज रोजी-रोटी की उम्मीद में अपनी जमीन से उखड़ कर वहां पहुंचे होते हैं।

जम्मू-कश्मीर में लक्षित हमलों के रूप में आतंकी हमलों की यह नई प्रकृति है, जिसमें आतंक का दायरा फैल रहा है। निश्चित रूप से यह चिंता की बात है और सुरक्षा बलों के साथ सरकार को आतंकवाद के इस नए चेहरे से निपटने के लिए अलग रणनीति पर काम करने की जरूरत है। इस समस्या के जटिल होते जाने की मुख्य वजह यह रही है कि इसके तार सीमा पार के ठिकानों से संचालित संगठनों से जुड़े हैं। वहीं से मिलने वाले संरक्षण और पोषण का नतीजा है कि कभी सुरक्षा बलों के शिविर पर हमला करके, तो कभी किसी प्रवासी मजदूर की हत्या कर आतंकी अपनी मौजूदगी दर्शाना चाहते हैं। हाल में हुए विधानसभा चुनावों के बाद वहां एक चुनी हुई सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है और उसके बाद यह स्वाभाविक उम्मीद जगी है कि वह अपनी सीमा में आतंकवाद और खासतौर पर लक्षित हमलों पर काबू पाने के मामले में सख्त कदम उठाएगी। यही उसकी कसौटी भी है कि इस दिशा में वह क्या कर पाती है।

तरक्की की मीनारें और गुरबत के दाग

देश ने पचहत्तर वर्ष की आजादी मना ली। अब शतकीय महोत्सव मनाने की ओर बढ़ रहा है। संकल्प है कि विकसित भारत में खुशहाली के सूचकांकों की नई ऊंचाइयों को छुआ जाएगा, लेकिन यहां विरोधाभास नजर आ रहा है।

सुरेश सेठ

यह अजब विरोधाभास है कि ज्यों-ज्यों किसी देश में आर्थिक प्रगति होती है, त्यों-त्यों वहां अमीर और अमीर होते चले जाते हैं तथा गरीब और गरीब। यह विरोधाभास सशक्त पश्चिमी देशों में देखने को मिलता है। तीसरी दुनिया के देशों में भी देखने को मिलता है। जहां तक भारत का संबंध है, यह विरोधाभास इस हद तक पहुंच गया है कि हम कहते हैं कि भारत एक अमीर देश है, जिसमें गरीब बसते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार से ऊपर कोई और पुरस्कार या सम्मान नहीं माना जाता। अलग-अलग पांच विधाओं में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें से एक विधा है साहित्य। साहित्य जीवन के कितना नजदीक है, यह बात इस बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीन अर्थशास्त्रियों- डारोन एसेमोग्लू, साइमन जानसन और जेम्स ए रोबिन्सन के शोध प्रबंधों से सामने आती है। इन शोध प्रबंधों में आर्थिक तरक्की के साथ-साथ गरीबी और अमीरी के भेद के मिटते जाने के कारणों की विशद चर्चा की गई है। स्पष्ट है कि इस चर्चा का समाधान भी यही शोध प्रबंध दे रहे हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसमें काम करती हुई विभिन्न संस्थाओं के सुधार के साथ ही गरीब और अमीर का भेद मिट जाएगा।

जहां तक दुनिया में शासन का संबंध है, अमीर देशों ने जिन देशों को सैन्य बल से और अब अपने आर्थिक बल से अपना उपनिवेश बना रखा है, वहां की तरक्की का अध्ययन करते हुए यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अगर एक स्वस्थ दृष्टिकोण से चलाया जाए, तो गरीबी और अमीरी का भेद अपने आप खत्म हो जाएगा। चाहे इन उपनिवेशों ने शुरू में थोड़ी बहुत तरक्की दिखाई, लेकिन बाद में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक व्यवहार पर सत्तारूढ़ दल की वर्चस्ववादी नीतियों के कारण ये देश पिछड़ेपन और गरीबी के रसातल में डूब गए। नोबेल से सम्मानित अर्थशास्त्रियों की यह त्रयी बताती है कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका और मैक्सिको का लंबा सीमांत देखा जा सकता है। एक गांव ले लीजिए- नोगल्स, जो मैक्सिको में है और पिछड़ेपन के रसातल में डूबा है। सीमा पार होते ही अमेरिका है, जो तरक्की और खुशहाली की मंजिलें तय कर रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भूगोल या संस्कृति किसी इलाके की आर्थिक संपन्नता या विपन्नता तय नहीं करती, बल्कि वे संस्थान तय करते हैं, जिनके अधीन उस देश के नागरिक जी रहे हैं। अमेरिका में स्थिति बेहतर मिली, क्योंकि वहां अमेरिकियों को अपनी शिक्षा और पेशा चुनने की पूरी स्वतंत्रता थी और अमेरिका का प्रजातांत्रिक ढांचा उन्हें राजनीतिक अधिकार और स्वतंत्रता दे रहा था।

नोबेल पुरस्कार विजेता इसी प्रश्न से जूझते और बताते हैं कि अपना देश चूंकि सैकड़ों वर्ष तक गुलामी की चक्की में पिसता रहा, और यहां आई विदेशी सत्ता यानी इंग्लैंड ने इस प्रकार की नीतियों का पालन किया, जिसमें हमारी संपदा का शोषण अधिक था, लेकिन देश के प्राकृतिक साधनों, श्रमशक्ति और निवेश उद्यम को सही दिशा देकर विकास का

माहौल नहीं बनाया गया था। यही कारण रहा कि जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय हम पिछड़ेपन के कगार पर थे। भारत सरकार ने वर्ष 1951 में इसी पिछड़ेपन के अभिशाप को दूर करने के लिए योजनाबद्ध आर्थिक विकास का संकल्प लिया। इस संकल्प में निहित था

> **आपाधापी के इस माहौल में आदर्शों की बात करना जैसे गुनाह हो गया है। संस्थाओं की मुंहजोरी के कारण भ्रष्टाचार नए शिखर को छू रहा है और महंगाई दस बार रेपो रेट न बदलने के बावजूद नियंत्रण में नहीं आ रही। देश के करोड़ों नौजवान बेकार हैं और उन्हें मनरेगा की आंशिक रोजगारी से बहलाया नहीं जा सकता। ऐसी हालत में सवाल यह है कि क्या संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना पहला कदम नहीं होना चाहिए। तीनों नोबेल विजेता भी यही कहते हैं कि औपनिवेशिक अधिनायकवाद की जगह अगर प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के साथ देश चलेगा, तो लोगों को अपना काम करने या उसका प्रशिक्षण लेने की अपेक्षाकृत आजादी रहेगी।**

कि शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपनी मेहनत के साथ बुनियादी ढांचे को इस प्रकार विकसित किया जाएगा कि देश में एक समावेशी माहौल बनाया जा सके। अमीर और गरीब दो अलग-अलग खाइयों में बंटते नजर न आएं, बल्कि विकास पथ के सहयात्री बन कर देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकें। मगर ऐसा नहीं हुआ।

देश ने पचहत्तर वर्ष की आजादी मना ली। अब शतकीय महोत्सव मनाने की ओर बढ़ रहा है। हमारा संकल्प है कि विकसित भारत में खुशहाली के सूचकांकों की नई ऊंचाइयों को छुआ जाएगा, लेकिन यहां भी विरोधाभास स्पष्ट नजर आ रहा है। एक ओर सरकार कहती है कि देश ने अभूतपूर्व तरक्की की है और वह दुनिया में पांचवीं आर्थिक शक्ति बन गया है। यही नहीं, दो-तीन वर्ष में भारत का संकल्प तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने का है और कर्तव्य पथ पर चलते हुए, जब यह देश आजादी का शतकीय महोत्सव मनाएगा, तो यह पूरी तरह से विकसित होगा। मगर जब देश के यथार्थ की ओर देखते हैं, तो यह दावा दिवास्वप्न लगता है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में तरक्की हुई है। चुनिंदा धनपतियों की संख्या इस प्रकार बढ़ी है कि उनका देश की प्राकृतिक और भौतिक संपदा के 90 फीसद हिस्से पर कब्जा हो गया है। वहीं देश की अधिकांश आबादी, जो वंचितों और गरीबों की है, वह केवल दस फीसद संपदा पर जीने के लिए अभिशप्त है। इसके कारण संविधान में रखा गया प्रजातांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य कहीं भी पूरा होता नजर नहीं आता। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्रियों के शोध को पढ़ें, तो कारण साफ नजर आता है कि अपना देश प्रजातांत्रिक अवश्य है, लेकिन यहां व्यवस्था कितनी जर्जर और नकारात्मक हो गई है कि आम लोग अपने जीवन मूल्य को बदलते नजर आ रहे हैं। हालत यह हो गई है कि एशिया में सर्वाधिक खरबपति अगर भारत में हैं, तो भूख से मरते लोगों की संख्या भी अभी आए वैश्विक भुखमरी सूचकांक के अनुसार मध्यवर्ग के देशों से भी कहीं पीछे है।

आपाधापी के इस माहौल में आदर्शों की बात करना जैसे गुनाह हो गया है। संस्थाओं की मुंहजोरी के कारण भ्रष्टाचार नए शिखर को छू रहा है और महंगाई दस बार रेपो रेट न बदलने के बावजूद नियंत्रण में नहीं आ रही। देश के करोड़ों नौजवान बेकार हैं और उन्हें मनरेगा की आंशिक रोजगारी से बहलाया नहीं जा सकता। ऐसी हालत में सवाल यह है कि क्या संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना पहला कदम नहीं होना चाहिए। तीनों नोबेल विजेता भी यही कहते हैं कि औपनिवेशिक अधिनायकवाद की जगह अगर प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के साथ देश चलेगा, तो लोगों को अपना काम करने या उसका प्रशिक्षण लेने की अपेक्षाकृत आजादी रहेगी। यह आजादी ही हमारे दीर्घकालिक विकास की नींव रखेगी।

निस्संदेह सरकार देश के लिए बहुत बड़े-बड़े सपने बना कर जनता जनार्दन को भेंट करती है, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए स्वस्थ और दोष रहित प्रशासन, शैक्षणिक ढांचे और सामाजिक कदाचार में बेहतरी की निरंतर उम्मीद चाहिए। देश में ऐसा नहीं हो रहा। प्रजातांत्रिक ढांचे के बावजूद हम सड़क पर चलते औसत आदमी की बेहतरी के लिहाज से पिछड़ रहे हैं। इसलिए एक स्वस्थ और दोषरहित प्रजातंत्र की कल्पना इस वर्ष के नोबेल विजेताओं ने की है और इसी का सपना भारत के लोग भी दिन-रात देखते हैं। अब अकादमिक शोध का समर्थन मिल जाने से उन्हें बल मिला है।

उदासी चुंबकीय है

दुनिया मेरे आगे

द्विवंकल तोमर सिंह

दुख एक ज्वार की तरह जीवन में आता है, जिसमें मन का सारा उल्लास टूटे तिनकों की तरह बह जाता है। उदासी मन पर कितने दिन हावी रहेगी, यह दो बातों पर निर्भर करता है। एक दुख की तीव्रता क्या है, दूसरा इससे बाहर निकलने के लिए कोई कितना प्रयास करता है। दोनों ही बातों में समय लगता है, जैसे कि कोई भी फल स्वाभाविक रूप से पकता है। कहा जाता है कि समय कैसा भी हो, एक अध्यापक की तरह हमेशा कुछ न कुछ पाठ पढ़ा ही जाता है। दुख अगर उदासी के पारावार में डूबो दे रहा है, तो गहराई के दर्शन भी करा देता है। गंभीर और उदास लोगों ने जीवन को जितनी अच्छी तरह से समझा है, उतना खुद में मग्न और सुखी व्यक्तियों ने कभी नहीं।

जीवन मात्र सुख और भोगों में डूबा देने के लिए नहीं है। कोलाहल से तनिक परे हटकर, मेले से थोड़ी दूरी बना कर इस जीवन की सार्थकता या निरर्थकता पर विचार करने का सामर्थ्य उदास लोगों के जिम्मे आ गया। यह अपने आप में एक विशिष्ट गुण है। रास-रंग में डूबा रहने वाला व्यक्ति कभी दार्शनिक नहीं होता। उदास लोगों के चेहरे पर गंभीरता का सौंदर्य दमकने लगता है। उदास आंखों में जितनी गहराई होती है, उतनी कहीं भी नहीं।

उदास लोगों के पास प्रफुल्लित लोगों की तुलना में बहुत कुछ होता है, जो सुंदर है, प्रेरणादायक है और चुंबकीय है। उदास लोगों के मन में एक विशेष प्रकार की गंभीरता पकने लगती है। वे मौके-बेमौके अनावश्यक बोलना पसंद नहीं करते। वे निष्प्रयोजन वृथा बात कभी नहीं कहते। उनकी ऊर्जा एक विशेष चिंतन प्रवाह की ओर चलायमान होने लगती है। उदास व्यक्तियों को मौन रहना, अपने दुख के साथ रहना, शोक मनाते रहना पसंद होता है। वे अपने आसपास की भीड़ को देखकर मनन करते रहते हैं कि ये इतने प्रसन्न क्यों हैं! सभी धारा के साथ एक दिशा में बहते जा रहे हों, जिनके लिए प्रसन्नता के मानक एक समान हों, उनमें कोई ऐसा हो जो धारा के विपरीत सोच सके। ऐसे लोगों में एक विरक्ति का भाव उपजने लगता है, उनका चिंतन गहराने लगता है।

हालांकि उदासी की अपेक्षा कोई नहीं करता। करना भी नहीं चाहिए। यह कोई उचित और आकर्षक ठहराने वाली परिस्थिति नहीं है कि दुख या उदासी कोई महान चीज है। मगर एक भाव जरूर है, जो व्यक्तित्व को, जीवन को प्रभावित करता है। दरअसल, दुख उदासी लाता है तो अंतर्मुखी भी बना देता है। यह दुख का सबसे बड़ा उपहार है। दुनिया में जितने भी विचारक या दार्शनिक हुए हैं, वे सब अंतर्मुखी रहे हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात बचपन से ही गंभीर थे। वे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना नहीं, बल्कि उन्हें चुपचाप देखना, उनके क्रिया-कलापों को दूर से निरीक्षण करना पसंद करते थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही है, 'कभी-कभी आप दीवारें दूसरों को दूर रखने के लिए खड़ी नहीं करते, बल्कि इसलिए खड़ी करते हैं कि आप यह देखना चाहते हैं कि इन्हें कौन तोड़ने की कोशिश करता है।' अंतर्मुखी होना कुछ यों है कि नीरवता में प्रकृति की झांझर सुनने का प्रयास करना।

एक बहुत सुंदर कहावत है कि टूटे हुए लोगों ने दुनिया को सबसे अधिक सुंदर बनाने का प्रयास किया है। इसका एक विशेष कारण भी है। टूटे हुए लोगों के हृदय में करुणा के अंकुर फूट पड़ते हैं। उन्हें अपने जैसे दुखी लोगों के साथ एक बंधुत्व का अनुभव होता है। साझा दुख से बढ़कर आसंजक कुछ भी नहीं। सुख स्वार्थी बना सकता है, दुख निस्वार्थ होने की ओर प्रेरित करता है। जो प्रफुल्लित है, सुखी है, स्वयं में मगन है, उसके पास दूसरों का दुख देखने का समय कहां? और अगर देख भी लिया तो उसकी तीव्रता अनुभव करने लायक संवेदना कहां? जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। करुणा एक शक्तिशाली संवेदना है, जो यह भाव देती है कि जैसे मैं दुखी रहा, वैसे दूसरों को दुखी नहीं रहने दूंगा। यह हृदय में सेवा की इच्छा को पल्लवित करती है।

> **सुख स्वार्थी बना सकता है, दुख निस्वार्थ होने की ओर प्रेरित करता है। जो प्रफुल्लित है, सुखी है, स्वयं में मगन है, उसके पास दूसरों का दुख देखने का समय कहां? और अगर देख भी लिया तो उसकी तीव्रता अनुभव करने लायक संवेदना कहां? जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई।**

उदास लोगों के पास एक विचित्र प्रकार का चुंबकत्व आ जाता है। उनकी गंभीरता आकर्षित करती है। उनका चिंतन प्रवाह दार्शनिक हो जाता है, जिसमें गोते लगाने से कुछ बेहद संघनित तात्त्विक दर्शन के मोती प्राप्त हो जाते हैं। हम अगर ऐसे लोगों के साथ थोड़ी देर बैठेंगे, तो पाएंगे कि जाने कितने घंटों के घोर चिंतन के बाद जो नवनीत उनके पास इकट्ठा हुआ है, वह कितना समृद्ध है, मूल्यवान है। उनके शब्दों के अर्थ कितने गहरे होते हैं। उनके जीवन के अनुभव का सारा रस उनकी वाणी को सराबोर कर देता है।

यहां यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि जिन लोगों ने दुख सहा, उससे लड़ाई लड़ी, ईश्वर से दुखी होकर प्रश्न पूछे, स्वयं ही उत्तर खोजने की दिशा में चल दिए, वे उदास थे, दुख को समझने की चुनौती उठाने वाले लोग थे, अवसादी या मानसिक रोगी नहीं। अगर अवसाद या निराशा उनके जीवन में आई होगी तो उन्हें कमजोर नहीं बना सकी होगी। थोड़े दिनों में उन्हें इन बादलों के पार देखना पड़ा होगा। दुख तोड़ देता है तो हताशा जन्म लेती है, यहीं दुख कुछ लोगों के जीवन में एक फीनिक्स पक्षी की तरह आता है, वे शून्य पर सिमट जाएं तो भी पुनर्जीवित होते हैं, और अच्छे से लड़ाई लड़ने के लिए, दुनिया को कुछ देकर जाने के लिए। प्रसिद्ध विचारक विक्टर ह्यूगो ने एक सुंदर बात कही है- 'मेलनकली इज द हैप्पीनेस आफ बीइंग सैड।' मतलब उदासी दुखी होने का सुख है।

संवाद के मायने

हाल ही में हुई शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखा। यह बैठक की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा था, लेकिन इससे ज्यादा अहम बात यह थी कि जयशंकर पाकिस्तान में थे। पाकिस्तानी नागरिक उनके आने से बहुत उत्साहित थे। उन्हें लग रहा था कि शायद भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू हो सकती है। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि इस यात्रा में भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय मुद्दों पर कोई बात नहीं होगी। फिर भी, पाकिस्तानी इसे नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बातचीत का एक मौका मान रहे थे। इस संदर्भ में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान के आम लोगों में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू करने की इच्छा बढ़ रही है। भले ही पाकिस्तान के शासक इस मुद्दे पर कुछ भी सोचें, लेकिन आम लोग बातचीत के पक्ष में दिखाई देते हैं। हो सकता है कि लोगों की यह इच्छा पूरी न हो, लेकिन यह अच्छी बात है कि पाकिस्तान के नागरिक भारत से वार्ता के लिए दबाव बना रहे हैं। वे भारत के साथ व्यापार शुरू करके अपने देश की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं।

– वंदन कुमार नाथ, बारपेटा, असम

साइबर जाल

साइबर अपराध का बढ़ता दायरा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती है। आजकल सोशल मीडिया मंच के जरिए विमान में बम रखे जाने की झूठी खबर देकर लोगों को भयभीत किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई विमानों में बम रखे जाने की झूठी सूचनाएं देकर विमानन कंपनियों, यात्रियों और सुरक्षा एजंसियों के सामने संकट पैदा किया जा रहा है। किसी भी तरह की सूचना मिलने के बाद विमान को पास के हवाईअड्डे पर उतार कर उसकी सघन जांच की जाती है। इस प्रक्रिया से यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में देरी होती है। वहीं यात्रियों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। लिहाजा झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने की जरूरत है। फर्जी ई-मेल आइडी और अन्य सोशल नेटवर्किंग आइडी के जरिए सूचना भेजना सामान्य बात हो चुकी है। आज भी कई स्थानों पर बिना पूरी जांच के सिम कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। साइबर अपराध को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए।

– हिमांशु शेखर, गया

दवा के जोखिम

आजकल छोटी-मोटी बीमारियों में गोलियों की जरूरत आम बात है। कई लोग बहुत सी बीमारियों का इलाज अपनी समझ और अनुभव के आधार पर कर लेते हैं। आज दवा बाजार में नकली दवाइयां जानलेवा साबित हो सकती हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक या लगातार सेवन से जो रपट सामने आई है, वह चिंताजनक है। रपट के अनुसार शरीर में रोगाणु एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति लगातार प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर रहे हैं। इससे दवाओं का असर क्षीण होता जा रहा है। आइसीएमआर के अध्ययन में आई इस जानकारी के बाद लोगों को अपने रोग और उनके इलाज के प्रति सतर्क हो जाना चाहिए। वैसे बीमारियों की वजह अनियमित दिनचर्या भी है जो आजकल सुविधाभोगी लोगों में अधिक नजर आती है। नियमित व्यायाम या खुद काम करने की क्षमता को नकारने से भी शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता गंवा बैठता है और फिर उसे एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत पड़ती है। अच्छा हो कि लोग शारीरिक परिश्रम करें।

– अमृतलाल मारू 'रवि' इंदौर

दांव पर रिश्ता

आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने और भारत में नियुक्त कनाडा के छह राजनयिकों के निष्कासन की कार्रवाई से स्पष्ट हो गया है कि भारत को उदारता को कायरता समझने की भूल टूडो को वैश्विक स्तर पर भरी पड़ने जा रही है। भारत ने कितनी कुर्बानियों से पंजाब के अलगाववादी आंदोलन पर काबू पाया, कनाडा समेत पश्चिम के तमाम देश वाकिफ हैं। विडंबना देखिए कि कनाडा ने एक आतंकी के लिए भारत को बदनाम करने की कोशिश की। मगर ट्रूडो को कौन समझाए कि जिस आतंकी के लिए वे रिश्तों को दांव पर लगा रहे हैं, उसके सिर पर भारत सरकार ने इनाम घोषित कर रखा था। अब तक भारत ने थ्रीज का परिचय दिया है, क्योंकि कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो अपने यहां चुनाव के कारण गंदी राजनीति कर रहे हैं।

– हर्षवर्द्धन, पटना

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

सम्पादकीय

क्वांटम तकनीक पर तेजी से बढ़ने की जरूरत

इस वर्ष 13 अगस्त का दिन क्वांटम तकनीक (टेक्नोलॉजी) के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय मानक एवं तकनीक संस्थान (एनआईएसटी) ने पहले तीन पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (पीक्यूसी) मानकों की घोषणा की। पीक्यूसी वह तकनीक है, जिसमें अल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है और अहम जानकारी (डेटा) को अनधिकृत इस्तेमाल से बचाया जाता है। इन मानकों की घोषणा के बाद दुनिया भर के प्रतिष्ठानों में इस तकनीक के इस्तेमाल का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब यह चिंता काफी हद तक दूर हो सकती है कि क्वांटम कंप्यूटरों के जरिये मौजूदा सुरक्षा उपायों (इन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल) को तोड़ न दिया जाए और पूरा साइबर तंत्र खतरे में न पड़ जाए। आज हम जिस डिजिटल दुनिया को देख रहे हैं, उसमें क्वांटम तकनीक भारी उथल-पुथल लाने वाली है। डिजिटल नवाचार के जरिये पिछले पांच दशकों में तेज बदलाव देखने के बाद अब हम क्वांटम तकनीक की मदद से और भी तेज बदलाव के साक्षी बन रहे हैं। बड़े बदलाव लाने की क्षमता वाली क्वांटम तकनीक उद्योग, अर्थतंत्र और सुरक्षा को अभूतपूर्व तेजी के साथ नई शक्ल देगी। इसलिए यह वैश्विक तकनीकी होड़ का केंद्र बन गई है और दुनिया के प्रमुख देश क्रांति लाने वाले इस क्षेत्र में वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। इस समय दो प्रमुख तकनीकी रुझान हैं, पीक्यूसी और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (क्यूकेडी)। पीक्यूसी में क्रिप्टोग्राफ वाले अल्गोरिदम तैयार किए जाते हैं, जिन पर क्वांटम हमलों का असर ही नहीं होता। मगर क्यूकेडी सुरक्षा उपाय मुहैया करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करती है। इस बात पर एक राय नहीं है कि आगे जाकर दोनों में किसका वर्चस्व होगा। दुनिया दो खेमों में बंट गई है: अमेरिका पीक्यूसी का हिमायती है मगर चीन और रूस क्यूकेडी पर दांव लगा रहे हैं। नवंबर 2023 में अमेरिका ने पहल करते हुए अपनी सभी संघीय एजेंसियों को सुरक्षा के लिए पीक्यूसी के इस्तेमाल का निर्देश दिया, जिसके बाद पीक्यूसी मानकों के विकास में तेजी आ गई। एनआईएसटी 2016 से इन मानकों पर काम कर रहा था और कुछ ही महीनों में उसने इन्हें तैयार कर दिया। इस बीच रूस और चीन क्यूकेडी में आगे निकल रहे हैं। चीन ने 2017 में पेइचिंग और शांघाई के बीच 2,000 किलोमीटर लंबा क्यूकेडी-सिक्योर्ड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तैयार कर लिया जिसमें एक हॉप लगभग 100 किलोमीटर का था। हॉप संदेश (डेटा) भेजने वाले और इसे प्राप्त करने वाले पक्षों के बीच नेटवर्क पथ का एक हिस्सा होता है। भारत ने 2019 में 130 किलोमीटर का सिंगल-हॉप क्यूकेडी तैयार कर लिया। मगर जनवरी 2024 में चीन और रूस ने उपग्रह से जोड़कर क्यूकेडी तैयार किया, जिसने एक दूसरे से लगभग 3,800 किलोमीटर दूर स्थित मॉस्को और उरुमकी को जोड़ दिया। भारत क्वांटम तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप इकाइयां ऐसी तकनीक लग रही हैं, जो अमेरिकी और चीनी तकनीक को भी चुनौती देती है। भारतीय स्टार्टअप इकाइयों ने एनआईएसटी के अनुकूल पीक्यूसी तकनीक तैयार की हैं और 200 किलोमीटर सिंगल-हॉप सिस्टम सहित फाइबर के जरिये क्यूकेडी भी तैयार कर लिया है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट से निजात के लिए कुशल और विश्वसनीय तकनीकों की आवश्यकता

मिलावट करने से कोई भी उत्पाद आकर्षक व सुंदर तो दिखने लगता है, परंतु उसकी पोषकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।खाद्य अपमिश्रण से आंखों की रोशनी जाना, हृदय संबन्धित रोग, लीवर खराब होना, कुष्ठ रोग, आहार तंत्र के विभिन्न रोग, पक्षाघात व कैंसर जैसे खतरनाक व भयंकर रोग हो सकते हैं। आज के समय में अनेक स्वार्थी उत्पादक एवं व्यापारी कम समय में अधिक लाभ कमाने के लिए खाद्य सामग्री में अनेक सस्ते अवयवों की मिलावट करते हैं, जो हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं।

सुनील कुमार महला

पहले शारदीय नवरात्र, उसके बाद विजयादशमी और अब दीपावली, अक्टूबर-नवंबर के महीने भारत में त्योहारी महीने होते हैं। वर्तमान में दीपावली का त्योहार नजदीक है और दीपावली के अवसर पर आजकल खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसे आम हो गई है। दीपावली के त्योहार पर दूध,पनीर,मावा, खाद्य तेल, मसालों,घी, शहद और विशेषकर मिठाईयों में मिलावट की सबसे ज्यादा आशंका बनी रहती है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर यह मिलावट होती क्या है ? दरअसल, खाद्य पदार्थों में मिलावट से तात्पर्य जानबूझकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को खराब करने के कृत्य से है, जिसमें या तो खाद्य पदार्थों में अपेक्षित वैकल्पिक घटकों को मिलाया जाता है या प्रतिस्थापित किया जाता है, या कुछ मूल्यवान घटकों को हटा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में यह बात कही जा सकती है कि खाद्य अपमिश्रण का तात्पर्य खाद्य पदार्थों में अपेक्षित वैकल्पिक घटकों को जोड़कर या बदलकर या कुछ मूल्यवान घटकों को हटाकर जानबूझकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को खराब करने के कार्य से है। यह आमतौर पर किसी दिए गए खाद्य उत्पाद की लागत कम करने या उसका थोक बढ़ाने के लिए किया जाता है। दीपावली का त्योहार हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है और दीपावली पर हर परिवार कुछ न कुछ खरीदारी अवश्य ही करता है और मिलावट के फेर में आसानी से फंस जाता है। यह बहुत ही दुखद है कि आज बाजार में अमानक, अपमिश्रित मिलावटी, स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही हानिकारक खाद्य पदार्थ धड़ल्ले से बिकते हैं। सच तो यह है कि दालें, अनाज से लेकर सब्जी व फल तक कोई भी खाद्य पदार्थ आज मिलावट से अछूते नहीं रहे हैं। हर तरफ मिलावट का जहर है। वास्तव में खाद्य अपमिश्रण, मिलावट से किसी भी उत्पाद/प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता काफी कम हो जाती है और वह स्वास्थ्य को बहुत नुक्सान पहुंचाते हैं, विशेषकर खाद्य पदार्थों में सस्ते रंजक, रासायनिक पदार्थ इत्यादि। सच तो यह है कि व्यापार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण मिलावट आज हर जगह देखने को मिलती है। कहीं दूध में पानी की मिलावट होती है, तो कहीं मसालों में रंगों की मिलावट होती है। यहां तक कि सब्जियों व फल भी रसायनों के प्रयोग से पकाये जाते हैं, नेचुरल सब्जियां व फल तो जैसे बाजार में अब रहे ही नहीं हैं, डिमांड भी बढ़ती जनसंख्या के कारण कुछ ज्यादा ही है, आपूर्ति करना कोई हंसी-खेल नहीं है। जानकारी देना चाहूंगा कि आज कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम साइक्लामेट, साइनाइड और फार्मोलिन जैसे खतरनाक रसायनों का व्यापक रूप से हरे उष्णकटिबंधीय फलों को पकाने, उन्हें ताजा रखने और बिक्री तक संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। बहरहाल, जानकारी देना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा खाद्य सामग्री की मिलावट की रोकथाम तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध आहार उपलब्ध कराने के लिए सन् 1954 में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम (पीएफए एक्ट 1954) लागू किया गया था। वास्तव में,

उपभोक्ताओं के लिए शुद्ध खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अहम् जिम्मेदारी है। भारत सरकार द्वारा 1954 में जो खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम बनाया गया, उसके मुख्य उद्देश्यों में क्रमशः जहरीले एवं हानिकारक खाद्य पदार्थों से जनता की रक्षा करना, घटिया खाद्य पदार्थों की बिक्री की रोकथाम करना तथा धोखाधड़ी प्रथा को नष्ट करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना को शामिल किया गया है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि जिला स्तर पर जिला प्रशासन व खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम आमजन को मिलावटी खाद्य पदार्थों से निजात दिलाने के लिए समय समय पर अभियान नहीं चलाती है, लेकिन मिलावट करने वाले राजनेताओं, रसूखदार लोगों, प्रशासन से मिलीभगत करके किसी न किसी बहाने से पुलिस की गिरफ्त से छूट जाते हैं और मिलावट का धंधा ज्यों का त्यों चलता रहता है और आमजन इसका शिकार बन जाता है और यही कारण है कि इस आशय की खबरें आये दिन अखबार व मीडिया की सुर्खियों में पढ़ने को मिलती रहती हैं। यहां पाठकों को यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि खाद्य अपमिश्रण के परीक्षण के लिए मैसूर, पुणे, गाजियाबाद एवं कोलकाता में भारत सरकार द्वारा चार केन्द्रीय प्रयोगशालाएं व्यवस्थित रूप से स्थापित की गई हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए इन केन्द्रीय प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार के खाद्य निरीक्षक, भोज्य पदार्थों के नमूने को सरकारी/लोक विश्लेषक के पास भेजते हैं। आज खाद्यान्न गुड़, दालें, मसालों में कंकड़, पत्थर, मिट्टी,रेत, लकड़ी का बुरादा , सरसों के तेल में आर्जीमोन तेल, चना/अरहर की दाल/बेसन में खेसरी दाल, बेसन और हल्दी में पीला रंग/मेटानिल, बादाम के तेल में मिनरल तेल, दालों में टेलकम पाउडर या एस्बेस्टस पाउडर, लाल मिर्च में रोडामाइन बी, हल्दी में लेड क्रोमेट/सिंदूर पेय पदार्थों में निषिद्ध रंग व रंजक, चांदी की वर्क के स्थान पर एलयुमिनियम की वर्क, चायपत्ती व काफी में लीह चूर्ण या रंग मिलाया जाना आम है। कुछ समय पहले ब्रांडेड मसालों में भी विभिन्न रसायनों की मात्रा जरूरत से ज्यादा पाई गई थी। आज दूध में सबसे ज्यादा मिलावट देखने को मिलती है क्यों कि दूध में पानी, स्टार्च, वाशिंग पाउडर, यूरिया तक मिलाया जाता है। केसर आज मिलावटी आती है। कालीमिर्च में पपीते के सूखे बीजों को मिलाया जाता है। साधारण नमक में चाक पाउडर, हींग में मिट्टी व रेत, नारियल तेल में खनिज तेल, जीरा में घास के बीज, चीनी के बूरे में चाक पाउडर, यहां तक कि चावलों तक में मिलावट का जहर घुला रहता है। जानकारी देना चाहूंगा कि चावल में प्लास्टि?क और आलू से बने नकली चावलों की मिलावट होती है। लाल मिर्च में तो मिलावट के तौर पर ईंट या कबेलू का बारीक पिसा हुआ पाउडर प्रयोग किया जाता है, जिसमें कृत्रिम रंग भी मिला हुआ होता है। दालचीनी में मि?लावट के तौर पर अमरूद की छाल मिलाई जाती है।सरसों के दानों या राई में भी इसी प्रकार अर्जेमोने के बीज मिलाकर वजन को बढ़ाया जाता है।हरे मटर के दानों को अत्यधिक हरा दिखाने के लिए इसमें मेलाकाइट ग्रीन को मिलाया जाता है।धाय पत्ती में चमड़े की कतरन मिलाई जाती है। धनिया पाउडर में भूसा के साथ हरा रंग, घोड़े की लीद आदि मिला हो सकता है।दालों में मिलावट की बात की जाए तो इनकी चमक बढ़ाने के लिए दुकानदार पॉलिश कर देते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। यह विडंबना ही है कि अब तो रसायनों का प्रयोग करके सिंथेटिक दूध, घी, खोया तथा अन्य खाद्य पदार्थ तैयार किये जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक होते हैं। वास्तव में,भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण आए दिन लोगों को अलग-अलग चीजों में मिलावट की पहचानने के तरीका बताता है, ऐसे में हमें यह चाहिए कि हम इन्हें ध्यान में रखें और हमेशा जागरूक व सतर्क रहें और मिलावटखोरों को पुलिस को पकड़वायें, उनकी शिकायत करें और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवायें। अंत में यही कहूंगा कि मिलावट न केवल एक काफी आर्थिक समस्या है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विधि तरीके को पूरा करेंगे। कब आप यह समझ पाते हैं कि आपके जीवन के ऐसे मौसम हैं, जब आपके जिंदगी कुछ लोग और तुम्हारी तरह, अपनी दिल बातें में लगातार तरक्की होगा। एक ने किसी तरह की और और कुछ को तुम्हारे साथ स्वतंत्रता उन्हें जो साकुछ करेंगे, सकेंगे परेशानियां लोगों में भी, जब तक लगातारता नहीं लोग और कामों में लाभ उठाना होगा

मेष
रोमांस के लिए आज अनुकूल दिन है। आज का हर कार्य आप दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास से पूरा करेंगे। प्रवास-पर्यटन की संभावनाएं हैं। अच्छा भोजन और नए वस्त्र मिलने का अवसर मिल सकता है। भागीदारी से लाभ होगा।

वृष
आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। व्यापार स्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा। उच्च अधिकारी आप पर प्रसन्न रहेंगे। आप का हर काम आज सफलता से पूरा होगा। नौकरी में पदोन्नति भी हो सकती है।

मिथुन
आज अचानक धन खर्च होने का योग है। यह खर्च स्वास्थ्य के कारण भी हो सकता है। व्यावहारिक या सामाजिक काम के लिए बाहर जाना हो सकता है। खान-पान में ध्यान रखें। क्रोध तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहें।

कर्क
मानसिक रूप से स्वस्थता का अनुभव नहीं करेंगे। निराशा और असंतोष की भावना से काम में मन नहीं लगेगा। कुटुंबजनों के साथ किसी विषय पर वाद-विवाद हो सकता है। विद्यार्थियों को अभ्यास का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा। व्यापार में बाधाएं उपस्थित होंगी।

सिंह
आप में आज आत्मविश्वास कूट-कूटकर भरा रहेगा। किसी भी काम को करने के लिए आप जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं। पिता तथा बड़ों की ओर से लाभ होगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। वाणी में उग्रता ना रखें।

कन्या
आपका आज का दिन शुभफलदायी है। कई क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। मित्रों से लाभ होगा और उनके पीछे धन खर्च भी हो सकता है। पर्यटन स्थल की सैर आपको रोमांचित करेगी। परिजनों से मुलाकात आनंददायी हो सकती है। वाहन सुख मिलेगा।

तुला
अधिकारियों से काम का उचित फल भी मिल सकता है। भाई-बंधुओं के साथ कोई झगड़ा दूर होगा। विचार लगातार परिवर्तन होते रहेंगे। आर्थिक विषय में सावधानी बरतनी आवश्यक है। नेगेटिव विचारों से मन परेशान रह सकता है।

वृश्चिक
सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। पेट दर्द से परेशानी हो सकती है। आज आप किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ करेंगे। उसमें सफलता भी प्राप्त भी करेंगे। पिता की ओर से आपको लाभ हो सकता है।

धनु
आज आपका स्वास्थ्य नरम-गरम रह सकता है। शारीरिक रूप से आलस्य और अशक्ति का अनुभव करेंगे। मन में चिंता रह सकती है। गलत कामों से दूरी बनाए रखें। किसी भी योजना को सावधानीपूर्वक करें।

मकर
विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। सरकारी कामों में आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है। संतान के लिए पूंजी निवेश करेंगे। नई योजना का आरंभ करने के लिए आज अनुकूल दिन है। सरकारी काम में लाभ होगा।

कुंभ
आपको उग्र स्वभाव पर संयम रखने की सलाह दी जाती है। आज आप मानसिकरूप से थकान का अनुभव करेंगे। अधिक परिश्रम की तुलना में कम फल की प्राप्ति होगी। संतान के विषय में आपको चिंता हो सकती है।

मीन
आज इगो के कारण किसी से बातचीत में मनमुटाव हो सकता है। मित्रों के साथ किसी बात विवाद हो सकता है। स्वभाव में आवेश और क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी। धार्मिक कामों में धन का खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यापार में बाधाएं उपस्थित होंगी।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं श्री उत्कल रंजन साहू जाकि राजस्थान पुलिस के मुखिया हैं। 20 जून सन 1964 को ओड़िसा में जन्में साहू साब बहुत बेहरीन अधिकारी माने जाते हैं। एम्बूकेशन ओड़िसा से ही हुई एमटेक इंजी० भूविज्ञान कर उन्होंने पुलिस सेवा जॉईन की। प्रशिक्षण के तहत एलबीएसएन, एनपीए, आरपीए रहे। उसके बाद सहायक एसपी, जोधपुर पूर्व रहे। कमांडेंट, 8वीं बटालियन, आरएसी, अगरतला। पुलिस अधीक्षक, धौलपुर। पुलिस अधीक्षक,बाड़मेर।पुलिस अधीक्षक,आरएसबीआई, जयपुर। पुलिस अधीक्षक,हनुमानगढ़। पुलिस अधीक्षक, सीकर। पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा। पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर। पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा। पुलिस अधीक्षक, जोधपुर (शहर)। पदोन्नत होकर डीआईजी बने और उपपुलिस महानिरीक्षक, एसीबी प० प्रभारी विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ, जयपुर लगाए गए। पदोन्नत होकर आईजी बने और पुलिस महानिरीक्षक, एसीबी.प० प्रभारी विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ, जयपुर लगाए गए। पुलिस महानिरीक्षक, कोटा रेंज, कोटा। पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, जयपुर। महानिरीक्षक पुलिस, नियम, राजस्थान, जयपुर। पुलिस महानिरीक्षक, योजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण, राजस्थान, जयपुर। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, इन्टेकलिजेन्स, राजस्थान, जयपुर। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, इन्टेलिजेन्स एवं मुख्यमंत्री सतर्कता एवं सुरक्षा, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आयोजना, आधुनिकीकरण और कल्याण, राजस्थान, जयपुर। महानिदेशक पुलिस, आयोजना, आधुनिकीकरण और कल्याण, राजस्थान, जयपुर। महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर। महानिदेशक एवं कमाण्डेन्ट जनरल, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर और अब राजस्थान पुलिस के मुखिया के रूप में डीजी पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। पुलिस कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी के रूप में लोग इन्हे जानते हैं। अच्छी व बेहतरीन पुलिस सेवा के लिए इन्हें अनेकों पुरूस्कारों से भी नवाजा गया है। एक दम सरल व सादगीपूर्ण तरीके से जीवन जीने वाले साहू साब बहुत ही बेहतरीन पुलिस अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

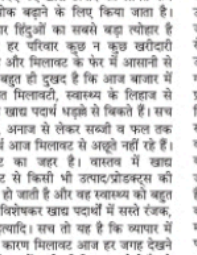

श्री उत्कल रंजन साहू
(आरआर-88)
(डी.जी.पी राजस्थान पुलिस)

रूपक शर्मा

विशेष आलेख

इजरायली पीएम के घर पर ड्रोन हमला, इजरायली डिफेंस फोर्स के सुरक्षा घेरे में सेंध से दुनियाँ हैरान

कर विशेषज्ञ स्तंभकार एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी,गोंदिया महाराष्ट्र

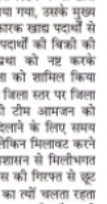

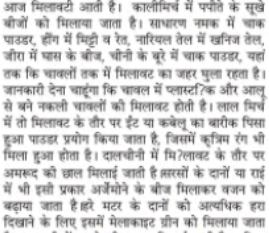

वैश्विक सरापर दुनियाँ दो खेमों में बंट चुकी है। इन देशों में अप्रत्यक्ष रूप से प्रॉक्सी वॉर शुरू है,इस बीच भारत कनाडा का टेंशन भी बढ़ा हुआ है, वहीं इस बिगड़ते माहौल व युद्ध के बीच 19 अक्टूबर 2024 को देर शाम इजरायल के प्रधानमंत्री के घर ड्रोन हमले की जानकारी डिजिटल मीडिया पर आग की तरह फैली जिसे देर रात्रि इजरायली पीएमओ कार्यालय व आईडीएफ ने भी कंफर्म किया व किसी जनहानि से इनकार किया। उधर इस कठिन माहौल के बीच रूस के कज़ान में 23 -25 अक्टूबर 2024 सेंब्रिक्स देशों का 16वीं शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है जिसकी तैयारियां जोर-जोर से की गई है। भारतीय पीएम भी 22-23 अक्टूबर 2024 को इस महासम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें संभावित वैश्विक जंग यानें वैश्विक युद्ध के दोनों आधार रूस-यूक्रेन व हमास-इजरायल युद्ध को रोकने के उपचार में भारतीय पीएम फिर ग्लोबल लीडर साबित हो सकते हैं।हालांकि अभी नए घटनाक्रमों के चलते इस बारे में कहा नहीं जा सकता। खैर इजरायली पीएम के घर पर ड्रोन हमले से इसराइल एफडीआई के सुरक्षा घेरे में सेंध से दुनियाँ हैरान है, इसलिए आज हम मीडिया में उल्लेख जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे।हिजबुल्लाह का याह्या सिनवर मौत पर पलाश इजरायली पीएम के घर ड्रोन हमला।रिएक्शन, तीसरे विश्व युद्ध का टेंशन।

साथियों बात अगर हम इजरायली पीएम के घर ड्रोन हमले की करें तो,लेबनानी गुट हिजबुल्लाह की ओर से शनिवार को निजी आवास पर ड्रोन हमले की कोशिश के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस ड्रोन अटैक के पीछे ईरान के एजेंट हिजबुल्लाह का मकसद उनको मारना था।उन्होंने दावा किया कि उनके साथ-साथ उनकी पत्नी की भी हत्या इस ड्रोन अटैक के जरिए करने की साजिश थी। उन्होंने इस अटैक के लिए ईरान के प्रॉक्सी और एजेंट्स को जिम्मेदार कहा है।ईरान पर लगाया हमले का आरोप,याह्या सिनवार की मौत और ड्रोन हमले ने इस युद्ध में एक नया मोड़ दिया है। इजरायल अब हमास और उससे जुड़े ईरानी एजेंटों से संघर्ष को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है।मसलन, इजरायली अधिकारी ने दावा किया कि हमले ईरान के इशारे पर किए गए थे, लेकिन इसके लिए इजरायल ने कोई सबूत पेश नहीं किया है।पीएम ऑफिस से आए एक बयान के मुताबिक, ईरान ने नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश की थी। यह घटना कारोलिराय में हुई,जो अपने शानदार विला और रोमन सभ्यता के अवशेषों के लिए मशहूर है।हडीएफ ने बताया कि ड्रोन लेबनान से लॉन्च किए गए थे और इस हमले के कारणों की जांच की जा रही है। ईरान की तरफ से फिलहाल इजरायल के आरोपों पर कुछ प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।हाला जा रहा है कि ड्रोन हमले के बीच लोगों को कोई हानि नहीं मिली। मसलन, इजरायल का सुरक्षा कवच (वार्निंग सिस्टम) आमतौर पर किसी भी हमले को भांप लेता है और साइरन के जरिए लोगों को चेतावनी भेजती है। हालांकि, नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाने वाले ड्रोन का पता नहीं लगा। साथियों बात अगर हम दुनियाँ के अलग-अलग गुटों में बंटे होने व भारत की भूमिका की करें तो, इस समय अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य जटिल भी होता जा रहा है। दुनियाँ अलग अलग इलाकों में कई तरह से बंटी नजर आती है। जहां यूक्रेन के खिलाफ अमेरिका पूरी दुनियाँ को रूस को लामबंद कर रहा है, और भारत रूस का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वहीं हमारा देश कई मामलों में चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ देता दिखता है, तो फिर रूस, भारत, चीन, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जैसे देशों का संगठन कुछ अजीब सा ही लगता है।पिछले कुछ समय से दुनियाँ में हलचल और युद्ध का संकट ज्यादा दिखाई दे रहा है, ऐसे में भारत की वैश्विक मंच पर भूमिका भी और भी संवेदनशील हो चली है। ऐसे में भारत और रूस, सहित कई विकासशील देशों का आपस में एक सहयोग संगठन में है जिसे ब्रिक्स कहते हैं।आगामी 22 अक्टूबर भारतीय पीएम रूस के शहर कज़ान में इसी के सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे है। भारत के पीएम अपनी वैश्विक भूमिकाओं के कारण ग्लोबल लीडर साबित हुए हैं। वे दुनियाँ के हर मंच पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले उनकी ये भूमिका उन्हें दुनियाँ के अन्य नेताओं से अलग करती है। साथियों बात अगर हम युद्ध के माहौल में 16 वे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23-25 अक्टूबर 2024 की करें तो, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले भारत के पीएम के इज़राइल व फिलिस्तीन और रूस व यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए किए गए प्रयास के कारण एक बार फिर ग्लोबल लीडर साबित हुए हैं। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिएभारतीय पीएम के प्रयासों की सराहना की है। इससे पीएम की यह छवि और पुख्ता हुई है। पुतिन ने इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। भारत ने हमेशा दोनों पक्षों के बीच बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की है।भारत सरकार ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाया है, साथ ही भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और दो-राज्य समाधान के सिद्धांत का समर्थन किया है। भारत की भूमिका में मध्यस्थता, कूटनीतिक संवाद, और मानवता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। हालांकि, स्थिति जटिल है और पीएम की भूमिका सीमित होती है, लेकिन भारत का यह प्रयास वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स सम्मेलन में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की भागीदारी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह न केवल फिलिस्तीन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज़ उठाने का अवसर है, बल्कि यह ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और एकजुटता को भी दर्शाता है। इस भागीदारी के माध्यम से, अब्बास फिलिस्तीनी मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और वैश्विक समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के सम्मेलनों में शामिल होकर, वे फिलिस्तीन के संघर्ष और स्थिति को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अन्य देश और अंतरराष्ट्रीय संगठन फिलिस्तीन के अधिकारों और स्वतंत्रता के समर्थन में आगे आ सकें।ब्रिक्स जैसे मंचों पर उनकी भागीदारी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक नया दृष्टिकोण और संवाद का निर्माण कर सकती है।

नेगेटिव लोगों से दूर रहें : जीवन में शांति और संतुलन का महत्व

अनिल माथुर

हम सभी के जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो निरंतर नेगेटिव ऊर्जा का संचार करते हैं। ये लोग हमेशा किसी न किसी समस्या की शिकायत करते रहते हैं, हर परिस्थिति में नकारात्मकता ही देखते हैं और अपने विचारों से दूसरों के आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहना आपके मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक विकास के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

नेगेटिविटी का प्रभाव

नेगेटिव लोग अक्सर तनाव, चिंता, और निराशा फैलाते हैं। जब हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो उनकी नकारात्मक सोच हमारे भीतर भी समाहित होने लगती है। यह न केवल हमारी सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है।

आपकी ऊर्जा की सुरक्षा

जीवन में सकारात्मकता और शांति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी ऊर्जा को संरक्षित करें। नेगेटिव लोगों के संपर्क में रहने से हमारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है और हम मानसिक रूप से थके हुए महसूस करते हैं। सकारात्मक सोच और आत्म-संयम बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों

से दूरी बनाना जरूरी है जो निरंतर नकारात्मक बातें करते हैं।

नेगेटिव लोगों की पहचान

नेगेटिव लोगों की पहचान करना मुश्किल नहीं है। ये लोग अक्सर दूसरों की आलोचना करते हैं, खुद को हमेशा पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करते हैं और समाधान की बजाय समस्याओं पर अधिक ध्यान देते हैं। वे दूसरों की सफलता को कभी नहीं स्वीकारते और उनके सामने आने वाली हर परिस्थिति में शिकायत करते रहते हैं।

अपना दृष्टिकोण बनाए रखें

जब भी आप ऐसे लोगों के साथ हों, अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को मजबूत बनाए रखें। यह जरूरी नहीं है कि आप हर समय उनकी बातों का जवाब दें। कभी-कभी मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। आप यह सुन सकते हैं कि किसकी बातों को सुनना है और किससे दूरी बनाए रखनी है।

अपने वातावरण का चुनाव करें

जीवन में संतुलन और सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने चारों ओर सकारात्मक वातावरण बनाएं।

नेगेटिव लोगों से दूरी कैसे बनाए रखें

नेगेटिव लोगों से दूरी बनाने का अर्थ यह नहीं है कि हम उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करें। कभी-कभी हमें परिस्थितियों के अनुसार उनके साथ व्यवहार करना पड़ सकता है। लेकिन यह आवश्यक है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक शांति को प्राथमिकता दें। आप विनम्रता के साथ अपनी सीमाओं को तय कर सकते हैं और संवाद में सकारात्मकता को प्राथमिकता दे सकते हैं।

आत्म-चिंतन और ध्यान

नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है आत्म-चिंतन और ध्यान। ये दोनों विधियां आपको मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाती हैं, जिससे आप बाहरी नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचा पाते हैं।

निष्कर्ष : नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखना आपके व्यक्तिगत विकास और खुशहाल जीवन के लिए आवश्यक है। याद रखें कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आपके पास यह अधिकार है कि आप अपने जीवन में किसे स्थान दें। सकारात्मक सोच और ऊर्जा से भरपूर वातावरण में जीवन का आनंद लें और नकारात्मकता से दूरी बनाए रखें।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हरीपुरा रोड़ खण्डवा,निम्बई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतिष्ठा" सेक्टर-18, प्रताप नगर संगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान* । प्रधान संपादक-राव बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-मालपुरा दिल्ली रोड़ फोन नं.01437-244881 जिला 01438-222101,202,203 अजमेर कार्यालय-रे

राष्ट्रीय सहारा
पटना • सोमवार • 21 अक्टूबर • 2024
www.rashtriyasahara.com

बेहतर बैलेंस

टर्म इंश्योरेंस, वरिष्ठ नागरिक और पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर रेट कम करने के साथ बीस लीटर की पानी की बोतल, साइकिल और अभ्यास नोटबुक पर जीएसटी घटाने के सुझाव दिए गए हैं। दिल्ली में जीएसटी के मंत्री समूह की बिहार के उपमुख्यमंत्री व वाणिज्य-कर मंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री ने इस पर सहमति जताई। इसमें जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा को लेकर चर्चा हुई। टैक्टर को शून्य टैक्स पर लाने और अन्य कृषि उपकरणों पर टैक्स हटाने की भी अनुसंशा की गई। महंगी कलाई घड़ियों और जूतों पर कर बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया। दस हजार से कम कीमत वाली साइकिल पर

जीएसटी बारह से घटा कर पांच फीसद करने का सुझाव आया। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा। जीएसटी के तहत रोजमर्रा की जरूरी चीजों को कर से छूट दी जा सकती है या सबसे कम स्लैब में रखा जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे नुकसानदेह वस्तुओं व लग्जरी आइटम को सबसे ऊंचे स्लैब में किया जा सकता है। जीएसटी करों की संरचना पांच स्लैबों में यानी आवश्यक वस्तुओं के लिए 0%, बुनियादी आवश्यकताओं के लिए 5%, मानक वस्तुओं के लिए 12%, अधिकांश उपभोक्ता उत्पादों के लिए 18% और विलासिता व नुकसानदेह वस्तुओं पर 28% की दरें निश्चित की गई हैं। पिछले वित्त वर्ष में केंद्र व राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमीयम पर जीएसटी लगाकर 8,262.94 करोड़ का राजस्व एकत्र किया था। स्वाथ्य पुनर्बीमा प्रीमियर से 1,484 करोड़ से अधिक का कर वसूला था। आम आदमी तेजी से स्वास्थ्य बीमा कराने के प्रति जागरूक होता जा रहा है। उसे बीमा के प्रति आकर्षित करने के लिए यह कदम सकारात्मक साबित हो सकता है। पूरे देश में समान व्यापक व संतुलित कर प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए वस्तुओं व सेवाओं की विशिष्ट श्रेणियों के लिए नामित किया है जिसके लिए संबिधान में संशोधन भी किया गया था। सितम्बर में ही सरकार ने जीएसटी से 1.73 करोड़ रुपये का संग्रह किया है, जो अगस्त में 1.75 करोड़ था। प्रतीत होता है, इसी के मद्देनजर ये सुझाव लिए गए जो जनता को सुकून देने वाले साबित हो सकते हैं। जिन चीजों पर कर बढ़ाने की बात हुई, उनके खरीदारों की जेब पर बढ़ी हुई कीमतों का अधिक असर नहीं होता। दोनों में बैलेंस रखना ही इन सुझावों की नेक-नीयति कही जा सकती है।

पूछताछ में समझदारी जरूरी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने परिपत्र जारी करके अपने अधिकारियों खासकर जांच अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समय पर बुलाए गए लोगों से 'बेवक्त' पूछताछ न करें और उन्हें कार्यालय में घंटों इंतजार न कराया जाए। परिपत्र बंबई उच्च न्यायालय के उस निर्देश के आलोक में जारी किया गया है, जो अदालत ने 64 वर्षीय एक याचिकाकर्ता की सुनवाई के दौरान दिया था। याचिकाकर्ता ने अदालत में बताया था कि ईडी ने उसे तलब करके रात भर हिरासत में रख कर पूछताछ की। उच्च न्यायालय ने इस पर नाराजगी जताते हुए

कहा कि एजेंसी के इस कृत्य से उस व्यक्ति की नींद बाधित हुई जो उसका बुनियादी मानवाधिकार है। ईडी का यह कृत्य अस्वीकार्य है, और उसे अपने अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत समन जारी करने के बाद किसी को बयान दर्ज करने बुलाया जाए तो वक्त-बेवक्त का ध्यान रखा जाए। हाल के वर्षों में एजेंसियों की पूछताछ को लेकर ऐसे संकेत गए हैं कि पूछताछ के नाम पर आरोपी का उत्पीड़न किया जाता है। विपक्ष इस बात को काफी जोर-शोर से उठाता भी रहा है कि जांच एजेंसियों को उत्पीड़न का जरिया बना दिया गया है जबकि एजेंसियां कानून के दायरे में रहकर काम करती हैं। किसी को परेशान करने जैसे आरोप अंतिरेकी प्रतीत होते हैं, लेकिन ईडी समेत तमाम जांच एजेंसियों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी एक विश्वसनीयता और स्तवा है जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हालिया वर्षों में विपक्ष ने खासा मुखर होकर आरोप लगाए हैं कि उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज करके जांच एजेंसियों के जरिए उत्पीड़न कराया जा रहा है। मजे की बात यह कि विपक्ष की किसी पार्टी से जुड़ा कोई आरोपी जमानत पर बाहर आता है, तो समझाया जाने लगता है कि जेल से छोड़ा जाना ही बेगुनाही का सबूत है जबकि ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि जमानत पर बाहर आने का अर्थ कदापि यह नहीं है कि व्यक्ति को आरोप-मुक्त कर दिया गया है। जब इस प्रकार से विमर्श चलाए जाने का माहौल बन गया हो तो एजेंसियों के लिए जरूरी हो जाता है कि अपना आचरण विवेकपूर्ण बनाए रखें। ऐसा न लगे कि पूछताछ के लिए बुलाए गए व्यक्ति का उत्पीड़न किया जा रहा है जबकि हकीकत में ऐसा कतई नहीं होता।

परिधि/ राजीव मंडल

'दुर्भाग्य' से परे सोचना होगा

अंधविश्वास से जुड़ी दो तस्वीरों को हमें देखना-समझना चाहिए। पहली तस्वीर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की है। यहां के सियासी गलियारे में यह धनधोर तरीके से माना जाता रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आता है, उसकी सत्ता चली जाती है। उदाहरण के लिए 1995 में बतौर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव इस औद्योगिक शहर आए और उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। इसी तरह सितम्बर 1999 में कल्याण सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री यहां का दौरा किया, मगर सत्ता उनकी नहीं रही। हालांकि इस अंधविश्वास को गुरुर के साथ तोड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अंधविश्वास के बारे में बात करते हुए सीएम योगी ने कहा था, 'मैं अब नोएडा आता रहूंगा। मैं ऐसे ठोटकों में भरोसा नहीं करता। लोग हमें वोट देते रहेंगे ताकि हम नोएडा आते रहें।' अच्छी बात है कि योगी दूसरी बार भी सत्ता में लौटे हैं।

अब आते हैं दूसरी तस्वीर की ओर। यह बिहार का दृश्य है। यहां उप मुख्यमंत्री को आवंटित होने वाला सरकारी आवास भी अंधविश्वास की भेंट चढ़ गया है। कहते हैं कि यहां रहने वाला लीडर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। तेजस्वी यादव इसका उदाहरण हैं। इस ठोटके को फिलहाल कोई चुनौती नहीं देता दिखता है। तेजस्वी के बाद आए भाजपा नेता सम्राट चौधरी भी अंधविश्वास के शिकार हैं। वस उन्होंने चालाकी से की कि वास्तुशास्त्र के दोष होने की आड़ में उन्होंने इस आवास के दरवाजे को अस्थायी तौर पर बंद करवा दिया। दरअसल, यहां दो नेताओं की सोच मायने रखती है। दोनों एक ही राजनीतिक पार्टी के हैं, मगर दोनों की सोच में भारी अंतर दिखता है। एक खम ठोंककर कहता है कि मुझे ठोटके की परवाह नहीं। वहीं दूसरे नेता अंधविश्वास को मानते हैं, भले इसे स्वीकारते नहीं हैं। वो इसे थोड़ा ट्विस्ट करते हैं और यह दलील देते हैं कि वास्तुशास्त्र हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सवाल यही कि क्या विकास की बात करने वाले या विकास की दुहाई देने वाले नेताओं को ऐसा सोचना चाहिए? अगर ठोटके वाली बात वाकई सच होती तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहते। दरअसल, शिक्षा और जागरूकता के अभाव में ही लोग अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं। इस दकियानूसी सोच को दरकिनार करने की जरूरत है। क्योंकि 'ईसान बिना मुहूर्त के जन्मता है, बिना मुहूर्त के ही मर जाता है। फिर भी हर कार्य के लिए मुहूर्त पूरी जिंदगी तलाशता है।

क्या सही से खर्च होते हैं पैसे

विकास कार्य

विनीत नारायण

बंजर भूमि, मरूभूमि और सूखे क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपया प्रतीय सरकारों को देती आई है। जिले के अधिकारी और नेता मिलीभगत से सारा पैसा डकार जाते हैं। झूठे आंकड़े प्रांत सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिए जाते हैं पर इस विषय के जानकारों को कागजी आंकड़ों से गुमराह नहीं किया जा सकता। आज हम उपग्रह कैमरे से हर राज्य की जमीन का चित्र देख कर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जहां-जहां सूखी जमीन को हरी करने के दावे किए गए, वो सब कितने सच्चे हैं।

दरअसल, यह कोई नई बात नहीं है। विकास योजनाओं के नाम पर हजारों करोड़ रुपया इसी तरह वर्षों से प्रांतीय सरकारों द्वारा पानी की तरह बहाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का यह कथन अब पुराना पड़ गया कि केंद्र के भेजे एक रुपये में से केवल 14 पैसे जनता तक पहुंचते हैं। सूचना का अधिकार कानून भी जनता को यह नहीं बता पाएगा कि उसके ईर्द-गिर्द की एक गज जमीन पर पिछले 70 वर्षों में कितने करोड़ रुपये का विकास किया जा चुका है। सड़क निर्माण हो या सीवर, वृक्षारोपण हो या कुंडों की खुदाई, नलकूपों की योजना हो या बाढ़ नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाएं हों या शिक्षा का अभियान की अरबों-खरबों रुपया कागजों पर खर्च हो चुका है। पर देश के हालात कछुए की गति से भी नहीं सुधर रहे। जनता दो वक्त की रोटी के लिए जूझ रही है और नौकरशाही, नेता और माफिया हजारों गुना तरक्की कर चुके हैं। जो भी इस क्लब का सदस्य बनता है, कुछ अपवाद को छोड़कर, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई, लोकपाल और अदालतें उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिले में योजना बनाने वाले सरकारीकर्मी योजना इस दृष्टि से बनाते हैं कि काम कम करना पड़े और कमीशन तगड़ा मिल जाए। इन्हें हर दल के स्थानीय विधायकों और सांसदों का संरक्षण मिलता है। इसलिए ये नेता आए दिन बड़ी-बड़ी योजनाओं की अखबारों में घोषणा करते रहते हैं। अगर इनकी घोषित योजनाओं की लागत और मौके पर हुए काम की जांच करवा ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। यह काम मीडिया को करना चाहिए था। पहले करता भी था। पर अब नेता पर कॉलम सेंटीमीटर की दर पर पिछा भुगतान करके बड़े-बड़े दावों वाले अपने बयान स्थानीय अखबारों में प्रमुखता से छपवाते रहते हैं। जो लोग उसी इलाके में ठोस काम करते हैं, उनकी खबर खबर नहीं होती पर फर्जीवाड़े के बयान लगातार धमाकेदार छपते हैं। इन भ्रष्ट

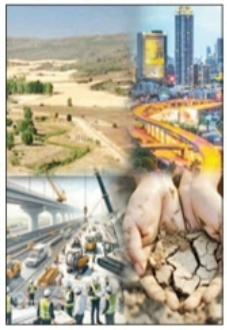

अफसरों और निर्माण कंपनियों का भांडा तब फूटता है जब लोकार्पण के कुछ ही दिनों बाद अरबों रुपये की लागत से बने राजमार्ग या एक्सप्रेस-वे गुणवत्ता की कमी के चलते या तो धंस जाते हैं, या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी घांघली सड़क मार्गों पर ही होती है। ऐसा भी देखने को मिला है जब रेल की पटरियां भी धंस गईं और रेल दुर्घटना हुई।

उधर जिले से लेकर प्रांत तक और प्रांत से लेकर केंद्र तक प्रोफेशनल कंसलटेंट का एक बड़ा तंत्र खड़ा हो गया है। यह कंसलटेंट सरकार से अपनी औकात से दस गुनी फीस वसूलते हैं, और उसमें से 90 फीसद तक काम देने वाले अफसरों और नेताओं को पीछे से कमीशन में लौटा देते हैं। बिना क्षेत्र का सर्वेक्षण किए, बिना स्थानीय अपेक्षाओं को जाने, बिना प्रोजेक्ट की सफलता का मूल्यांकन किए केवल खानापूर्ति के लिए डीपीआर (विस्तृत कार्ययोजना) बना देते हैं। फिर चाहे जेएनआरयूएम हो या मनरेगा, पर्यटन विभाग की डीपीआर हो या ग्रामीण विकास की, सबमें फर्जीवाड़े का प्रतिशत काफी ऊंचा रहता है। यही वजह है कि योजनाएं खूब बनती हैं, पैसा भी खूब आता है, पर हालात नहीं सुधरते। आज के सूचना क्रांति के दौर में ऐसी चोरी पकड़ना बायें हाथ का खेल है। उपग्रह सर्वेक्षणों से हर परियोजना के क्रियान्वयन पर पूरी नजर रखी जा सकती है और काफी हद तक चोरी पकड़ी जा सकती है। पर चोरी पकड़ने का काम नौकरशाही का कोई सदस्य करेगा तो अनेक कारणों से सच्चाई छिपा देगा। निगरानी का यही काम देश भर में अगर प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठनों या व्यक्तियों से करवाया जाए तो चोरी रोकने में पूरी नहीं तो काफी सफलता मिलेगी। ग्रामीण विकास के मंत्री ही नहीं, बल्कि हर मंत्री को तकनीकी क्रांति की मदद लेनी चाहिए। योजना बनाने में आपाधापी को रोकने के लिए सरल तरीका है कि जिलाधिकारी अपनी योजनाएं वेबसाइट पर डाल दें और उन पर जिले की जनता से 15 दिन के भीतर आपत्ति और सुझाव दर्ज करने को कहें। जनता के सही सुझावों पर अमल किया जाए। केवल सार्थक, उपयोगी और ठोस योजनाएं ही केंद्र सरकार और राज्य को भेजी जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन की साप्ताहिक प्रगति के चित्र भी वेबसाइट पर डाले जाएं जिससे उसकी कमियां जागरूक नागरिक उजागर कर सकें। इससे जनता के बीच इन योजनाओं पर हर स्तर पर नजर रखने में मदद मिलेगी और अपना लोकतंत्र मजबूत होगा। फिर बाबा रामदेव या अन्ना हजारे जैसे लोगों को सरकारों के विरुद्ध जनता को जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आज हर सरकार की विश्वसनीयता, चाहे वो केंद्र की हो या प्रांतों की, जनता की निगाह में काफी गिर चुकी है और अगर यही हाल रहे तो हालत और भी बिगड़ जाएगी। देश और प्रांत की सरकारों को अपनी पूरी सोच और समझ बदलनी पड़ेगी। देश भर में जिस भी अधिकारी, विशेषज्ञ, प्रोफेशनल या स्वयंसेवी संगठन ने जिस क्षेत्र में भी अनुकरणीय कार्य किया हो, उसकी सूचना जनता के बीच, सरकारी पहल पर, बार-बार, प्रसारित की जाए। इससे देश के बाकी हिस्सों को भी प्रेरणा और ज्ञान मिलेगा। फिर सात्त्विक शक्तियां कहेंगी और देश का सही विकास होगा। अभी भी सुधार की गुंजाइश है। लक्ष्यपूर्ति के साथ गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि इन घोषणाओं के चलते किए गए ये दावे गुणवत्ता के पैमाने पर कितने खरे उतरते हैं? चूंकि ऐसी योजनाओं में भ्रष्टाचार तो अपने पांव पसारता ही है? ऐसे में जनहित का दावा करने वाले नेता क्या वास्तव में जनहित करे पाएंगे?

(लेख में विचार निजी हैं)

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का यह कथन पुराना पड़ गया है कि केंद्र के भेजे एक रुपये में से केवल 14 पैसे जनता तक पहुंचते हैं। सूचना का अधिकार कानून भी जनता को नहीं बता पाएगा कि उसके ईर्द-गिर्द की एक गज जमीन पर 70 वर्षों में कितने करोड़ रुपये का विकास किया जा चुका है। जिले में योजना बनाने वाले सरकारीकर्मी योजना इस दृष्टि से बनाते हैं कि काम कम करना पड़े और कमीशन भी तगड़ा मिल जाए

महानता

श्रीराम शर्मा आचार्य

मानवीय विकास का वास्तविक स्वरूप निर्धारित करना हो तो यह मानकर नहीं चला जा सकता कि मनुष्य शरीर पाने तक ही उसकी अंतिम परिणति है। उसे विकासोन्मुख होने के लिए शरीरगत जीवन यापन को भी सब कुछ न मान कर अपनी सत्ता चेतना के साथ जोड़नी पड़ेगी जो इस ब्रह्मांड पर अनुशासन करती और अंतराल को सुविकसित, स्वच्छ बना लेने वालों पर अपनी उच्चस्तरीय अनुकंपा बरसाती है। मनुष्य को इस प्रकार का चिंतन अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है कि उसके अंतराल में अति महत्त्वपूर्ण क्षमताओं का भी भंडार भरा पड़ा है, जिसे थोड़ा विकसित कर लेने पर वह काया की दृष्टि से यथावत रहते हुए भी व्यक्तित्व की दृष्टि से महानतम बन सकता है। इस अध्यात्म विकास के तत्त्वज्ञान के अनुरूप चेतना को विकसित, परिष्कृत, समर्थ, विलक्षण बनाने का द्वार मनुष्य शरीर मिलने के उपरांत खुलता है। इससे पूर्व तो वह मात्र जीवधारी ही बनकर रहता है। प्रकृति का अनुशासन मानने के लिए भी बाध्यित रहता है। प्रकृति पर परमात्मा का स्वामित्व है। मनःस्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदाता है। मनुष्य अपने भाग्य निर्माता आप है। प्रकृति की कठपुतली मात्र नहीं है। अन्य प्राणियों की तरह मात्र निर्वाह ही उसकी एकमात्र आवश्यकता नहीं है वरन व्यक्तित्व का स्तर उठाकर जीवन सज्जा को अनेक उपलब्धियों-विभूतियों से अलंकृत करना भी विशिष्ट उद्देश्य है। जब तक यह विचारणा नहीं उठती, तब तक वस्तुतः मनुष्य नर-पशु ही रहता है और इन्द्रिय लिप्साओं तथा मानसिक तृष्णाओं तक ही उसकी गतिविधियां सीमित रहती हैं, न वह जीवन का महत्त्व समझ पाता है और न उसे चेतना की पुथकता, विशिष्टता संबंधी कुछ ज्ञान होता है। विकास की दृष्टि से पेड़ की ऊंचाई एक सीमा तक बढ़ती जाती है। यह सीमा पूरी होने पर उसका फैलाव एवं मोटाई की अभिवृद्धि होती है तथा फल-फूल लगने लगते हैं। योनियों की दृष्टि से हाथी, सिंह आदि का विस्तार तथा प्रभाव बढ़ा-चढ़ा है पर शारीरिक संरचना और मानसिक स्तर की दृष्टि से मनुष्य ही मूर्धन्य है। इसीलिए उसे सृष्टि का शिरोमणि कहा जाता है। सुख साधन उसके पास असीम मात्रा में हैं। अस्त्र-शस्त्रों सहित रण कौशल में उसकी प्रवीणता है। समाज गठन और शासन तंत्र का निर्माण उसी का अनुपम कौशल है। पदार्थ विज्ञान में उसने असाधारण उन्नति की है।

रीडर्स मेल

शरीफ का पॉजिटिव संकेत

पाकिस्तान में हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) की शिखर बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस कुशल डिप्लोमेसी से सकारात्मक माहौल को जन्म दिया है, वह पाकिस्तान के साथ मधुर संबंधों का सबब भी बन सकता है। यद्यपि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के साथ बेहतर रिश्तों के लिए पहले भी अपनी इच्छा जाहिर की थी। पीएम नवाज शरीफ ने भारत के साथ रिश्तों को सुधारने का जो आह्वान किया है वह पॉजिटिव संकेत है। पाकिस्तानी मीडिया में इसे दोस्ती की तरफ बढ़ा कदम माना गया। यह भी सकारात्मक संदेश है जबकि एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शिरकत करनी चाहिए थी। बावजूद इसके पीएम नवाज शरीफ ने इसे तूल न देकर विदेश मंत्री एस जयशंकर को पॉजिटिव डवलपमेंट के रूप में स्वीकारा। वैशक, यह पहलकदमी महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है बशर्ते आतंकवाद पर पीएम नवाज शरीफ हिकंजा कसने में कामयाब रहें। उम्मीद करें पाकिस्तान का निजाम इस मोर्चे पर खरा उतरेगा और लोगों में भरोसा पैदा कर पाएगा।

माम चंद सागर, ई मेल से

बड़ी बहस का मुद्दा बने शराबबंदी

सुशासन बाबू के बिहार राज्य में छपरा, सीवान, गोपालगंज में शराब पीने से अब तक 36 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और करीब 40 लोग अस्पताल में जिंदगी-मौत से जूझ रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने डीजीपी को जांच का जिम्मा सौंपा है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। मुख्यमंत्री द्वारा मुआवजा की घोषणा भी कर दी जाएगी, लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है, क्या उनका परिवार संभल पाएगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दरअसल, देश में शराबबंदी बड़ी बहस का मुद्दा होना चाहिए। बिहार राज्य में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके अवैध शराब की बिक्री रोकने में सरकार नाकाम रही है। इसकी रोकथाम के लिए कारगर और ठोस उपाय करने होंगे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। इस दुखद घटनाक्रम पर प्रियंका गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक ने सरकार को घेरा है और सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिह्न खड़ा किया है लेकिन जनता को जागरूक करने की जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल एवं विपक्ष, दोनों की है।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

संवाद का माहौल तो बने

पाकिस्तान के साथ बातचीत की हर बार जमीन तैयार की जाती है, लेकिन सार्थक बातचीत नहीं हो पाती। आखिर हो भी कैसे/ दोनों पक्ष अपने अपने मुद्दों पर अड़ाग हैं। भारत चाहता है कि पाकिस्तान नेकदिली से हाथ बढ़ाए, भारत में आतंकवाद को एक्सपोर्ट करना बंद करे, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। वो कश्मीर का मुद्दा और अब साथ ही धारा 370 का मुद्दा अपने जीते जी छोड़ नहीं सकता। उनकी भी मजबूरी है। अगर सत्ता में रहना होगा तो कश्मीर कश्मीर कहना होगा। वरना गद्दी छोड़नी होगी। पाकिस्तान की जनता तो जानती है कि भारत से संबंध सुधारने में ही उसकी भलाई है, लेकिन सत्ता के गलियारों में ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री अलग थी, लेकिन वो केमिस्ट्री उनके छोटे भाई के साथ नहीं बन पाई। भारत तो संबंध सुधारना चाहता है तभी तो विदेश मंत्री को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए भेजा।

चंद्र प्रकाश शर्मा, गया

letter.editorsahara@gmail.com

टीवी न्यूज

चैनल्स की इज्जत लगातार कम हुई है। ये कई बार बहुत परेशान करता है। न्यूज चैनल में काम करते हुए मैं एक बात ईमानदारी से मानता हूं कि चैनल को एंकर ड्राइव करने लगे हैं। जिस दिन चैनल एंकर ड्रिवेन होने के बजाय खबर ड्रिवेन हो जाएंगे, चैनल्स के सुनहरे दिन वापस आ जाएंगे।

सुकेश रंजन, पत्रकार
@RanjanSukesh

मुट्ठी भर ने ही बदला है इतिहास

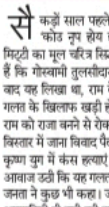

विमर्श

डॉ. सी.पी. राय

सैकड़ों साल पहले ही भारत में लिख दिया गया था 'कोउ नृप होय हमें का हानि'। इससे भारत की मिट्टी का मूल चरित्र सिद्ध होता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने मुगल राज स्थापित होने के बाद यह लिखा था, राम के युग में ही संपूर्ण जनता किसी गलत के खिलाफ खड़ी हो गई हो ऐसा तो नहीं दिखा। चाहे राम को राजा बनने से रोकना हो या सीता की अग्नि परीक्षा। विस्तार में जाना विवाद पैदा कर सकता है।

कृष्ण युग में कंस हत्याएं करता जा रहा था पर कहां कोई आवाज उठी कि यह गलत है। अशोक के काल में भी कहां जनता ने कुछ भी कहा। जनता हमेशा ताकत और सत्ता की अनुगामिनी ही बनी रही वरना सैकड़ों की तादाद में आते थे विदेशी लुटेरे और लूट कर चले जाते थे भारत को। कोई आता तो खेती करता किसान हल-बैल लेकर किनारे खड़े होकर तमाशा देखता और बाकी लोग भी। लड़ता सिर्फ वो था जिसे लड़ने के पैसे मिलते थे और ज्यादातर वो भी सेनापति के घायल होने या मर जाने पर भाग खड़े होते या विजेता से मिल कर उनके लिए लड़ने लगते।

भारत पर आक्रमण करने वाला या राज करने वाला कोई भी बड़ी फौज लेकर नहीं आया था। सबकी लड़ाई और राज भारतीय लोगों के दम पर ही चले। भारत के नागरिक पर जुल्म या हत्या सब यहां के लोगों ने किया या तो डर कर या बिक कर और विदेशियों को बुलाकर लाने वाले भी भारतीय थे, रास्ता बताने वाले या कमजोरी बताने वाले भी भारतीय थे। जब सोमनाथ को लूटा जा रहा था तो वहां के सारे पंडे और दर्शनार्थी बैठ कर पूजा करने लगे कि अभी भगवान का प्रकोप होगा और सब लुटेरे भस्म हो जाएंगे। पर वो करने की बजाय उन्होंने अपने थाली-लोटे से भी आक्रमण कर दिया होता तो सोमनाथ नहीं लुटा होता, भगवान की मूर्ति और मंदिर की शक्ति का भ्रम भी बना रहता और लुटेरे टुकड़ों में मुर्दा पड़े होते और उससे भी बड़ा काम यह हुआ होता कि आईदा कोई भी भारत पर आक्रमण करने से पहले सौ बार सोचता कि भारत का या उसके किसी भी हिस्से का हर आदमी अपने राज या जमीन के लिए लड़ने को खड़ा हो जाता है।

आगे भी पूरा देश तो कभी खड़ा नहीं हुआ, बल्कि थोड़े से

लोग खड़े हुए किसी भी लड़ाई में वो आंदोलन चाहे आजादी का रहा हो और चाहे आपातकाल से पहले का। जिन लोगों ने भी हिंसा का रास्ता अपनाया उनके साथ कम लोग खड़े हुए। गांधी जी इस मिट्टी की तासीर को अच्छी तरह समझ गए थे। इसीलिए उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया और इस रास्ते से वो लाखों या करोड़ों को जोड़ने में कामयाब हुए पर वो भी पूरे देश को नहीं जोड़ पाए। अंग्रेजों के समय भी पूरी जनता तो इसी कोऊ नृप वाले भाव की थी तब बहुत से लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, बहुत से प्रशंसक थे तो हाथों में हथियार लेकर जलियांवाला बाग से होकर पूरे देश में गोली लाठी चलाने वाले, आजाद को गोली मारने वाले, भगत सिंह को फांसी लगाने वाले और सुभाष की सेना पर गोली बरसाने वाले सब तो भारतीय ही थे। केवल आदेश देने वाला अंग्रेज होता था और मुखबिरी कर आजादी के लिए लड़ने वालों की पकड़वाने वाले भी भारतीय ही थे। सभी के खिलाफ अंग्रेजों के पक्ष में मुकदमा लड़ने वाले भी भारतीय थे और गवाही देने वाले भी भारतीय ही थे।

आज भी वही हालत है जो भारत की तासीर है। आज भी सोमनाथ की तरह देश का बड़ा हिस्सा मंदिर में अपना सुख और भविष्य देख रहा है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जरा किसी धार्मिक स्थल को कुछ हो जाए, किसी के चित्र या प्रतिमा से कुछ हो जाए या दो जानवरों में से किसी का कुछ हो जाए तो निकलते हैं पर फिर भी मुट्ठी भर और वच-वच कर कि कोई खतरा तो नहीं और नहीं है तथा सामने वाला कमजोर या कम है तो कायरता पूरी ताकत से क्रूरता दिखाते हैं और चीख की आवाज भी बुलंद होती है।

आज फिर भारत आजादी बनाम गुलामी, लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद, संविधान बनाम प्रधान की इच्छा, कानून बनाम सत्ता की लाठी के बीच झूल रहा है। अधिकांश कोऊ नृप होय वाले हैं, तो बहुत से अज्ञात कारणों से प्रशंसक हैं तो बहुत से गली-गली में मुखिबर और बहुत से लाठी बंदूक और कानून की किताब के साथ इनके साथ खड़े हैं, तो बहुत से चाहे कलम से या कला से, जुबान से या आंखों की भाषा से लड़ाई भी लड़ रहे हैं सच की, ईमान की, लोकतंत्र की संविधान की और अंत में यही जीत जाएंगे सारे जुल्म के बावजूद क्योंकि हमेशा ही वे मुट्ठी भर लोग ही जीते हैं। इतिहास तो यही बताता है। बस, देखना इतना है कि वो एक कौन होगा इस युद्ध का नायक और क्या कोई संपूर्ण भारत को कभी निकाल सकेगा चाहे जिसके खिलाफ चाहे जब और चाहे जो भी गलत हो? क्या कोई बदल पाएगा ये आवाज कोऊ नृप होंय हमे का हानी' से 'को नृप होय ये हम ही जानी' में।

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्यूनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काजमी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मेडिया केन्यर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-परिमपुर, मुल्लिस सोहना-शहतूर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा प्रधान संपादक, सहारा इण्डिया बिहार, बीरेंद्र शेठ क्रार्टर, पटना से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428

न्याय का उद्देश्य हर किसी को उसका हक दिलाना है। - सिसेरो

त्योहारों से ऐन पहले हर साल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आबोहवा के बिगड़ने की रिवायत विचलित करने वाली है। उम्मीद करनी चाहिए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद्देनजर सरकारें असंवेदनशीलता छोड़, दीर्घकालीन विजन के साथ इस समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगी।

हवा में जहर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सुबह और शाम के वक्त तापमान में लगातार कमी से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन दीवाली से ठीक पहले यहां हवा की गुणवत्ता जिस खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, उससे पर्यावरण व सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। चिंता की बात अलबत्ता यह भी है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इससे जल्द राहत मिलने के संकेत नहीं दिए हैं। दरअसल, जैसे-जैसे ठंड नजदीक आती है, दिल्ली की हवा भी जहरीली होने लगती है, जिसके लिए स्थानीय सरकार पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने को वजह बताती आ रही है। हालांकि तथ्य कुछ और ही कहते हैं। दरअसल, दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान अक्तूबर की शुरुआत में एक फीसदी से भी कम था, जो अब जाकर ढाई फीसदी के आस्पास पहुंचा है। जबकि, यहां गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषकों का प्रतिशत दस फीसदी से भी ज्यादा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, राजधानी में निर्माण गतिविधियों व सड़कों पर जमी धूल का प्रदूषण में योगदान तकरीबन एक से दो फीसदी के बीच है। उल्लेखनीय है कि ठंड का मौसम आते-आते कोहरे की वजह से हवा भारी होने लगती है और उस पर प्रदूषित कण भी जमने लगते हैं, जिससे वह वायुमंडल में नहीं पहुंच पाती और प्रदूषण बढ़ने लगता है। लेकिन अभी जब वायु में नमी भी उस तरह से नहीं आई है, तब दिल्ली और उससे सटे फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गुरुग्राम में वायु प्रदूषण का बढ़ना सवाल पैदा करता है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में धूल विरोधी अभियानों के तहत जुर्माने लगाए जा रहे हैं, सार्वजनिक निर्माण के नियमों को लागू किया जा रहा है, जो जरूरी भी है, लेकिन वायु प्रदूषण की समस्या का हर साल दीवाली के वक्त विकराल रूप से सामने आना इससे निपटने की रणनीतियों में दीर्घकालिक विजन के बजाय फौरी उपायों पर अत्यधिक निर्भरता को ही दर्शाता है। यमुना के झाग पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन आसन्न छठ को देखते हुए यह स्थिति डराने वाली तो है ही। एक स्थानीय सर्वे की रिपोर्ट भी चिंतित करने वाली है, जिसके मुताबिक इस वक्त दिल्ली के छत्तीस फीसदी परिवार प्रदूषण संबंधी शारीरिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं। आने वाले दिनों में जब ठंड और बढ़ेगी, दीवाली के वक्त जब प्रदूषक कण वातावरण में स्थिर हो जाएंगे, और अगर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो जाहिर है कि स्वास्थ्य संकट विकराल रूप ले सकता है। प्रदूषण की वार्षिक हो चुकी समस्या प्रशासनिक असंवेदनशीलता को ही दिखाती है। ऐसे में जरूरी है कि सरकारें गंभीर हों, नागरिकर जागरूक हों और नियमों का सख्ती से पालन हो।

अदालतों का बोझ कम करने की यही राह है

देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या, न्याय मिलने में देरी और वर्षों चलने वाले मुकदमों के खर्च को देखते हुए प्रधान न्यायाधीश वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए मध्यस्थता की प्रक्रिया पर जोर देने की बात करते रहे हैं, जिससे सच्चे न्याय की उम्मीद बंधती है।

सीवीपी श्रीवास्तव
अध्यक्ष, सेंटर फॉर अप्लायड रिसर्च इन गवर्नेंस, दिल्ली

यह बिल्कुल सही है कि न्याय केवल दिया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए। न्याय मिलने में विलंब कई अवसरों पर अन्याय का कारण बनता है। यह भी विदित है कि सामाजिक स्तर पर लोगों या समूहों के बीच विचारों का आदान-प्रदान नहीं होना संघर्षों का कारण है। इसी संदर्भ में कुछ ऐसी प्रक्रियाओं का महत्व बढ़ जाता है, जिनके जरिये अंतःक्रियात्मक वातावरण बनाकर विवादों का समाधान किया जा सके और त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सके। कदाचित इसी उद्देश्य से हाल ही में देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए मध्यस्थता की प्रक्रिया पर जोर देने की बात कही है।

राष्ट्रीय न्यायिक ग्रिड के आंकड़ों और प्रधान न्यायमूर्ति द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, जिला और तालुका स्तर पर न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या लगभग 4.1 करोड़ है, जबकि उच्च न्यायालय में यह संख्या 59 लाख है। हालांकि उच्चतम न्यायालय सबसे कार्यकुशल न्यायालय है, क्योंकि यह प्रतिवर्ष लगभग 45,000-50,000 मामलों का निपटारा करता है, लेकिन इसके बावजूद लगभग 71,000 मामले इसमें भी लंबित हैं। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, 2010 और 2020 के बीच सभी अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में औसतन 2.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई है।

न्याय तंत्र की दूसरी बड़ी समस्या वादियों और प्रतिवादियों द्वारा खर्च होने वाली राशि है। ऐसा देखा गया है कि मामलों का निपटारा होने तक कई परिवार गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान एक मितव्ययी प्रक्रिया है। विशेषकर पारिवारिक विवादों के मामले में गोपनीयता बनी रहती है। इसके अतिरिक्त, पक्षकारों की स्वायत्तता का संरक्षण भी होता है। इसी पृष्ठभूमि में वैकल्पिक समाधान प्रक्रियाओं को समझना समीचीन होगा। भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान का सांविधानिक आधार अनुच्छेद 39-ए है, जो अनुच्छेद 21 से सीधे संबंधित है। अनुच्छेद 39-ए में समान और निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधान हैं। दूसरी ओर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 के तहत मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन), सुलह (कॉन्सिलिएशन) मध्यस्थता / और न्यायिक समाधान अथवा लोक अदालत को स्वीकार किया गया है। इनकी प्रक्रियाओं को नियमित करने के लिए इन्हें कानून के तहत शामिल किया गया है।

जैसे, मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम 1996 (2021 में संशोधित) के तहत क्रमशः बाध्यकारी निर्णय या प्रस्ताव के जरिये सिविल और शमनीय अपराधों (कम संगीन अपराधों, जैसे चोरी, आपराधिक अतिचार, व्यभिचार आदि) का समाधान किया जाता है। इसी प्रकार, मध्यस्थता अधिनियम 2021 में एक भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना का उल्लेख है, जो मध्यस्थता समझौते को कानूनी आधार देगा।

सबसे बड़ी बात है कि इस कानून में विवाद समाधान के लिए अधिकतम अवधि 180 दिनों की तय की गई है। इससे त्वरित न्याय उपलब्ध कराना सरल होगा। कई अवसरों पर ऐसे समाधान के बाद भी किसी पक्षकार को संतुष्टि नहीं होती। इसलिए यह प्रावधान भी है कि कोई भी पक्षकार मध्यस्थता के दो सत्रों के बाद प्रक्रिया से बाहर हो सकता है। सिविल और वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए वाद-पूर्व मध्यस्थता जहां लंबित मामलों की संख्या पर रोक लगाएगी, वहीं यह सामाजिक स्तर पर अंतःक्रिया बढ़ाकर आपसी संबंधों को मजबूत भी बनाएगी।

जहां तक लोक अदालतों का प्रश्न है, इनका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39-ए से प्रेरित विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में किया गया है। स्थायी लोक अदालत (अधिनियम की धारा 22-बी) के अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत और ई-लोक अदालत का प्रावधान न्यायतंत्र को मजबूत बनाने में सहायक है। भारत में पहली लोक अदालत का आयोजन गुजरात में 1999 में किया गया था। लोक अदालतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके निर्णय अंतिम होंगे और इनके विरुद्ध अपील नहीं की जाएगी। इसका अर्थ इन अदालतों का निरपेक्ष होना नहीं है। अपील का प्रावधान नहीं होने का कारण यह है कि ये अदालतें वाद-पूर्व विवाद समाधान करती हैं। इनकी निरपेक्षता को सीमित करने के लिए यह उल्लेख है कि असंतुष्ट पक्ष न्यायालय में वाद संस्थापित कर सकता है।

न्याय तंत्र तक पहुंच भी भारत में एक बड़ी समस्या रही है। इस तंत्र में तकनीकों के प्रयोग के बाद ई-अदालतों की भूमिका बढ़ी है। यदि ई-लोक अदालतों की भूमिका बढ़ाई जाए, तो न्याय उपलब्धता की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने से ही ऐसा हो सकेगा। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में आयोजित मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता निपटान समझौते के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। भारत द्वारा शीघ्र ही इसे अनुमोदित करने की आशा है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली मध्यस्थता केंद्र में 31 जुलाई तक मध्यस्थता के लिए उपयुक्त 2,86, 631 मामलों में से कुल 2,81,474 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा चुका है, जो कुल मामलों का 98.2 प्रतिशत है। यह निश्चित रूप से उत्साहवर्धक है और न्याय तंत्र में वैकल्पिक प्रक्रियाओं के महत्व का प्रतीक है।

मध्यस्थता के विषय पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार, मध्यस्थता सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है, जहां विचारों के आदान-प्रदान और सूचना के प्रवाह के माध्यम से सामाजिक मानदंडों को सांविधानिक मूल्यों के अनुरूप लाया जाता है। मध्यस्थता के दौरान अमूल्य चर्चा से प्राप्त समाधान व्यक्तियों और समूहों के लिए उनकी शर्तों पर, उनकी समझ में आने वाली भाषा में सच्चा न्याय सुनिश्चित करता है और एक ऐसा मंच प्रदान करता है, जो उनकी भावनाओं को रक्षा करता है और जो उनके अस्तित्व और आत्मा के करीब होता है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

नेल्सन मंडेला

मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज मुझे कभी मार सकती है, तो वह है उन लोगों के हिस्से में खुशी नहीं दे पाना, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है।

मानवीय करुणा हमें एक-दूसरे से जोड़ती है

मैंने आजादी की ओर जाने वाले उस लंबे रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है और कोशिश की है कि लड़खड़ाऊं नहीं। मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज मुझे कभी मार सकती है, तो वह है उन लोगों के हिस्से में खुशी नहीं दे पाना, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं और जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हैं। अगर मैं अपने जीवन का एक छोटा-सा हिस्सा उन्हें खुश करने में लगा सकता हूं, तो मैं खुशी महसूस करूंगा। यह बात मेरे जेहन में हमेशा रहती है कि एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा एक मजबूत संयोजन होता है। मानवीय गरिमा की कमी का परिणाम है कि आज बच्चे कस्बों की सड़कों पर भटकते रहते हैं, क्योंकि उनके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके माता-पिता परिवार चलाने के लिए सुबह ही काम करने के लिए घर से निकल जाते हैं। इस तरह उनके पास कोई भी नहीं होता, जो उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करे। इससे नैतिक मानकों में गिरावट आती है, अवैध कार्यों में खतरनाक वृद्धि होती है और हिंसा बढ़ती है। इन सबको रोकने के लिए समाज में शांति स्थापित करनी होगी। इसके लिए हमें शिक्षा का सहारा लेना होगा, क्योंकि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग हम दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा के बिना आपके बच्चे कभी भी उन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते, जिनका उन्हें सामना करना है। इसलिए बच्चों को शिक्षा देना और यह समझना बहुत जरूरी है कि उन्हें अपने देश के लिए भूमिका निभानी चाहिए।

हम हर तरह की परिस्थितियों से ऊपर उठ कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज मैं हमेशा से ही जानता हूं कि हर इन्सान के दिल की गहराई में दया और उदारता होती है, उसे स्वयं को शिक्षित करके उन्हें बाहर लाना चाहिए। हमारी मानवीय करुणा हमें एक-दूसरे से जोड़ती है-दया या संरक्षण के भाव से नहीं, बल्कि ऐसे इन्सानों के रूप में, जिन्होंने सीखा है कि कैसे अपने साझा दुख को भविष्य की आशा में बदला जाए। एक दिन, मैं अपने घर के सामने वाले बगीचे के पास खड़ा था और मैंने एक पेड़ पर बैठी गौरैया पर बंदूक तान दी। वहीं मौजूद आर्थर की पत्नी हेजल मुझे देख रही थीं और मजाक में बोलीं कि मैं निशाना नहीं लगा पाऊंगा। लेकिन अभी उन्होंने अपनी बात पूरी ही की थी कि गौरैया जमीन पर गिर पड़ी। मैं उनकी ओर मुड़ा और शेखी बघारने ही वाला था कि हेजल का बेटा पॉल, जो तब लगभग पांच साल का था, आंखों में आंसू लिए मेरी ओर मुड़ा और बोला, आपने उस चिड़िया को क्यों मारा? उसकी मां दुखी होंगी। मेरा भाव तुरंत गर्व से शर्म में बदल गया। मुझे लगा कि इस छोटे लड़के में मुझसे कहीं ज्यादा इन्सानियत है।

दयालु बनें

सूत्र

जीवन एक मुश्किल और चुनौतीपूर्ण यात्रा हो सकता है। कई चीजों में से एक, जो इसे सार्थक बनाती है, वह है दूसरों के प्रति दयालुता और खुद के प्रति भी वही दयालुता और करुणा दिखाना। दयालुता बाधाओं को तोड़ सकती है, किसी व्यक्ति के पूरे भाव को बदल सकती है और एक चिरस्थायी रिश्ता बना सकती है। हमेशा याद रखें, दयालुता का सबसे छोटा कार्य सबसे बड़े इरादे से भी अधिक मूल्यवान है।

दूसरा पहलू

लंदन स्थित 'द इंडिया क्लब' को शायद ही कोई भारतीय भुला पाए। वह हमारी स्मृतियों का भंडार था।

लंदन में बंद हुआ भारतीयों का प्रिय 'इंडिया क्लब'

रमेश ठाकुर

'द इंडिया क्लब' बीते 70 वर्षों से स्वतंत्रता की लड़ाई, सांस्कृतिक इतिहास और स्वादिष्ट भारतीय व्यंजनों का केंद्र बना हुआ था।

लंदन पहुंचने वाला कोई भी हिंदुस्तानी क्लब का दीदार करना नहीं भूलता था। क्लब में भारतीय परंपराओं और संस्कृतियों से जुड़ी बेशुमार निशानियां हैं। क्लब के मालिक यहां होटल बनवाना चाहते हैं।

प्रवासियों के आने की राह देखने वाला लंदन स्थित 'द इंडिया क्लब' को शायद ही कोई भारतीय भुला पाए। वह हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलनकारियों और राष्ट्रवादियों का मात्र गढ़ ही नहीं था, बल्कि हमारी स्मृतियों का भंडार था, जिसे अब बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। यह क्लब प्रवासी भारतीयों को परदेश में अपनेपन का एहसास करवाती थी। क्लब के बंद होने से भारतीय संस्कृति की तमाम भूली-बिसरी यादें भी धूमिल हो गईं। इसे वर्ष 1951 में वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने स्थापित किया था। बीते 70 वर्षों से यह क्लब स्वतंत्रता की लड़ाई, सांस्कृतिक इतिहास और स्वादिष्ट भारतीय व्यंजनों का केंद्र बना हुआ था।

भारत से लंदन पहुंचने वाला कोई भी हिंदुस्तानी उस क्लब का दीदार करना नहीं भूलता था। पिछले वर्ष सितंबर-2023 में क्लब को बंद करने का निर्णय उसके मालिकों ने लिया था। हालांकि क्लब को उसके मालिक नहीं चलाते थे, बल्कि उसके प्रोपराइटर भारतीय मूल के मार्कर मार्क और उनकी बेटी फिरोजा किराए पर चलाते थे। बीते एकाध दशक से क्लब के मालिक लगातार किराया बढ़ाते जा रहे थे और क्लब को खाली करने का कानूनी नोटिस भी भिजवा रहे थे। हालांकि फिरोजा ने क्लब को बचाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। अंततः पिछले महीने मालिकों के पक्ष में ही फैसला सुना दिया गया।

क्लब में भारतीय परंपराओं और संस्कृतियों से जुड़ी बेशुमार निशानियां मौजूद हैं। वह टेबल-कुर्सी, जिस पर पंडित नेहरू आकर अक्सर तुलसी पत्ती की चाय पिया करते थे। उनके लिखे खत, उनके इस्तेमाल किए बर्तन इत्यादि भी क्लब में मौजूद हैं। क्लब में नेहरू, माउंटबेटन, वीके मेनन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, दादाभाई नौरोजी के अलावा शशि थरूर, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे मौजूदा पीढ़ी के अनगिनत नेताओं का आना-जाना हमेशा रहा। ब्रिटेन के कुछ कट्टरपंथी दशकों से इस क्लब को बंद करवाने की मांग कर रहे थे। क्लब मालिक यहां आलीशान होटल बनवाना चाहते हैं। क्लब में कुल 26 कमरे थे, भीतर एक बड़ा गार्डन और लॉन था। वहां एक साथ पांच सौ लोग समा सकते थे। क्लब पांच इलाका 'चेरिल क्रॉस के नजदीक भूखंड संख्या-143 के स्टैंड कॉन्टिनेटल' में स्थित है, जिसका कभी कृष्ण मेनन के नेतृत्व में इंडिया लीग के सदस्यों ने अपने करकमलों से श्रीगणेश किया था। आज उनकी आत्माएं भी रोती होंगी। उनकी तमाम यादें क्लब से जुड़ी थीं।

आंकड़े

इलेक्ट्रॉनिक निर्यात

तमिलनाडु ने वित्त वर्ष 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो निर्यात के कुल हिस्से का लगभग 33 फीसदी है।

तमिलनाडु	32.84%
कर्नाटक	15.78%
उत्तर प्रदेश	15.32%
महाराष्ट्र	10.62%
गुजरात	9.43%

आंकड़े प्रतिशत में हैं। चेन्नई : Eco. Survey

संत सुंदरमूर्ति विवाह की शर्त का उल्लंघन करने के चलते अंधे हो गए। लेकिन भगवान की भक्ति से उनकी आंखों की रोशनी लौट आई।

संत सुंदरमूर्ति की भक्ति

अंतर्यात्रा
संकलित

तामिल प्रांत के एक छोटे से गांव में संत सुंदरमूर्ति का जन्म हुआ। इनके माता-पिता हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते और समाज सेवा में ही अपना मन लगाते थे। एक समय बाद संत सुंदरमूर्ति ने निश्चय किया कि वह गांव-गांव जाकर भगवान का गुणगान करेंगे। संत सुंदरमूर्ति कभी किसी से कोई वस्तु नहीं मांगते थे। प्रभु स्वयं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे।

एक बार एक व्यक्ति ने संत सुंदरमूर्ति को अपने घर पर आमंत्रित किया। उस व्यक्ति ने अपनी दो लड़कियां उन्हें अर्पित कर दीं। सुंदरमूर्ति ने अपने उदात्त व्यक्तित्व एवं चरित्र के कारण उन्हें अपनी कन्या मानकर स्वीकार कर लिया।

मद्रास के एक गांव में एक कन्या ने यह निश्चय कर लिया था कि किसी संत से ही विवाह करेगी या हमेशा के लिए अविवाहित रहेगी। एक दिन संत सुंदरमूर्ति उसी गांव में पहुंचे और उस कन्या से विवाह किया। शर्त यह थी कि उस गांव की सीमा से उन्हें बाहर नहीं जाना है। लेकिन संत सुंदरमूर्ति एक दिन किसी कारण गांव से बाहर चले गए। नतीजतन वह अंधे हो गए और उन्हें अन्य कई तरह के कष्ट भी झेलने पड़े। तब उन्होंने भगवान की भक्ति की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। भगवान संत सुंदरमूर्ति की भक्ति से प्रसन्न हुए और उनकी दोनों आंखों में पुन रोशनी लौट आई। उन्होंने अपने जीवनकाल में लगभग अड़तीस हजार पद लिखे।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 22 जनवरी, 1961

चीन के कारखानों में अच्छे माल का उत्पादन नहीं हो रहा

चीन के कारखानों में अच्छे माल का उत्पादन नहीं हो रहा

कम्युनिस्ट पार्टी ने समेकन किया

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक प्रस्ताव में यह स्वीकार किया है कि देश में भारी उद्योगों में बनने वाला माल अच्छा नहीं बन रहा। उन्होंने आगे कहा कि इन कारखानों के उत्पादन के स्तर में सुधार करना जरूरी है।

अश्लील वीडियो और कठघरे में नैतिकता

जब भी कोई दुष्कर्म का मामला सुर्खियों में आता है, कुछ लोग उससे जुड़े तथाकथित वीडियो इंटरनेट पर खोजने में जुट जाते हैं।

मुकुल श्रीवास्तव — मुद्दा

इस बदलते दौर में तकनीक ने हमारे जीवन को कई तरह से आसान बनाया है, पर इसके साथ ही मानवीय संवेदनाओं पर गहरे घाव भी किए हैं। जैसे-जैसे तकनीकी प्रगति हो रही है, हमारे समाज में संवेदनहीनता, हिंसा और आपराधिक गतिविधियों का एक नया चेहरा उभर रहा है। अब अपराधियों के पास डिजिटल तकनीक के रूप में एक ऐसा हथियार है, जिसे वे अपनी घिनौनी मंशाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तकनीक की आड़ में अश्लील वीडियो खरीदने-बेचने का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है।

समाज का एक बड़ा तबका ऐसे वीडियो को इंटरनेट पर खोजते और देखते हुए इसे बढ़ावा दे रहा है। जब भी कोई दुष्कर्म का मामला सुर्खियों में आता है, कुछ लोग उससे जुड़े तथाकथित वीडियो इंटरनेट पर खोजने में जुट जाते हैं। पश्चिमा द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट इस घिनौनी प्रवृत्ति को उजागर करती है। हाल में हुई कोलकाता की एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या

और दुष्कर्म की खबरों के सुर्खियों में आने के बाद गूगल ट्रेंड्स पर पीड़िता के नाम से अश्लील वीडियो की खोज में वृद्धि देखी गई। इससे पहले जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स स्कैंडल मामले में भी ऐसा ही देखा गया था। ऐसे वीडियो देखने वाले पीड़िता के दर्द को महज मनोरंजन का साधन समझते हैं।

भारत में दुष्कर्म और असहमति से बनाए गए सेक्स वीडियो का बढ़ा कारोबार है। पहले ये वीडियो गोपनीय ढंग से सीडी और पेन ड्राइव के माध्यम से बेचे जाते थे। लेकिन इंटरनेट के आने के साथ यह काला कारोबार अब इन्क्रिप्टेड ऐप्स पर चला गया है, जहां इन वीडियो क्लिप्स को रोकना संभव नहीं है।

फैक्ट चैकिंग संस्था बूम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंस्टाग्राम से ये अपराधी लिंक के जरिये सामग्री को प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर ले जाते हैं, जहां से यह काला कारोबार होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोशल मीडिया साइट्स पर यदि आप ऐसे एक आपत्तिजनक पेज को फॉलो करते हैं, तो एल्गोरिदम और भी ऐसे अकाउंट आपको सुझाता है। लिंक के लिए यूपीआई, इंस्टेंट पे से भुगतान करने के बाद इच्छुक ग्राहक को टैराबॉक्स और क्लाउड एग्रीगेटर ऐप्स की ओर ले जाया जाता है। जहां वे इन अवैध और अमानवीय सामग्री तक पहुंच कर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार डाउनलोडिंग के बाद इसका पता लगाना या रोकना लगभग असंभव हो जाता है।

अमेरिकी गैर लाभकारी संस्था नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की रिपोर्ट कहती है कि भारत दुनिया में बाल यौन शोषण सामग्री का सबसे बड़ा निर्माता है। पॉक्सो ऐक्ट जैसे कठिन प्रावधानों और सजा के बाद भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर बाल यौन शोषण सामग्री भरी हुई है। यह व्यापार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी इसे रोकने में असमर्थ नजर आ रही हैं। इन चैनलों को बंद करना भी एक अस्थायी समाधान ही है, क्योंकि नए चैनल्स कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाते हैं। इस अनैतिक व्यापार ने न केवल कानून को चुनौती दी है, बल्कि समाज की नैतिकता और संवेदनशीलता को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। एआई जैसी तकनीक आने से अपराधियों के हौसले और बढ़ गए हैं, जहां तकनीक की मदद से सामान्य तस्वीर को फेक न्यूड तस्वीरों और डीपफेक वीडियो में बदला जा सकता है।

साल 2023 में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसी सामग्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके बाद यूट्यूब ने अपनी नई कम्युनिटी गाइडलाइंस के मुताबिक, अक्तूबर से दिसंबर के बीच करीब 25 लाख वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया था। वहीं, टेलीग्राम पर 'स्टॉप चाइल्ड अब्यूज' चैनल के डेटा के मुताबिक, इस साल अब तक करीब छह लाख 70 हजार चैनल्स को बैन किया जा चुका है। पॉर्नोग्राफी और इस तरह की यौन हिंसा के वीडियो देखने की आदत के बीच गहरा ताल्लुक है। मनोचिकित्सक मानते हैं कि ऐसी सामग्री देखने से व्यक्ति की यौन और हिंसा के प्रति सामान्य दृष्टि विकृत हो गई है। यौन शिक्षा की कमी वाले भारत जैसे देश में यह समस्या को और गंभीर बना देती है। मंकी इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, पॉर्न वीडियो देखने के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर आता है, जिनमें 18 से 24 साल के युवाओं की संख्या 24 प्रतिशत है।

जाहिर है, इस समस्या का समाधान हम सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि जागरूकता बढ़ाकर ही कर सकते हैं। हमें ऐसी सामग्री के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और समझना होगा कि ऐसे वीडियो पर हर क्लिक, हर शेयर किसी की जिंदगी को तबाह कर सकता है।

प्रगति की राह

भारत डोगरा

नया ट्विस्ट! खबर है कि आरएसएडब्ल्यू अफसर विकास यादव को तो दिल्ली पुलिस ने पन्नू की हत्या के साजिशकर्ता के रूप में अमेरिका द्वारा उनका नाम लिए जाने से हफ्तों पहले ही वसूली के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया था। हैरत! इसका उस समय किसी को पता भी न चला। न ही सरकार ने उस समय संसद में इस बाबत कोई जानकारी दी थी।
एम.के. वेणु, पत्रकार @mkvenu1

शांति और पर्यावरण रक्षा

यदि बेहतर समाज बनाने के इतिहास में जाएं तो सबसे पहले के और सबसे साहसी प्रयास गुलामी के विद्रोह के रूप में मिलते हैं। अति शक्तिशाली रोमन साम्राज्य तक को कभी-कभी इन गुलामी के विद्रोहों ने हिला दिया था, विशेषकर स्पार्टाकस के नेतृत्व में हुए बेहद प्रेरणादायक विद्रोह ने जिसे आज तक याद किया जाता है।

इसके बाद भी लंबे समय तक बेहतर समाज बनाने के प्रयासों को न्याय और समता के संदर्भ में समझा गया। यह समझ आज भी बहुत जरूरी है। समता और न्याय आज भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं जितने पहले थे। पर इसके साथ पर्यावरण की रक्षा तथा अमन, शांति के उद्देश्यों को जोड़ना भी बहुत जरूरी हो गया है। इस संदर्भ में प्रायः सवाल उठाया जाता है कि आर्थिक समता की मांग के साथ पर्यावरण संरक्षण की मांग का क्या संबंध है? व्यावहारिक स्तर पर कुछ आंदोलनों ने इन मांगों में समन्वय के प्रयास किए हैं। शहीद शंकर गुहा नियोगी ने मुख्य रूप से मजदूर आंदोलन चलाते हुए मजदूरों के स्वास्थ्य पर पैकिंग्स के प्रदूषण के दुष्परिणाम को पर्याप्त महत्त्व तो दिया ही, साथ ही जल प्रदूषण द्वारा आसपास के गांवों की तबाही, बड़े बांध के स्थान पर छोटी सिंचाई परियोजनाओं की सार्थकता और प्राकृतिक वनों के स्थान पर प्लांटेशन के नुकसान जैसे विषयों को भी अपने आंदोलन में स्थान दिया। समता के आंदोलन का भारतीय संदर्भ में मुख्य लक्ष्य यह है कि सब लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हों किंतु साथ ही यह याद रखना भी जरूरी है कि आर्थिक दृष्टि से बहुत से कमजोर लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति के विभिन्न रूपों पर आश्रित हैं। वनों से तरह-तरह के फल और अन्य खाद्य पदार्थ तथा औषधि प्राप्त करते हैं, नदियों से दैनिक जीवन के लिए पानी प्राप्त करने के अतिरिक्त मछलियां प्राप्त करते हैं।

बस्तर के एक वन के बारे में मध्य प्रदेश आदिवासी कल्याण विभाग ने जो अध्ययन किया उसके अनुसार आदिवासी इस वन से अपने भोजन के लिए 22 तरह के फल, 8 तरह के फूल, 14 तरह के पत्ते, 21 तरह के कंद और 11 किस्म के बीज प्राप्त करते हैं। इस तरह के वन बचाना पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है तो उस कमजोर आर्थिक वर्ग की कुछ बुनियादी जरूरतों की निश्चित स्थाई आपूर्ति के लिए भी इस तरह के प्राकृतिक वन को बचाना उतना ही जरूरी है।

सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय के सैकड़ों गांवों में यात्रा कर यहां के लिए उपयुक्त नीतियों की तलाश की और जब योजना आयोग को इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर एक दस्तावेज तैयार करना था तो उसने सुंदरलाल जी को ही विशेषज्ञ के तौर

पर आमंत्रित किया। उस समय उन्होंने इस लेखक को बताया था, टिकाऊ और स्थाई अर्थव्यवस्था और कहीं से नहीं मिलेगी, यह पर्यावरण बचाने से ही मिलेगी।' पिछले अनुभव से यही पता चला है कि यदि हम पहले वनों को उजड़ने दें, भूमि को बंजर होने दें, नदियों को प्रदूषित होने दें तथा भूजल को बहुत नीचे जाने दें तो बाद में बुनियादी जरूरतों को उपलब्ध कराना बहुत कठिन और महंगा सिद्ध होता है। यह पूछना भी जरूरी है कि क्या स्वच्छ हवा में सांस लेना भी बुनियादी जरूरत नहीं है?

लोगों की जरूरतों को पूरा करने और पर्यावरण का संरक्षण करने का रास्ता एक ही है। जब लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी तभी वे पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में जुट सकेंगे, दूसरी ओर जब जमीन, जल और जंगल को बचाया जाएगा, तभी लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकेंगी। जमीन और जंगल जिन लोगों की स्थाई आजीविका का आधार बनेंगे, वे ही सबसे पहले उनकी रक्षा के लिए जी-जान लगाएंगे। आर्थिक समानता के आंदोलन का जैसे पर्यावरण के आंदोलन से नजदीकी रिश्ता है, वैसे ही विश्व शांति के आंदोलन से भी गहरा संबंध है। आधुनिक शस्त्र इतने विनाशक हो गए हैं कि जहां-जहां इनका उपयोग युद्ध या आंतरिक कलह में होता है, वहां की अर्थव्यवस्था बुरी तरह उजड़ जाती है, और बड़ी संख्या में लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित होते हैं। इराक, अफगानिस्तान, सूडान, आदि ऐसे कितने ही देश हैं जहां कुछ दशकों में युद्ध के कारण और उससे उत्पन्न अभावों से लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। युद्ध और गृह युद्ध के कारण खेत, उद्योग, अस्पताल, सरकारी कार्यालय सब उजड़ सकते हैं और इसका सीधा असर खाद्यान्न, दवाओं, चिकित्सा सुविधाओं, पीने के साफ पानी, वस्त्र, आवास के अभाव आदि के रूप में दिखाई देता है। अनेक युद्धों के मूल में किसी दूसरे देश या क्षेत्र के संसाधनों को हड़पने की प्रवृत्ति होती है। अतः विश्व शांति का आंदोलन जब युद्ध का विरोध करता है, तो वह साथ ही उन संसाधनों की रक्षा भी करता है, जिनके आधार पर स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं। युद्ध का तनाव बना रहने के कारण निरंतर नये हथियारों को प्राप्त करने की होड़ लगी रहती है, जिसे हथियार उद्योग अपनी ओर से उकसाता भी रहता है। यदि सैन्य खर्च को आधा किया जा सके तो निश्चय ही सब तरह की बुनियादी जरूरतों को उपलब्ध करने के लिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी।

विश्व शांति का आंदोलन धर्म, रंग, जाति के आधार पर हिंसा का भी विरोध करता है, और जैसा कि सब जानते हैं साम्प्रदायिक और जातीय हिंसा में सबसे अधिक चोट गरीब लोगों की रोजी-रोटी को ही पहुंचती है। यह आंदोलन हर तरह की तानाशाही का विरोध और लोकतंत्र का समर्थन करता है क्योंकि प्रायः तानाशाहियों में युद्ध की तरह अनेक वेगुनाह लोग मारे जाते हैं किंतु साथ ही तानाशाहियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और मनमानी के कारण अनेक लोगों को बुनियादी जरूरतों से वंचित होना पड़ता है तथा आर्थिक विषमता बढ़ती है। अतः लोकतंत्र के समर्थन हुए भी शांति आंदोलन समता के आंदोलन के लिए सहायक सिद्ध होता है। यह संबंध भी एकतरफा नहीं है क्योंकि जहां भी लोग बड़े स्तर पर जीवन की आवश्यकताओं से वंचित होते हैं, वहां तरह-तरह के वैमनस्य और हिंसा की आशंका बढ़ती है। अफ्रीका के कुछ देशों में जिस बड़े स्तर की हिंसा को जातीय हिंसा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसके मूल में वास्तव में अमीर देशों की कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई व्यापक आर्थिक तबाही है, जिसने भूख और अभाव से पीड़ित लोगों के बीच आपसी हिंसा को भयंकर रूप दिया है। समता का आंदोलन या सब लोगों की बुनियादी जरूरतों को जुटाने का प्रयास अनेक स्तरों पर अन्य सार्थक आंदोलनों और प्रयासों से जुड़ा है, इस समझ के आधार पर इन सब प्रयासों को जोड़ते हुए और सामजवाद को एक अधिक व्यापक परिभाषा देते हुए अधिक से अधिक लोगों के दुख-दर्द दूर करने का मार्ग खोजा जा सकता है।

उधर की मौज और मीडिया

मीडिया

सुधीश पचौरी

दो फिल्मी सुपर स्टार एक विज्ञापन में 'तीखा लाल' यानी 'तीखी लाल मिर्च' बेचते रहते हैं। उनके फैन उनको घेर लेते हैं तो वे अपने फैनों को घुमा देते हैं और खुद लाल मिर्च वाला खाना खाने के लिए निकल जाते हैं। एक और सुपर स्टार हर दिन एक न एक खास ब्रांड के मसाले बेचता रहता है। मसालों के साथ वे तेल, घी और आटे, दाल तक बेचते रहते हैं। तेल और घी आदि की खूबियों को भी बताते चलते हैं।

इस मामले में इन दिनों सरसों के तेल व घी बेचने पर जोर बढ़ा है। एक विज्ञापन कहता है कि इसमें झांस है, दूसरा कहता है यह कोल्ड का तेल है, फिर असली घी के विज्ञापन आ जाते हैं। वे हमारे स्वाद व स्वास्थ्य की चिंता करते हुए भी कमाई करते हैं। सुबह-सुबह चाय, बिस्किट, नमकीन भी चाहिए ही, सो चाय की पत्ती, काफी या दूध तो चाहिए ही। इसके लिए मीडिया कई ब्रांड के दूध-दही आदि बेचता रहता है। एक ब्रांड तो अपने दूध, पनीर, मक्खन को 'टेस्ट ऑफ इंडिया' बताता है।

इस तरह मीडिया हमारी 'खाती-पीती मिडिल क्लासी जीवन शैली' को बनाए रखता है, और अपना भी पेट भरता रहता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वे 'ऐप' लीजिए। ऑनलाइन ऑर्डर दीजिए! 'खाइए, पीजिए, मौज कीजिए'। मसाले वाला खाना खाएंगे तो पेट में जलन होगी लेकिन चिंता न करें आप गैस दूर करने वाला ये पेय लीजिए और गैस गायब। गले में खिंच खिंच है तो ये गोली लो और खिंच खिंच दूर करो! मसालेदार खाने को पचाने में 'प्रॉब्लम' हो रही है; ऐसा मसालेदार खाओगे तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। लेकिन आप परेशान न हों। आप ये जड़ी-बूटी वाला पेय लीजिए। सब कुछ पच जाएगा और अगर आपको कब्ज सता रहा है तो ये ये गोलियां/पाचक पीजिए। कब्ज गायब हो जाएगा। आना-जाना है तो इस ब्रांड की, तेल कम खर्च करने वाली मोटरसाइकिल लीजिए। नहीं तो पूरे परिवार के लिए 'कार' लीजिए। कार क्या है आपका चलता-फिरता छोटा-मोटा 'मकान' है। ये कार तेजी से स्पीड पकड़ लेती है। ये ऊंची से ऊंची और रफ सड़क पर दौड़ लगाती है। आप छत पर शीशे वाली गाड़ी लीजिए, जिसकी छत खुल जाए, उसे लीजिए ताकि बच्चे उसे खोलकर आसमान में उड़ते परिंदों को देख सकें। कार में टीवी भी है, कंप्यूटर भी है, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा है। इन दिनों तो 'बुद्धिमान कार' भी है, जो समझ लेती है कि कहां, कैसे पार्क करें। उसमें 'जीपीएस' की सुविधा भी है जो आपको हर मोड़ पर बताती चलेगी कि इतने मीटर के बाद आपको दाईं ओर मुड़ना है कि आप अपनी मंजिल से इतनी दूरी पर है कि आगे 'जाम' है कि नहीं...जितनी हैसियत है उतनी कीमती वह कार है।

अगर छुट्टियां हैं, तो आप 'टूरिस्ट पैकेज' लें। इतने पैसे में इतने देशों की सैर कर सकते हैं, इतने दिन इस या उस 'रिसॉर्ट' में रह सकते हैं। हर 'रिसॉर्ट' को पांच सितारा स्वर्ग की तरह दिखाया जाता है। हर जगह स्विमिंग पूल दिखता है। हरा-भरा वातावरण दिखता है। काम करते-करते अपके सिर में दर्द हो गया है, तो उसका भी इलाज है। आप ये गोली लें, ये बाम लें और सिर दर्द दूर करें। अगर 'एनर्जी लॉस' हो रहा है तो ये ब्रांड का 'एनर्जी पेय' लें और 'जीओलेट' हो जाएं। सब करने के बाद आपके लिए 'पान मसाला' या चांदी के 'वर्क' वाली खूबसूरत इलायची है। यों पांच सितारा होटल भी हैं, लेकिन कानूनी मजबूरी है। शराब को मीडिया में नहीं बेच सकते। इसलिए भी इशारे से बेचते हैं। हम सोडे को शराब की तरह दिखाते हैं।

इन दिनों 'कृत्रिम बुद्धि' से लैस मशीनें' भी मीडिया में बिकती हैं। ये आपके हुकुम की गुलाम है। आप कहें कि 'एसी' चलाओ तो चला देंगी। 'एआई' यानी 'कृत्रिम बुद्धि' वाली घरेलू 'मशीन' से कहें कि ये 'एसी' चलाओ तो चला देगी। अगर कहें कि वो बाला गाना सुनाओ तो उस गाने को बजा देगी। अगर आप हैसियत न होने पर भी 'अच्छा इलाज' कराना चाहते हैं तो अपना 'बीमा' जरूर करा लें ताकि बीमार होने की स्थिति में आपकी 'सारी बचत' न निकल जाए...। बताइए, इतनी 'कैअर' करने वाला मीडिया कब था? वो तो चाहता है कि आप खूब खाएं, मौज करें। बीमार पड़ें तो परेशान न हों। बीमा के भारफल इलाज कराएं। शिक्षा के लिए बच्चे को विदेश पढ़ाना है तो लोन लीजिए। मकान के लिए लोन लीजिए हैं! जिंदगी जीना सीखिए। नकद हो तो अच्छा। उधार हो तो और भी अच्छा! उधार का जीवन जिओ और मौज करो! लगता है कि गालिब का जमाना आ गया है: 'कर्ज की पीते थे मय, लेकिन समझते थे कि हां! रंग लाएगी हमारी फाकामस्ती एक रोज'!!

शिक्षा के लिए बच्चे को विदेश पढ़ाना है तो लोन लीजिए। मकान के लिए लोन लीजिए है! जिंदगी जीना सीखिए। नकद हो तो अच्छा। उधार हो तो और भी अच्छा! उधार का जीवन जिओ और मौज करो! लगता है कि गालिब का जमाना आ गया है: 'कर्ज की पीते थे मय, लेकिन समझते थे कि हां! रंग लाएगी हमारी फाकामस्ती एक रोज'!!

संकट के दौर में ब्रिक्स सम्मेलन

वैश्विकी

डॉ. दिलीप चौबे

ब्रिक्स आयोजन के समय दुनिया को किसी अनहोनी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। संभव है कि इसी दौरान इस्राइल ईरान को निशाना बनाएं यदि ऐसा होता है तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई करेगा। इस्राइल अपने बलबूते ईरान की चुनौती का सामना करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अमेरिका सैनिक मदद के लिए संघर्ष में सीधे रूप से शामिल हो सकता है

रूस की मेजबानी में आयोजित होने वाला ब्रिक्स सम्मेलन कई अर्थों में ऐतिहासिक है। यदि ब्रिक्स नेताओं ने राजनीतिक सूझबूझ और साहस का परिचय दिया तो यह सम्मेलन नहीं विश्व व्यवस्था के निर्माण की शुरुआत बन सकता है। संगठन के मूल पांच सदस्य देशों के साथ इस बार विस्तारित ब्रिक्स के अन्य देश भी इसमें शिरकत करेंगे। दुनिया के अनेक देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। यह मौजूदा देश के लिए यह एक अवसर और चुनौती है। सामान्य सोच यह है कि जितने अधिक देश होंगे संगठन उतना ही प्रतिनिधिमूलक और प्रभावशाली होगा, लेकिन सर्वसम्मति या मतैक्य से चलने वाली संगठन में निर्णय प्रक्रिया की समस्या पैदा हो सकती है। विशेषकर ऐसे समय जब विभिन्न देशों के अलग-अलग राजनीतिक हित हैं। उदाहरण के लिए सैन्य संगठन नाटो का सदस्य देश तुर्की ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। रूस और चीन नाटो को यूरोप और पूर्व एशिया में चुनौती दे रहे हैं। ऐसे समय ब्रिक्स में तुर्की का शामिल होना नाटो के एक 'भेदया का जोखिम' उठाना है। पश्चिम एशिया में ईरान और सऊदी अरब के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी एक बड़ा सिरदर्द है। आने वाले दिनों में यदि इस्राइल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो इस क्षेत्र में नई लामबंदी शुरू हो जाएगी। ब्रिक्स इन देशों के परस्पर विरोधी हितों में कैसे सामंजस्य स्थापित करता है यह अन्य देशों के नेताओं की राजनीतिक सूझ-बूझ की परीक्षा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रूस यात्रा पर भी सबकी नजर रहेगी। तीन महीने के दौरान मोदी दूसरी बार रूस यात्रा पर जा रहे हैं। इस अवधि में काफी कुछ बदल गया है। कनाडा और अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में तनाव पैदा हुआ है। कनाडा के साथ तो टकराव की स्थिति है। वहीं खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की मोहरा बनाकर अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है। लगता है मोदी सरकार उसके निशाने पर है। कुछ राजनीतिक समीक्षा का आशयर्य व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर अमेरिका मोदी सरकार की क्यों अस्थिर करना चाहता है जबकि यह सरकार भारत में अब तक की सबसे अधिक अमेरिकी अनुकूल सरकार है। इन समीक्षकों का यह भी मानना है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी विरोधी प्रलाप के पीछे भी अमेरिका है। ट्रूडो को यह खुशफहमी है कि वह कनाडा एक बड़ा शक्तिशाली देश है। हकीकत यह है कि कनाडा हर महीने में अमेरिका का पिछलग्गू देश है। 'फाइव आईज' के अन्य देशों ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर भी वही बात लागू होती है। हाल के घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट हो गया है कि जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी अमेरिकी कुनबे के सक्रिय सदस्य बन गए हैं। इसे यूरोप और पश्चिम एशिया में तनाव के नये हालात बन गए हैं।

हाल में ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि उत्तर कोरिया के दस हजार से अधिक सैनिक यूक्रेन में रूस की ओर से मोर्चा संभालने वाले हैं। यदि उत्तर कोरिया रूस की मदद करने के लिए अपने सैनिक भेज रहा है तो यह भी स्वाभाविक है कि उसे रूस की ओर से यह आश्वासन मिला होगा कि दक्षिण कोरिया और जापान से संभावित संघर्ष में उसे रूस की मदद मिलेगी। इससे पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा हालात खतरनाक हद तक बिगड़ जाएंगे। भारत के लिए भी यह एक चुनौती होगी कि वह क्वॉड में अपनी भूमिका पर गौर करे। कजान (रूस) में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच यदि शिखर वार्ता होती है तो उसे पता चलेगा कि भारत अमेरिका और रूस के साथ अपने संबंधों में कैसे संतुलन बनता है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए चीन के साथ अपने संबंधों को पटरी पर लाने का एक अवसर है।

ब्रिक्स आयोजन के समय दुनिया को किसी अनहोनी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। संभव है कि इसी दौरान इस्राइल ईरान को निशाना बनाएं यदि ऐसा होता है तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई करेगा। इस्राइल अपने बलबूते ईरान की चुनौती का सामना करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अमेरिका सैनिक मदद के लिए संघर्ष में सीधे रूप से शामिल हो सकता है। चुनाव में लड़खड़ा रही डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस के लिए यह फायदे का सौदा हो सकता है। यह बात दूसरी बात है कि दुनिया में भारी तबाही का कारण बन सकता है?

क्या प्रतीक बदले तो न्याय मिलेगा?

न्यायपालिका

के. विक्रम राव

अचरज होता है कि भारत के न्यायतंत्र के आधुनिकीकरण पर! वर्ना जब अमेरिका जन्मा नहीं था, ब्रिटिश जनता बल्कल वस्त्र पहनती थी, मिस्र, यूनान और चीन अभी पिछड़े ही थे तब भारत में मनु, याग्यवल्क्य, कात्यायन, बृहस्पति आदि प्रचुरता में न्यायिक ग्रंथ लिख गए थे। मगर अब अमृतकाल में प्रधान न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ को इल्हाम हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीकों का आधुनिकीकरण होना चाहिए। न्यायशास्त्र का अध्ययन करते समय मुझे भी अचरज ही होता था कि पुरातन अध्ययन के आधुनिकीकरण का मुहूर्त कब आएगा? कानून के सामने सभी समान हैं, यह तो ध्रुव सत्य है। इसीलिए हैरानी होती है कि समतामूलक भारत को इतना अरसा क्यों हुआ इसे लागू करने में। गोस्वामी तुलसीदास सदियों पूर्व लिख गए, 'समरथ को नहीं दोष गोसाईं।' क्लेशदायी बात यह रही कि भारतीय महाद्वीप में नाइंसाफी पनपती रही। लोग डॉ. अंबेडकर की बड़ी श्लाघा करते हैं। तो क्या इस दलित पुरोधा ने संविधान में सबर्णों के साथ धोखा नहीं किया? अविभाजित भारतीय उपमहाद्वीप के राजनेता और स्वाधीनता-सेनानी लीग अध्यक्षों विधिवेत्ता ही रहे। राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना आदि। मगर इन सभी ने बिखरे समाज की ही पनपाया। नेहरू तो अत्यधिक पक्षपाती रहे। मुसलमानों के। मुसलमानों की अनगिनत स्त्री-सुख निर्बाध मिले। हिन्दू के साथ तो अर्धांगिनी एकल ही!! अंततः नरेन्द्र मोदी ने एक नर का नारी वाला युगल कराया। विधिवादी दार्शनिक गुआन झोंग (720-645 ईसा पूर्व) ने घोषणा की, 'राजा और उसकी प्रजा चाहे कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों न हो, कानून का पालन करना महान व्यवस्था होगी'। बाइबल कहती है 'तुम और परदेशी प्रभु के सामने एक समान होंगे: तुम पर और तुम्हारे बीच रहने वाले परदेशी पर एक ही नियम लागू होंगे'।

अमेरिका के नेब्रास्का राज्य ने 1867 में 'कानून के समक्ष समानता' का आदर्श वाक्य अपनाया। इस आदर्श वाक्य को नेब्रास्का में अश्वेतों और महिलाओं के लिए राजनीतिक-नागरिक अधिकारों का प्रतीक बनाने के लिए चुना गया था, विशेष रूप से नेब्रास्का की गुलामी की अस्वीकृति। दक्षिण अफ्रीकी स्वतंत्रता चार्टर 1955 में अपनाया गया जिसमें कहा गया, 'कानून के समक्ष सभी समान होंगे!' याद रहे मिस्र ने विश्व न्यायतंत्र को तराजू दिया। यह न्याय व संतुलन का प्रतीक है। यूनानी सभ्यता से न्याय की देवी यूरोप और अमेरिका पहुंची। इसे भारत ब्रिटेन के एक अफसर लेकर आए। 17वीं सदी में ब्रिटिश काल में 18वीं शताब्दी के दौरान न्याय की देवी की मूर्ति का सार्वजनिक इस्तेमाल किया जाने लगा। भारत की आजादी के बाद न्याय की देवी को उसके प्रतीकों के साथ भारतीय लोकतंत्र में स्वीकार किया गया।

अलग-अलग देशों में न्याय की देवी अलग-अलग रूपों में देखने को मिलती है। लेडी जस्टिस की मूर्ति आम तौर पर खड़ी या बैठी हुई महिला के रूप में होती है। आम तौर पर नंगे पैर होती है और उसके बाल या तो उसके कंधों तक लटकते हुए होते हैं या फिर बंधे होते हैं। कहीं-कहीं बाल सिर के चारों ओर फैले हुए होते हैं। वह एक हाथ में तराजू और दूसरे में तलवार रखती है। आम तौर पर तराजू बाएं हाथ में और तलवार दाएं हाथ में होती है। करीब सभी जगह उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। फिलहाल हर परिवर्तन केवल प्रतीकात्मक होता है। जब तक मानव न्यायप्रिय नहीं बनता समाज अत्याचारी रहेगा, क्योंकि समाज का आधार ही शक्तिपूजा और निरंकुशता रहेगी।

रेलवे

प्रियंका सौरभ

बार-बार क्यों हो रही बे-पटरी

भारत का रेलवे बुनियादी ढांचा विशाल लेकिन पुराना है, जिससे विभिन्न कमियों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। हाल में सिग्नल की विफलता के कारण मैसूर-दरभंगा एक्सप्रेस चेन्नई के पास स्थिर मालगाड़ी से टकरा गई जिससे मजबूत सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश पड़ा। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आधुनिकीकरण की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। ट्रेन में सुरक्षित सफर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ट्रेन यात्रा करने वाले मंजिल तक सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं, कहीं ट्रेन हादसे का शिकार तो नहीं हो जाएगी।

दरअसल, भारतीय रेलवे से हर दिन एक लाख किमी. से अधिक फैले देशव्यापी ट्रेक नेटवर्क पर करीब ढाई करोड़ यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। 2019-20 के लिए एक सरकारी रेलवे सुरक्षा रिपोर्ट में पाया गया है कि 70 फीसद रेलवे दुर्घटनाओं के लिए उनका पटरी से उतरना जिम्मेदार था, जो पिछले वर्ष 68 फीसद से अधिक था। इसके बाद ट्रेन में आग लगने और टक्कर लगने के मामले आते हैं, जो कुल दुर्घटनाओं में क्रमशः 14 और आठ फीसद के लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट में 2019-20 के दौरान 33 यात्री ट्रेनों और सात मालगाड़ियों से संबंधित 40 पटरी से उतरने की घटनाएं गिनाई गईं। इनमें से 17 पटरी से उतरने की घटनाएं ट्रैक खराबियों के कारण हुईं जबकि नौ घटनाएं ट्रेनों, इंजन, कोच, वैगन में खराबी के कारण हुईं।

ट्रेनों का पटरी से उतरना रेलवे के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ट्रेन कई कारणों से पटरी से उतर सकती है। ट्रैक का रखरखाव खराब हो सकता है, कोच खराब हो सकते हैं, और गाड़ी चलाने में गलती हो सकती है। ट्रेन हादसे रोकने के लिए पटरियों का मरम्मत कार्य होते रहना बहुत जरूरी है। इन कमियों को दूर करने में 'कवच' प्रणाली की भूमिका अहम है, कवच प्रणाली लाल सिग्नल पार करने पर ट्रेनों को स्वचालित रूप से रोक देती है, जिससे खतरनाक टकराव को रोका जा सकता है। रेल मंत्रालय ने दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा मार्गों पर कवच लागू किया। परिणामस्वरूप घटनाओं में कमी आई। कवच पता लगाता है कि दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर हैं, और टक्कर रोकने के लिए स्वचालित रूप से ब्रेक लगाती हैं। परीक्षण के दौरान सिस्टम ने दुर्घटनाओं को टाल दिया दक्षिण-मध्य रेलवे नेटवर्क पर कवच सुनिश्चित करता है कि ट्रेन गति सीमा से अधिक न चलें। महत्त्वपूर्ण कार्यों को स्वचालित करके, कवच लोकोमोटिव पायलटों पर कार्यभार कम करता है, मानवीय त्रुटि कम करता है।

परीक्षणों से पता चला है कि कवच-संरक्षित ट्रेनों का उपयोग करने वाले पायलटों के बीच थकान संबंधी त्रुटियों में 50 की कमी आई है। कवच का एकीकरण कई बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का समाधान करते हुए अधिक डिजिटलीकृत और स्वचालित रेलवे प्रणाली की ओर बदलाव का संकेत देता है। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 में कवच को 34,000 किमी. के उच्च-घनत्व वाले मार्गों पर विस्तारित करने की परिकल्पना की गई है। इस प्रणाली को वार्षिक रेलवे पूंजीगत व्यय के 2 पर लागू किया जा सकता है, जो नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रभावी तरीका प्रदान करता है। 2024 के रेलवे बजट में 1,112.57 करोड़ आवंटित किए गए हैं, प्रमुख रेलवे गलियारों में कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली का विस्तार करने के लिए, ट्रेन स्थानों पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करके, कवच दुर्घटनाओं के मामले में त्वरित प्रतिक्रिया की सुविधा प्रदान करता है, जिससे सुरक्षा परिणामों में सुधार होता है।

ट्रेन के पटरी से उतरने की एक वजह नहीं, बल्कि कई हैं। सबसे मुख्य कारण रेलवे ट्रैक पर मैकेनिकल फॉल्ट यानी रेलवे ट्रैक पर लगने वाला उपकरण खराब हो जाने को माना जाता है। हादसे उस वक्त होते हैं, जब पटरियों पर दरार पड़ जाती हैं। ट्रेन के डिब्बों को बांध कर रखने वाले उपकरण का ढीला होना भी कारण हो सकता है। एक्सेल, जिस पर ट्रेन की बोगी रखी होती है, का टूटना भी ट्रेन के डिरेल होने की वजह हो सकता है। पहियों का घिस जाना भी ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह हो सकता है। गर्मी के मौसम में पटरियों के स्ट्रक्चर में कई बार बदलाव आ जाता है। ट्रेन को तेज स्पीड से मोड़ना या ब्रेक लगा देना भी ट्रेन के पटरी छोड़ने की वजह हो सकता है

ट्रेन के पटरी से उतरने की एक वजह नहीं, बल्कि कई हैं। सबसे मुख्य कारण रेलवे ट्रैक पर मैकेनिकल फॉल्ट यानी रेलवे ट्रैक पर लगने वाला उपकरण खराब हो जाने को माना जाता है। हादसे उस वक्त होते हैं, जब पटरियों पर दरार पड़ जाती हैं। ट्रेन के डिब्बों को बांध कर रखने वाले उपकरण का ढीला होना भी कारण हो सकता है। एक्सेल, जिस पर ट्रेन की बोगी रखी होती है, का टूटना भी ट्रेन के डिरेल होने की वजह हो सकता है। पहियों का घिस जाना भी ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह हो सकता है। गर्मी के मौसम में पटरियों के स्ट्रक्चर में कई बार बदलाव आ जाता है। ट्रेन को तेज स्पीड से मोड़ना या ब्रेक लगा देना भी ट्रेन के पटरी छोड़ने की वजह हो सकता है

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काज़मी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया कैम्पर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-परियापुर, पुलिस स्टेशन-बाइपुर, थानापुर, पटना से मुद्रित तथा पाटलीपुत्र, सहारा इण्डिया प्लिंट, मोरीन रोड क्रॉसिंग, पटना से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी ।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
वर्ष - 19, अंक 6456
आर.एन.आई. नं. -बीआईएनएआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

हमें गर्व है हम भारतीय हैं